राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 5 अंक 27

मूल्य ₹8.00, नई दिल्ली, बुधवार, 7 जुलाई, 2021

www.jagran.com

पृष्ठ 14



38 साल की मिताली महिला वनडे रैंकिंग में फिर शीर्ष पर

›› 12

जागरण विशेष

वैदिक ज्ञान से निकाली नाले की सफाई की तकनीक



पटियाला : नालों की सफाई के लिए बड़ी मशीनों का इस्तेमाल तो आम बात है, लेकिन जड़ी-बूटियों के घोल से गंदे पानी की सफाई नया प्रयोग है। इसके प्रारंभिक नतीजे उम्मीद जगाने वाले हैं। (पेज-10)

मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार आज, उत्तर प्रदेश व बिहार को मिलेगा बड़ा हिस्सा

अनुभव संग सधेंगे जातीय समीकरण

मुख्यमंत्री और राज्यों में मंत्री रह चुके नेताओं को मिलेगी प्राथमिकता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- 25 पर पहुंच सकती है ओबीसी मंत्रियों की संख्या, अभी हैं डेढ़ दर्जन
- केंद्र में बढ़ सकता है ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट का प्रतिनिधित्व
- शिक्षित व युवाओं को मिलेगाज्यादा मौका
- सर्बानंद सोनोवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट लगभग तय

कैबिनेट का गणित

81 मंत्री हो सकते हैं मंत्रिमंडल में

28 पद सरकार में अभी हैं खाली



सर्बानंद सोनोवाल



ज्योतिरादित्य सिंधिया



अनुप्रिया पटेल

मौजूदा 'ब्यूरोक्रेट' मंत्री : विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिजली मंत्री आरके सिंह और केंद्रीय शहरी विकास राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ऐसे मंत्री हैं, जो पहले ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहे हैं।

मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी कर ली है। इसमें सियासी समीकरण के लिहाज से जातीय और क्षेत्रीय संतुलन तो होगा ही, साथ ही युवा, अनुभवी, शिक्षित और ब्यूरोक्रेट-टेक्नोक्रेट भी पसंद में शामिल होंगे। यानी जातीय समीकरण के खांचे में भी पूर्व आइएएस, आइएफएस, इंजीनियर आदि कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। बताया जा रहा है कि संभवतः बुधवार शाम को कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। इस विस्तार के बाद केंद्र सरकार में दो दर्जन से ज्यादा मंत्री ओबीसी होंगे। युवाओं का भी प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, जिससे मंत्रिमंडल के सदस्यों की औसत आयु काफी कम हो जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट विस्तार का खाका तैयार हो गया है। उप्र व बिहार को बड़ा हिस्सा मिल सकता है। दरअसल उप्र में अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव है। दूसरी ओर, बिहार से सहयोगी दल जदयू को भी कैबिनेट में प्रतिनिधित्व देना है। इस विस्तार में अनुभव को सबसे ऊपर रखने की बात कही जा रही है। ऐसे में राज्यों में बतौर मुख्यमंत्री जिम्मेदारी संभाल चुके और राज्य सरकारों में लंबे समय तक मंत्री पद संभाल चुके नेता प्राथमिकता में हैं। कुछ पूर्व अफसर भी इसमें दिख सकते हैं। दरअसल, पीएम मोदी ऐसे लोगों को आगे लाना चाहते हैं, जो विकास कार्यों को तेज कर सकें। कुछ युवा चेहरे भी शामिल होंगे। मंत्रिमंडल में मुख्यतः शिक्षित लोगों को ही जगह मिलेगी। मोदी सरकार की योजनाओं व राजनीतिक दांव के केंद्र में अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी शुरू से रहे हैं। पूरे देश और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी का खासा प्रभाव है। ऐसे में ओबीसी मंत्रियों की संख्या 25 हो सकती है। फिलहाल कैबिनेट में डेढ़ दर्जन से कम ओबीसी मंत्री हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा।

केंद्रीय कैबिनेट में 81 मंत्री हो सकते हैं। वर्तमान में 28 पद खाली हैं। आधे दर्जन मंत्री ऐसे हैं जिनके पास दो से भी ज्यादा मंत्रालय हैं। एक दुर्घटना में घायल होने के बाद से आयुष मंत्री श्रीपद येस्सो नायक का मंत्रालय भी किसी और के पास है।

बताया जा रहा है कि उप्र से चार से पांच और बिहार से तीन मंत्री बनाए जा सकते हैं। उप्र में सहयोगी अपना दल से अनुप्रिया पटेल के साथ-साथ भाजपा कोटे से वरुण गांधी शामिल हो सकते हैं। उप्र के हर प्रमुख जातिसमूह से केंद्र में कोई न कोई प्रतिनिधि होगा। अन्य में सहयोगी दलों को भी शामिल किया जा सकता है। बिहार से जदयू के खाते से दो मंत्री बनाए जा सकते हैं। संभव है कि दोनों कैबिनेट दर्जे के हों। भाजपा के कोटे से भी एक मंत्री बनाया जा सकता है। लोजपा के खाते से रामविलास पासवान का निधन हो चुका है और अब पार्टी पर औपचारिक हक को लेकर जंग चल रही है। ऐसे में लोजपा से फिलहाल किसी को मंत्री बनाने पर सहमति नहीं है।

असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, कांग्रेस से भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया का आना तय है। कर्नाटक में भी 2023 में चुनाव हैं। वहां से किसी सांसद को मंत्री बनाया जा सकता है। बंगाल से पार्टी अध्यक्ष दिलीप घोष या उत्तर बंगाल से पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे मतुआ समुदाय के शांतनु ठाकुर को मंत्री बनाया जा सकता है। लद्दाख से सांसद जामयांग नामग्याल को भी केंद्र सरकार में लाने की संभावना है।

मंत्रिमंडल विस्तार से पहले राज्यपाल बनाए गए थावरचंद गहलोत

नई दिल्ली : मंत्रिमंडल विस्तार के पहले सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। साथ ही तीन अन्य नए राज्यपाल बनाए गए हैं। चार मौजूदा राज्यपालों को नए राज्यों में राजभवन की बागडोर सौंपी गई है। इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति,जनजाति, ओबीसी के साथ-साथ मुस्लिम समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। (पेज-3)

सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग मंत्रालय पेज››3

20 से 25 जुलाई के बीच जेईई मेन का तीसरा चरण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

इंतजार खत्म

- इंजीनियरिंग में दाखिले की प्रवेश परीक्षा का चौथा चरण 27 जुलाई से दो अगस्त के बीच आयोजित होगा
- तीसरे सत्र के लिए छह से आठ जुलाई तक और चौथे सत्र के लिए नौ से 12 जुलाई तक आवेदन करने का एक और मौका



इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए जेईई-मेन यानी संयुक्त प्रवेश परीक्षा-मुख्य के बाकी बचे दोनों चरणों के आयोजन की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को परीक्षा कार्यक्रमों का एलान किया। 20 से 25 जुलाई के बीच तीसरे और 27 जुलाई से दो अगस्त के बीच चौथे चरण का आयोजन होगा। पहले के दोनों चरणों के नतीजे अगस्त में घोषित हो सकते हैं।

निशंक ने छात्रों के हित में दो और बड़ी घोषणाएं कीं। पहला यदि कोई भी छात्र इन दोनों ही चरणों में शामिल होने के लिए किन्हीं कारणों से आवेदन नहीं कर पाया है तो उसे आवेदन का एक और मौका मिलेगा। इस दौरान वह तीसरे सत्र के लिए छह से आठ जुलाई को रात 11.50 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। चौथे सत्र की परीक्षा के लिए नौ से 12 जुलाई को रात 11.50 बजे तक आवेदन किया जा सकेगा। दूसरा बड़ा एलान यह कि छात्र सुविधा के मुताबिक परीक्षा केंद्र भी बदल सकेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा, कोशिश है कि छात्रों की मांग पर परीक्षा केंद्र मुहैया कराए जाएं। हालांकि इसके लिए उन्हें आवेदन की तय तारीखों पर ही आग्रह करना होगा। वहीं, एनटीए ने कहा है कि तीसरे चरण के लिए बीई-बीटेक व चौथे चरण के लिए बीआर्किटेक्चर-बी प्लानिंग के लिए छात्रों को अलग-अलग आवेदन करना होगा।

इस साल चार चरणों में जेईई मेन

कोरोना के मद्देनजर इस साल जेईई मेन को चार चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहला चरण फरवरी और दूसरा चरण मार्च में आयोजित किया गया था। अप्रैल में तीसरे व मई में चौथे चरण का आयोजन होना था, लेकिन कोरोना केस बढ़ने पर इन चरणों को टालना पड़ा था।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की वरिष्ठ निदेशक साधना पराशर ने बताया कि जिन शहरों में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। शहरों की संख्या 232 से बढ़ाकर 334 और परीक्षा केंद्रों की संख्या 660 से बढ़ाकर 828 कर दिया गया है।

न्यूज गैलरी

राजनीति ▶ पृष्ठ 4

सोनिया-कैप्टन मुलाकात में तय हुआ सुलह का फार्मूला

नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे में पार्टी के घमासान के समाधान के लिए हाईकमान के फार्मूले और फैसले को मानने का एलान कर दिया है। कैप्टन के एलान से पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू की बड़ी और नई भूमिका का रास्ता साफ हो गया है। हाईकमान ने यह भी साफ कर दिया कि पंजाब विधानसभा के चुनाव में अमरिंदर ही कांग्रेस के चुनावी कैप्टन रहेंगे।

राष्ट्रीय फलक ▶ पृष्ठ 5

जम्मू-कश्मीर में परिसीमन आयोग से नहीं मिलेगी पीडीपी

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए मंगलवार को परिसीमन आयोग जैसे ही श्रीनगर पहुंचा पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने उसकी वैधता पर सवाल उठाते हुए मुलाकात से ही मना कर दिया। पीडीपी ने कहा, परिसीमन प्रक्रिया का नतीजा पहले से तय है। यह एक दल विशेष के हितों के संरक्षण जबकि दूसरे वर्ग को राजनीतिक सियासी रूप से कमजोर बनाने के लिए हो रहा है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 7

आठ महीने बाद जीएसटी संग्रह लाख करोड़ रुपये से कम

नई दिल्ली : कोरोना की दूसरी लहर की वजह से जून का जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से कम रहा। यह गत आठ माह में सबसे कम संग्रह है। जून में जीएसटी का संग्रह 92,849 करोड़ रुपये रहा। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2021) में 3,36,987 करोड़ का जीएसटी संग्रह किया गया, जो कोरोना पूर्व के दो वित्त वर्षों की समान अवधि में हासिल रकम के मुकाबले अधिक है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 11

अफगानिस्तान में बंद नहीं होंगे भारत के मिशन

नई दिल्ली: अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती ताकत के बीच भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वह अफगानिस्तान में शांति व संपन्नता के लिए लगातार कोशिश करता रहेगा। साथ ही भारत ने इन बातों से भी इन्कार किया है कि वह काबुल, कंधार और मजार-ए-शरीफ स्थित मिशनों को बंद करने जा रहा है। हालांकि हालात को देखते हुए काबुल स्थित दूतावास या दूसरे वाणिज्य दूतावासों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या जरूर कम की जा सकती है।

'स्पष्ट निर्देश संग आए ट्विटर, नहीं तो बढ़ेंगी मुश्किलें'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, जब तक चाहे समय नहीं ले सकता ट्विटर
- ट्विटर ने माना, नहीं किया नए आइटी नियमों का अनुपालन

नए आइटी नियम लागू नहीं करने पर इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने दो टूक कहा कि अगली सुनवाई पर स्पष्ट जवाब लेकर आइए, वरना आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पीठ ने अंतरिम आधार पर स्थानीय शिकायत अधिकारी (आरजीओ) की नियुक्ति के मामले में अधूरी जानकारी देने पर भी आपत्ति जताई। उक्त आरजीओ ने 21 जून को इस्तीफा दे दिया है।

अधिवक्ता अमित आचार्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, ट्विटर ने केवल एक आरजीओ नियुक्त किया था। 31 मई को अदालत को दी गई जानकारी में यह नहीं बताया गया कि वह अधिकारी अंतरिम आधार पर था। जब आरजीओ ने 21 जून को इस्तीफा दे दिया तो फिर 15 दिनों में किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति क्यों नहीं की गई, जबकि पता था कि छह जुलाई को सुनवाई होनी है। अगर ट्विटर को लगता है कि वह जब तक चाहे समय ले सकता है तो यह भारत में नहीं होगा। अदालत इसकी कतई अनुमति नहीं देगी।

कोर्ट ने कहा, नए आइटी नियमों का करना होगा अनुपालन: केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सालिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा, नए आइटी नियम 25 फरवरी को लागू हुए थे। इसके अनुपालन के लिए तीन माह का समय दिया गया था, जो 25 मई को समाप्त हो गया। उन्होंने कहा, ट्विटर का भारत में व्यापार करने के लिए स्वागत है, लेकिन उसे यहां के नियमों का पालन करना होगा। इस पर पीठ ने कहा, हम पहले ही साफ कर चुके हैं कि ट्विटर को नए आइटी नियमों का अनुपालन करना होगा और अदालत उन्हें किसी तरह की सुरक्षा नहीं देने जा रही है।



ट्विटर ने स्वीकार किया, नहीं नियुक्त है कोई अधिकारी

पीठ की तख्त टिप्पणी के बाद ट्विटर के वकील साजन पुवैया ने स्वीकारा कि वर्तमान में माइक्रो ब्लागिंग साइट की ओर से कोई आरजीओ या नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है। पुवैया ने कहा, नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने स्वीकारा कि ट्विटर ने अब तक नए आइटी नियमों का पालन नहीं किया है। पुवैया ने कहा, यह सच है कि ट्विटर को नियमों का अनुपालन करना चाहिए और वह इसका पालन करेगा। उन्होंने मांग की कि इसके लिए उचित समय दिया जाए।

सैन फ्रांसिस्को और भारत के समय में अंतर का दिया हवाला : पीठ ने ट्विटर के अधिवक्ता को अधिकारियों से निर्देश लेने के लिए सुनवाई कुछ देर के लिए टाल दी। सुनवाई दोबारा शुरू होने पर अधिवक्ता साजन पुवैया ने कहा, सैन फ्रांसिस्को व भारत के समय में अंतर होने के कारण निर्देश नहीं लिए जा सके हैं। कुछ समय और दिया जाए। पीठ ने सुनवाई आठ जुलाई तक स्थगित करते हुए चेताया कि अगर स्पष्ट जवाब नहीं मिला तो ट्विटर की मुश्किलें बढ़ जाएंगी।

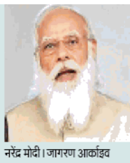
दलाई लामा को मोदी ने दी जन्मतिथि की शुभकामनाएं

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली



दलाई लामा। जागरण आर्काइव

- प्रधानमंत्री ने चीन को दिया तिब्बत नीति में बदलाव का संकेत
- अभी तक दलाई लामा से संवाद को सार्वजनिक करने से बचती रही है भारत सरकार



नरेंद्र मोदी। जागरण आर्काइव

भारत में पिछले छह दशकों से निर्वासित जीवन बिता रहे तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा की मंगलवार को 86वीं जन्मतिथि थी और पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें टेलीफोन कर लंबे जीवन की शुभकामनाएं दीं। चीन के साथ बेहद तनावपूर्ण रिश्ते को देखते हुए मोदी की तिब्बत के धार्मिक नेता से टेलीफोन वार्ता को बहुत ही अहम माना जा रहा है। भारत सरकार के दलाई लामा के साथ रिश्तों को लेकर चीन की भृकुटियां हमेशा से तनी रहती हैं और अभी तक मोदी बतौर प्रधानमंत्री चीन के रवैये का एक हद तक लिहाज भी कर रहे थे। दलाई लामा के उत्तराधिकारी के मुद्दे पर पहले से ही भारत व चीन में अंदरूनी तनातनी चल रही है।

मोदी ने दोपहर में ट्विटर पर बताया, 'मैंने दलाई लामा से उनकी 86वीं जन्मतिथि पर बात की और उन्हें लंबे व स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दीं।' इस संक्षिप्त संदेश को भारत की तिब्बत नीति में बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय पीएम की अभी तक दलाई लामा के साथ मुलाकात या टेलीफोन वार्ता को सार्वजनिक नहीं करने की परंपरा रही है।

पीएम का पद पहली बार संभालने के बाद मोदी ने वर्ष 2014 में दलाई लामा से मुलाकात की थी, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग का भारत दौरा होना था। संभवतः इसे देखते हुए दलाई लामा के साथ मुलाकात को ज्यादा प्रचारित नहीं किया गया था। यही नहीं, मोदी और चिनफिंग की वुहान में हुई पहली अनौपचारिक बैठक से पहले भारत सरकार ने अपने अधिकारियों को दलाई लामा के आधिकारिक सम्मेलन में हिस्सा लेने से भी रोका था। जाहिर है कि उन्होंने अब इस नीति से दूर होने का संकेत दे दिया है।

बंगाल विस से पारित हुआ विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव

कोलकाता : बंगाल में तीसरी बार सत्ता में आई ममता सरकार द्वारा राज्य विधान परिषद के गठन के लिए मंगलवार को पेश प्रस्ताव विधानसभा से पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत यह प्रस्ताव पेश किया। मुख्य विपक्षी भाजपा ने इसका विरोध किया। (पेज-4)

उमर गौतम के मदरसे की खोज में 30 से अधिक रडार पर

गाजियाबाद : मतांतरण के मुख्य सूत्रधार उमर गौतम के मदरसे की खोज में गाजियाबाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के रडार पर 30 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इन्हें नोटिस जारी करने के साथ ही विभाग एफआइआर भी दर्ज कराएगा। सुरक्षा एजेंसियों को अंदेशा है कि उमर का मसूरी इलाके में मदरसा है या फिर वह मदरसों को फंडिंग करता था। (पेज-5)

नहीं माने तो कोरोना प्रतिबंधों में ढील वापस ले लेंगे

नई दिल्ली, आइएएनएस: लाकडाउन और पाबंदियों में छूट मिलते ही हिल स्टेशनों पर उमड़े लोगों की तस्वीरों को सरकार ने भयावह करार दिया है। पर्यटन स्थलों के साथ ही बाजारों में कोरोना प्रोटोकाल की धज्जियां उड़ा रहे लोगों को चेतावनी देते हुए सरकार ने कहा कि यदि वे नियमों का पालन नहीं करते हैं तो कोरोना से संबंधित प्रतिबंधों में ढील वापस ले ली जाएगी।

देश में कमजोर पड़ती कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने प्रेस कान्फ्रेंस में कोरोना प्रोटोकाल के उल्लंघन संबंधी तस्वीरों को रेखांकित किया। संयुक्त स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने मनाली, शिमला, मसूरी समेत विभिन्न हिल स्टेशनों की तस्वीरों का हवाला देते हुए कहा, पर्यटन स्थल जाने वाले लोग कोरोना प्रोटोकाल का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मुंबई और दिल्ली के बाजारों में हाल में भीड़ की तस्वीरों का भी जिक्र किया।

अग्रवाल ने कहा, 'अगर प्रोटोकाल का पालन नहीं किया जाता है तो हम फिर से प्रतिबंधों में ढील को खत्म कर सकते हैं।' उन्होंने कहा, लाकडाउन और प्रतिबंधों को खत्म किए जाने के बाद लोग समझने लगे हैं कि महामारी खत्म हो गई है, लेकिन उन्हें समझना होगा कि दूसरी लहर अभी भी बनी हुई है और कुछ क्षेत्रों में सिमट गई है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के निदेशक बलराम भार्गव ने कहा, लोगों को कोरोना से बचाव के उचित व्यवहार का पालना करना चाहिए, अन्यथा अभी तक इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में हमने जो लाभ हासिल किया है उसे खो देंगे। शिमला और मनाली में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को पत्र भी भेजा है और इसे रोकने को कहा है।

चेतावनी

- सरकार ने लोगों को चेताया, कोरोना प्रोटोकाल का पालन करने पर दिया जोर
- शिमला और मसूरी समेत हिल स्टेशनों पर उमड़े लोगों की तस्वीरों को भयावह बताया



हिमाचल प्रदेश में हर दिन पर्यटकों का हुजूम उमड़ रहा है। मंगलवार को प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली में सैलानियों की भीड़। जागरण

73 जिलों में संक्रमण दर 10 फीसद से ज्यादा : लव अग्रवाल ने कहा, 17 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 73 जिलों में 29 जून से पांच जुलाई के बीच संक्रमण दर 10 फीसद से ज्यादा दर्ज की गई है। इनमें अरुणाचल प्रदेश के 18, राजस्थान के 10, मणिपुर के नौ, केरल के सात, मेघालय के छह, त्रिपुरा के चार जिले भी शामिल हैं। भार्गव ने कहा, देश के 65 जिलों में संक्रमण दर पांच से 10 और 595 जिलों में पांच फीसद से कम है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जांच की बहुत ही अहम भूमिका है। इन राज्यों में संक्रमण बढ़ रहा है।

चिंताजनक

सेंटर फार साइंस एंड एन्वायरमेंट की नई रिपोर्ट 'स्टेट आफ इंडियाज एन्वायरमेंट 2021 में भी सामने आई भयावह तस्वीर

पुराने कृषि कानूनों के भंवर जाल में फंसते रहे किसान

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

केंद्र सरकार के नए कृषि सुधार कानूनों के विरोध में महीनों से धरना-प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि पुराने कृषि कानून किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गए थे और इनमें बदलाव देश की जरूरत थी। सेंटर फार साइंस एंड एन्वायरमेंट (सीएसई) की नई रिपोर्ट 'स्टेट आफ इंडियाज एन्वायरमेंट 2021 में भी यह बात साफ हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, पुराने कृषि कानूनों के कारण किसान समस्याओं के जाल में फंसते जा रहे थे और साल दर साल आत्महत्या के मामले बढ़ रहे थे।

सीएसई ने 2017 से 2019 के बीच देशभर में आत्महत्या करने वाले किसानों और खेतिहर श्रमिकों पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक, 2019 में देशभर में 5,957 किसान आर्थिक संकट के कारण आत्महत्या के लिए मजबूर हुए। इस दौरान 4,324 खेतिहर श्रमिकों ने भी जान दी थी। रिपोर्ट दावा करती है कि देश में 28 किसान एवं कृषि खेतिहर श्रमिक प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। 2019 में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसानों की आत्महत्या के मामले सामने आए। 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खेतिहर श्रमिकों ने भी अपनी जीवन लीला खत्म कर ली, जबकि नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आत्महत्या के मामलों में साफ तौर पर वृद्धि देखने को मिली।

पांच गुना बढ़ा विरोध प्रदर्शन : सेंटर फार साइंस एंड एन्वायरमेंट की रिपोर्ट के अनुसार, 2017 में पांच राज्यों में किसानों के 34 बड़े विरोध-प्रदर्शन हुए थे। इसके दो साल बाद यानी 2019 में इन प्रदर्शनों का दायरा बढ़कर 22 राज्यों तक पहुंच गया। इसी तरह विरोध प्रदर्शन भी पांच गुना बढ़कर 165 हो गए। इनमें सर्वाधिक 96 प्रदर्शन आर्थिक कृषि नीतियों के विरोध में और 38 न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने को लेकर हुए।

सियासत में उलझे धरतीपुत्र

- 2019 में देशभर में 6,000 किसानों ने खत्म की जीवन लीला
- पुराने नियम बन गए थे किसान व खेतिहर श्रमिकों के लिए समस्या

दो वर्षों में सामने आए आत्महत्या के मामले

वर्ष	किसान	श्रमिक
2018	5,763	4,586
2019	5,957	4,324



इन राज्यों में बढ़े आत्महत्या के मामले : आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उप्र में किसानों की आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि देखी गई। वहीं, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा में कृषि श्रमिकों की खुदकुशी के केस ज्यादा मिले हैं।

इसमें शक नहीं है कि पुराने कृषि कानूनों में खामियां रही हैं। इसी वजह से किसानों व खेतिहर श्रमिकों की आत्महत्या की घटनाएं बढ़ी हैं। नए कृषि कानूनों में केंद्र सरकार ने विसंगतियों को दूर करने का दावा किया है। ऐसे में विरोध करने से पूर्व इनका गंभीरता से अध्ययन और इनकी व्यावहारिकता देखी जानी चाहिए।

-किरण पांडे, कार्यक्रम निदेशक, एन्वायरमेंट रिसर्च यूनिट, सीएसई

गोमती रिवरफ्रंट घोटाले में सात और ठिकानों पर सीबीआइ के छापे

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- एक चीफ इंजीनियर के घर मिली एक करोड़ रुपये की एफडी
- कई अफसरों व फर्म संचालकों के घर में हीरे व सोने के जेवर भी मिले

उत्तर प्रदेश में सपा शासनकाल में हुए गोमती रिवरफ्रंट घोटाले में सीबीआइ ने सात और ठिकानों पर छापे मारे हैं। मेरठ में प्रभात नगर स्थित अशोक वाटिका निवासी ठेकेदार हरपाल सिंह चौधरी के घर पर भी छानबीन की गई। सिंचाई विभाग से रिटायर हरपाल सिंह एक आइएएस अधिकारी के रिश्तेदार हैं। हरपाल सिंह ने गोमती रिवर फ्रंट के एक हिस्से में पौधारोपण कराया था। कुल 49 स्थानों पर की गई छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों का अध्ययन किया जा रहा है। जांच की आंच कई बड़ों तक पहुंच सकती है। सीबीआइ अधिकारियों को आशंका है कि यह सब केवल इंजीनियरों के बस का नहीं था। जांच आगे बढ़ी तो इसकी आंच पूर्व मंत्री व कई आइएएस अधिकारियों तक पहुंच सकती है।

सीबीआइ ने सोमवार को उप्र, राजस्थान के अलवर व बंगाल के कोलकाता स्थित 42 ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान कुछ आरोपितों के अन्य ठिकानों की भी जानकारी सामने आई और सीबीआइ ने सात अन्य स्थानों पर भी देर रात तक पड़ताल की। सीबीआइ लखनऊ के साथ गाजियाबाद, देहरादून, बिहार व दिल्ली के अफसरों की टीमें बनाकर यह छापे मारे गए थे। सीबीआइ को एक तत्कालीन चीफ इंजीनियर के घर से एक करोड़ रुपये की एफडी भी मिली है। कई अफसरों व फर्म संचालकों के घर में हीरे व सोने के जेवर भी मिले, जिनका ब्योरा दर्ज किया गया है।

जिस फर्म को चाहा काम दिलवा दिया पेज››5

कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों की मदद करना हमारा फर्ज : केजरीवाल

राहतकारी कदम ▶ मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत

पीड़ित परिवार को एकमुश्त राशि और प्रतिमाह भी आर्थिक मदद

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली



योजना शुरू करने की घोषणा करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सौजन्य-दिल्ली सरकार

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिये दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवार की मदद करना उनका फर्ज है। इस योजना के तहत ऐसे परिवारों को एकमुश्त 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी, मृतकों के आश्रित को हर माह 2500 रुपये दिए जाएंगे। अनाथ हुए बच्चों को 25 साल की उम्र तक हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि इस योजना के तहत आर्थिक मदद लेने के लिए लोगों को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन करना है। हालांकि, दिल्ली सरकार आवेदन का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि सरकार के प्रतिनिधि लोगों के घरों तक पहुंचेंगे। वे लोग आवेदन करने में पीड़ित परिवार की मदद करेंगे।

इसके साथ ही यदि ऐसे लोगों के पास किसी दस्तावेज की कमी है तो उसे बनवाकर समस्या का समाधान करेंगे, न कि दस्तावेज में कमी निकालेंगे। दस्तावेज में कमी निकालना पीड़ित परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा होगा। यही नहीं दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि ही उनके घर तक चेक पहुंचाएंगे।

इन्हें मिलेगी आर्थिक मदद

- कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- किसी परिवार में यदि कमाने वाले व्यक्ति की जान गई है तो हर माह एक निश्चित राशि दी जाएगी।
- कोरोना से माता-पिता को खोने वाले बच्चों को 25 साल की उम्र तक 25 सौ रुपये प्रतिमाह की मदद दी जाएगी। यदि किसी बच्चे के माता या पिता में से किसी एक का निधन पहले हो चुका है और दूसरे का निधन कोरोना से हुआ है तो ऐसे बच्चों को भी योजना का लाभ मिलेगा।
- कोरोना से जान गंवाने वाले के यदि बच्चे नहीं हैं, लेकिन माता-पिता जीवित हैं तो उन्हें आजीवन 2500 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। यह मदद वृद्धावस्था पेंशन से अलग होगी।
- अगर अविवाहित पुत्र या पुत्री की मृत्यु कोरोना से हुई है तो पिता या माता को जीवित रहने तक 2500 रुपये की प्रतिमाह आर्थिक मदद मिलती रहेगी।
- किसी के भाई या बहन की कोरोना से मृत्यु हुई है और उनके आश्रित शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर हैं तो उन्हें पूरी उम्र प्रतिमाह 2500 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी।

अभी नहीं हटेंगे दिल्ली सरकार के बनाए गए अस्थायी अस्पताल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: कोरोना मरीजों के लिए आपात स्थिति में बनाए गए दोनों अस्थायी अस्पताल अभी नहीं हटाए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने इन्हें छह माह तक बनाए रखने के आदेश दिए हैं। यह फैसला कोरोना की आशंकित तीसरी लहर को देखते हुए किया गया है। इन दोनों अस्पतालों में एक हजार बेड की व्यवस्था की गई है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आक्सीजन सुविधा वाले 500-500 बेड के ये दोनों अस्पताल बनाए गए थे। एक अस्पताल रामलीला मैदान और दूसरा अस्पताल जीटीबी एक्लेव में तैयार किया गया था। दोनों अस्पताल पूर्ण रूप से वातानुकूलित है। दूसरी लहर के दौरान आक्सीजन और आक्सीजन बेड दोनों की भारी कमी देखी गई।

दिल्ली में कोरोना से अब तक 25 हजार से अधिक लोगों की गई जान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: राजधानी में कोरोना की संक्रमण दर 0.11 फीसद से भी कम बनी हुई है। इसलिए, मौजूदा समय में कोरोना से राहत है। मंगलवार को दिल्ली में कोरोना के 79 नए मामले आए जबकि 154 मरीज ठीक हुए। इस वजह से सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 833 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से चार मरीजों की मौत हो गई। इस वजह से कोरोना का संक्रमण शुरू होने से लेकर अब तक 25 हजार से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है।

पहली लहर के मुकाबले इस साल 24 फरवरी के बाद दूसरी लहर में 29.25 फीसद मरीजों की मौत अधिक हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दिल्ली में कोरोना के अब तक कुल 14 लाख 34 हजार 687 मामले आए हैं। जिसमें से 14 लाख आठ हजार 851 मरीज ठीक हो गए हैं। इससे मरीजों के ठीक होने की दर 98.19 फीसद है। वहीं मृतकों की कुल संख्या 25,001 हो गई है।

दूसरी लहर के आंकड़े

अब तक आए मामले	7,96,314
ठीक हुए मरीज	7,82,522
मौतें	14,095
मृत्यु दर	1.77 फीसद
अभी सक्रिय मरीज	833

'हर बाजार में पुलिस, निगम व बाजार संगठनों की कार्रवाई समिति बने'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

कोरोना दिशानिर्देशों का पालन न होने पर दिल्ली के बाजारों पर चल रहे पुलिस व प्रशासन के चाबुक के बीच कारोबारी संगठनों ने दो टूक कहा है कि बाजारों में भीड़ को नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी व्यापारियों की नहीं है। यह जिम्मेदारी पुलिस, नगर निगम व प्रशासन को ही निभानी होगी। यह आम राय चैंबर आफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआइ) की महापंचायत से निकली, जिसमें दो सौ से अधिक बाजार संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। बता दें कि पिछले पांच दिनों में लक्ष्मी नगर मार्केट, गांधी नगर मार्केट की 12 दुकानें, नांगलोई में दो बाजार, व लाजपत नगर मध्य बाजार को बंद करने की कार्रवाई की गई, जिसके चलते व्यापारियों में चिंता का माहौल है। इसी मुद्दे पर विचार-विमर्श करने तथा आगे की कार्ययोजना बनाने के लिए व्यापारियों की वर्चुअल महापंचायत बुलाई गई थी।

महापंचायत में व्यापारियों ने कहा कि बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी व्यापारियों और बाजार संगठनों पर डाली जा रही है जबकि यह काम प्रशासन, पुलिस और नगर निगम का है। व्यापारी अपनी दुकान, गोदाम व आफिस के अंदर-बाहर तक तो कोरोना नियमों का पालन करा सकते हैं। सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ को नियंत्रित करने का अधिकार उनके पास नहीं है। सीटीआइ के महासचिव विष्णु भार्गव और रमेश आहूजा ने मांग की कि अगर किसी बाजार को नियमों के उल्लंघन होने के चलते बंद किया जाता है तो उस बाजार से संबंधित पुलिस, प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों को भी निलंबित किया जाना चाहिए। सीटीआइ के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी व्यापारियों और बाजार संगठनों पर डाली गई है, इसको वापस लिया जाए।

आज से खुलेगी लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट

नई दिल्ली, जासं : कोरोना दिशानिर्देशों का पालन न करने पर जिला प्रशासन की ओर से सोमवार से बंद की गई लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट बुधवार से खुल जाएगी। मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ हुई मीटिंग के बाद जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि उन्होंने कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया जिसके बाद जिला प्रशासन ने बाजार खोलने की मौखिक अनुमति दी है। लिखित आदेश बुधवार सुबह तक जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना नियमों का उल्लंघन पाए जाने के बाद मार्केट को अगले आदेश तक बंद करने के निर्देश जारी किए गए थे।

न्यूज गैलरी

राजधानी में बनेगा ई-कचरा प्रबंधन पार्क

नई दिल्ली : दिल्ली में जल्द ही ई-कचरा निस्तारण पार्क बनाया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक कचरे का निपटान वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुसार किया जाएगा। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मंगलवार को इसी मुद्दे पर मुख्य सचिव, पर्यावरण सचिव एवं दिल्ली राज्य औद्योगिक व ढांचागत विकास निगम के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। इसमें अधिकारियों से ई-कचरा निस्तारण इकाइयों की स्थापना के लिए कार्य योजना बनाने के लिए कहा है। (राब्यू)

गांधी परिवार की याचिका पर सुनवाई टली

नई दिल्ली: आयकर मूल्यांकन को सेंट्रल सर्कल में स्थानांतरित करने के खिलाफ कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की याचिका पर सुनवाई टल गई। न्यायमूर्ति राजीव शकधर व न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने सुनवाई 20 जुलाई के लिए तब स्थगित कर दी, जब उन्हें सूचित किया गया कि सालिसिटर जनरल तुषार मेहता सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं हैं। आर्म डीलर संजय भंडारी के साथ लेन देन का आरोप लगने के आधार पर आयकर प्रमुख आयुक्त ने गांधी परिवार से जुड़े वर्ष 2018-19 के आयकर मूल्यांकन को केंद्रीय सर्कल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। गांधी परिवार ने इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। (जासं)

दिल्ली दंगा : सगे भाइयों की जमानत अर्जी खारिज

नई दिल्ली : दिल्ली दंगे के दौरान करावल नगर इलाके में एक युवक की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने मंगलवार को आरोपित आशीष कुमार और गौरव को जमानत देने से इन्कार कर दिया। आरोपित सगे भाई हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव के कोर्ट ने कहा कि आरोपित साथ में उस दंगाई भीड़ के पीछे नजर आ रहे हैं, जिसने डंडों से पीट-पीट कर युवक की हत्या कर दी थी। ऐसे में दोनों को जमानत नहीं दी जा सकती। गत वर्ष फरवरी में हुए दंगे में करावल नगर इलाके में युवक सुलेमान की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपित सगे भाई आशीष कुमार और गौरव ने जमानत के लिए तीसरी बार अर्जी लगाई थी। (जासं)

नियमों के उल्लंघन पर 66 डेयरियों को बंद करने का निर्देश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने मंगलवार पूर्वी दिल्ली के कोंडली और घरोली गांव में 66 डेयरियों को निर्धारित पर्यावरणीय दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर बंद करने का निर्देश दिया है। इन डेयरियों को बिना सहमति के संचालन, क्षेत्र के नालों में अपशिष्ट जल और गाय का गोबर डालने पर एक-एक लाख रुपये का पर्यावरण क्षति मुआवजा भी जमा करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), डीपीसीसी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने चार से सात जून के बीच कोंडली, घरोली गांवों और घरोली डेयरी फार्मों का संयुक्त निरीक्षण किया था। डीपीसीसी ने कहा कि डेयरियों को बंद करने का नोटिस जारी कर दिया गया है और 15 दिनों के भीतर सभी को एक-एक लाख रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा जमा करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

डीपीसीसी ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम को नियमित निरीक्षण करने के लिए भी लिखा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये डेयरियां दोबारा न शुरू हो जाएं और नई डेयरियों की स्थापना पर भी नजर रखी जा सके।

दिल्ली में महामारी में दर्द हरेंगे 12 हजार स्वास्थ्य स्वयंसेवक

संतोष कुमार सिंह, नई दिल्ली

कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मरीजों को अस्पतालों में बेड व आक्सीजन नहीं मिल रही थी। इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की कमी से मरीजों के इलाज में परेशानी हुई। सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और राजनीतिज्ञों द्वारा कई कोविड केयर सेंटर तो बना दिए गए, लेकिन वहां मरीजों का इलाज व देखभाल करने के लिए डाक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों का अभाव था। इससे कई कोविड केयर सेंटरों का उपयोग नहीं हो सका। इसे ध्यान में रखकर भाजपा ने बूथ स्तर पर स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैनात करने का फैसला किया है। पूरे देश में लगभग चार लाख और दिल्ली में 12 हजार के करीब स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैयार किए जा रहे हैं, जिससे कि कोरोना की तीसरी लहर आने पर स्वास्थ्य कर्मियों की कमी दूर की जा सके।

डा. अनिल गुप्ता होंगे प्रदेश प्रभारी : राष्ट्रीय व प्रदेश से लेकर बूथ स्तर पर स्वास्थ्य स्वयंसेवक काम करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए चार लोगों की टीम बनाई गई है। राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ, सीटी रवि व डी पुरंदेश्वरी के साथ ही हिमाचल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डा. राजीव बिंदल इस टीम में शामिल हैं। प्रत्येक राज्य में एक प्रमुख व चार सह प्रमुख होंगे। डा. अनिल गुप्ता को दिल्ली का प्रमुख बनाया गया है। डा. अनिल गोयल, सत्य नारायण गौतम, विनोद सहरावत व नीतू डबास सह प्रमुख होंगे।

प्रत्येक जिले व मंडल में होगी चार लोगों की टीम : प्रत्येक जिले व मंडल में चार लोगों की टीम बनाई जा रही है। एक प्रमुख व अन्य सह प्रमुख होंगे। इसी तरह से प्रत्येक शहरी केंद्र पर तीन लोगों की टीम तैयार की जाएगी। एक शहरी केंद्र में चार से पांच मतदान केंद्र होते हैं। जिला स्तरीय टीम का गठन हो गया है। जल्द ही मंडल व शहरी केंद्र की टीम बन जाएगी।

प्रत्येक टीम में डाक्टर व महिला अनिवार्य : प्रदेश से लेकर मंडल स्तरीय टीम में एक डाक्टर और एक महिला को अनिवार्य रूप से जगह मिलेगी। शहरी केंद्र की टीम में भी डाक्टर को रखने की कोशिश होगी। डाक्टर उपलब्ध नहीं होने पर किसी स्वास्थ्य कर्मी को रखा जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक टीम में एक आइटी क्षेत्र के कार्यकर्ता को शामिल किया जाएगा।

स्वास्थ्य स्वयं सेवकों को चार-चार घंटे का आनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी माह टीम गठन व प्रशिक्षण का काम पूरा कर लिया जाएगा।

आखिर दिल्ली सरकार को हमारे निर्देश की जरूरत क्यों है : हाई कोर्ट

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली

कोरोना महामारी के दौरान विदेश से आयात करके दान स्वरूप दिए गए चिकित्सा उपकरणों पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आइजीएसटी) पर छूट देने के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आखिर निर्णय लेने के लिए दिल्ली सरकार को अदालत के निर्देश की जरूरत क्यों है। न्यायमूर्ति राजीव शकधर व न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने कहा कि जब हरियाणा और गुजरात सरकार ने निर्णय लिया तो फिर दिल्ली सरकार भी ऐसा कर सकती है।

पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अनुज अग्रवाल ने कहा कि अदालत हमें निर्देशित करे। इस पर पीठ ने कहा कि अदालत से दिल्ली सरकार को निर्देश लेने का तर्क बिल्कुल समझ नहीं आता है। हालांकि, अदालत का रुख देखते हुए अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें एक सप्ताह का मौका दिया जाए, ताकि इस पर निर्णय ले सकें। इसके बाद पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 14 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

▶ कहा, हरियाणा व गुजरात चिकित्सा उपकरणों पर आइजीएसटी पर छूट पर ले चुके हैं निर्णय, ऐसा दिल्ली भी कर सकती है



दिल्ली हाई कोर्ट ने किया सवाल। फाइल फोटो

इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल एंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर ने अधिवक्ता अभिषेक ए रस्तोगी के माध्यम से याचिका दायर कर दान देने के लिए विदेश से मंगाए गए आक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर समेत अन्य चिकित्सा उपकरणों पर आइजीएसटी लगाने की अधिसूचना को चुनौती दी है। रस्तोगी ने कहा कि रिफंड करने के संबंध में गुजरात और हरियाणा सरकार ने अधिसूचना जारी की, जबकि दान किए गए उपकरणों का लाभ उठाने वाली दिल्ली सरकार ने कोई अधिसूचना जारी नहीं की। न ही इस संबंध में केंद्र सरकार ने ही कोई निर्देश जारी किया। उन्होंने पीठ को बताया कि कोरोना महामारी के दौरान आक्सीजन की कमी के दौरान याचिकाकर्ता ने अपने खर्च पर विभिन्न देशों से 208 आक्सीजन सिलेंडर और 208 रेगुलेटर मंगाए और इसके लिए पांच मई को नौ लाख 69 हजार 358 रुपये का आइजीएसटी का भुगतान किया गया। उक्त सिलेंडर और रेगुलेटर दिल्ली सरकार को दान स्वरूप दिए गए।

उन्होंने कहा कि तीन मई को जीएसटी काउंसिल की तरफ से आई अधिसूचना में कहा गया था कि राज्य सरकार या कोई अन्य इकाई दान स्वरूप चिकित्सा उपकरण आयात करती है तो उन्हें जीएसटी में छूट दी जाएगी, लेकिन इसे दिल्ली सरकार ने मान्यता नहीं दी।

उन्होंने दलील दी कि इसके बाद 31 मई को केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दान स्वरूप मंगाये गए चिकित्सा उपकरणों पर आइजीएसटी में छूट दी है, लेकिन इसमें तीन से 30 मई के बीच आयात किए गए, चिकित्सा उपकरणों पर राहत नहीं दी गई।

डीडीए ने रमेश पार्क के सामने यमुना खादर से हटाई 150 झुग्गियां

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यमुना खादर से अतिक्रमण हटाने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू कर दी है। मंगलवार को डीडीए ने रमेश पार्क के सामने यमुना खादर से करीब 150 झुग्गियों को हटाया। डीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि रिवर फ्रंट परियोजना की राह में अड़चन बन रहे हर तरह के अतिक्रमण को हटाया जाएगा।

डीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि रमेश पार्क के सामने यमुना खादर में काफी दिन पहले झुग्गी में रहने वालों को नोटिस दे दिया गया था ताकि लोग खुद ही खादर को छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाएं, लेकिन खादर में रहने वाले लोग नोटिस के बावजूद कहीं नहीं गए। डीडीए ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की प्रिंसिपल कमेटी से अनुमति लेकर अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू किया है। खादर से अतिक्रमण हटाने के बाद लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि वह दोबारा अतिक्रमण न करें। ऐसा करते पाए गए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने इसका विरोध भी किया। डीडीए ने पुलिस प्रशासन की देख-रेख में कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाने की मुहिम को चलाया।

▶ रिवर फ्रंट परियोजना की राह में अड़चनें हटाने की मुहिम

▶ झुग्गीवासियों को पहले ही अन्यत्र जाने का दिया गया था नोटिस



रमेश पार्क के पास यमुना खादर में डीडीए द्वारा तोड़ी गई झुग्गियां। जागरण

बिजली उपभोक्ताओं को स्थायी शुल्क वापस करे सरकार : आदेश गुप्ता

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : भाजपा ने दिल्ली सरकार पर कोरोना महामारी में व्यापारियों व अन्य बिजली उपभोक्ताओं की परेशानी को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि महामारी की वजह से कारोबारियों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, इसके बावजूद उनसे मनमाना बिजली बिल वसूला जा रहा है। उपभोक्ता राहत की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है।



आदेश गुप्ता। फाइल

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि स्थायी शुल्क के नाम पर उपभोक्ताओं से ज्यादा बिजली बिल वसूला जा रहा है। कोरोना महामारी व लाकडाउन की वजह से कई माह तक लोगों का कारोबार बंद रहा। इसके बावजूद उनसे बिजली का स्थायी शुल्क लिया जा रहा है। दिल्ली सरकार निजी बिजली वितरण कंपनियों को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है।

विदेश में युवक से शादी कर, भारत में समलैंगिक विवाह की मांगी मंजूरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

विदेश में जाकर युवक से शादी करने वाले भारतीय मूल के नागरिक ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) के तहत समलैंगिक विवाह करने की इजाजत की मांग की है। समलैंगिक विवाह को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। साथ ही मुख्य पीठ ने मामले से जुड़ी कुछ अन्य याचिकाओं को भी इसी के साथ सूचीबद्ध कर दिया।

अधिवक्ता करुणा नंदी के माध्यम से जायदीप सेनगुप्ता और अमेरिकी नागरिक रसल ब्लेन स्टेफेन्स ने याचिका दायर की है। 20 साल से दोनों के बीच संबंध हैं। याचिकाकर्ता न्यूयार्क में वर्ष 2001 में मिले थे। अगस्त 2012 में उन्होंने समलैंगिक विवाह किया और पेरिस में रहते हैं। उन्हें अमेरिका, फ्रांस और कनाडा में विवाहित युगल के रूप में मान्यता भी मिली है। अब इसी माह उन्हें अपने पहले बच्चे के आने की उम्मीद है। ऐसे में जायदीप सेनगुप्ता ओवरसीज सिटीजनशिप आफ इंडिया (ओसीआइ) स्टेटस लेना चाहते हैं ताकि वह भारत में अपने परिवार के साथ समय बिता सकें। वीजा हासिल करने के लिए स्टेफेन्स की योग्यता की कानूनी जानकारी के लिए याचिकाकर्ताओं ने सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

▶ समलैंगिक विवाह की इजाजत की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस

याचियों के अधिवक्ता नंदी ने पीठ को बताया कि विदेशी विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम को भारतीय संविधान के तहत देखा जाए। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं की शादी को अमेरिकी कानून के तहत मान्यता दी गई है।

छह नए पाठ्यक्रम शुरू करेगा अंबेडकर विश्वविद्यालय

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: अंबेडकर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी। विवि प्रशासन ने बताया कि स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए 12 जुलाई से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी। विवि कटआफ जारी कर प्रवेश देगा। नए शैक्षणिक सत्र में विवि छह नए पाठ्यक्रम भी शुरू करेगा।

विवि कुलपति प्रो अनु सिंह ने बताया कि विवि बीए हिंदी (आनर्स), मास्टर्स आफ पब्लिक हेल्थ, एम वोक टूरिज्म एंड हास्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एमए इन आर्कियोलाजी एंड हेरिटेज मैनेजमेंट, एमए इन कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड हैरिटेज मैनेजमेंट और मानव पारिस्थितिकी में एकीकृत एमए-पीएचडी (आइपीएचडी) पाठ्यक्रम शुरू करेगा। विवि नई शिक्षा नीति के तहत मानव पारिस्थितिकी में एकीकृत एमए-पीएचडी कराएगा। अनु सिंह ने कहा कि चार वर्षीय बीए (आनर्स) राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम की शुरुआत भी इसी शैक्षणिक सत्र से होगी।

मुश्किल

जलकुंभी की सफाई न होने से थम रहा बहाव, डेंगू ने तोड़ा तीन साल का रिकार्ड, नदी में भारी मात्रा में कूड़ा, थर्माकोल व प्लास्टिक के नीचे पैदा हो रहे मच्छर

जलकुंभी से पटी यमुना, मच्छरजनित बीमारियों का बढ़ा खतरा

अरविंद कुमार द्विवेदी, नई दिल्ली

सफाई न होने के कारण यमुना नदी जलकुंभी से पटती जा रही है। यह जलकुंभी मच्छरों के लिए पनाहगाह बनी हुई है। इस कारण राजधानी में इस साल सामान्य की अपेक्षा करीब छह गुना मच्छर बढ़ गए हैं। इससे पिछले डेढ़ साल से कोरोना महामारी से कराह रही राजधानी में मच्छरजनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। इस साल जनवरी से लेकर जून तक राजधानी में डेंगू के 34, मलेरिया के 11 व चिकनगुनिया के छह मामले सामने आ चुके हैं। जबकि वर्ष- 2018 में इसी समयावधि में डेंगू के 30, वर्ष- 2019 में 22 और वर्ष- 2020 में 20 मामले दर्ज किए गए थे। यानी पिछले तीन साल की तुलना में इस साल डेंगू के मामले सबसे ज्यादा आए हैं। इसके बावजूद दिल्ली जल बोर्ड ने यमुना की सफाई को लेकर कोई कदम नहीं उठाया, इससे आने वाले समय में यह समस्या और बढ़ सकती है।



▶ पिछले तीन साल की तुलना में इस बार डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आए

कालिंदी कुंज बैराज पर जलकुंभी से पटी यमुना। विपिन शर्मा

सफाई न होने के कारण कालिंदी कुंज से लेकर पीछे करीब दो-तीन किलोमीटर तक यमुना नदी जलकुंभी से पट गई है। विशेषज्ञों के अनुसार, जलकुंभी के कारण पानी का बहाव थम जाता है। इस ठहरे हुए पानी में पालिथिन, थर्माकोल के नीचे मच्छरों को प्रजनन के लिए अनुकूल माहौल मिलता है। जलकुंभी की बनावट ऐसी होती है कि बारिश के दौरान इसके पत्तों में पानी भर जाता है, जिसमें मच्छर पैदा होते हैं।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ओर से कई विभागों के साथ की गई इंटरसेक्टोरल कोआर्डिनेशन मीटिंग में चिंता जताए जाने के बावजूद जल बोर्ड व अन्य विभागों ने जलकुंभी साफ करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

आज हाल यह है कि आइटीओ पुल, लोहे का पुल, कुदेसिया घाट, सराय कालखां से महारानी बाग, जोगाबाई व कालिंदी कुंज घाट तक यमुना जलकुंभी से पट गई है। इस कारण नदी के आसपास स्थित मदनपुर खादर, कालिंदी कुंज, जैतपुर, मोलड़बंद, सरिता विहार, जामिया नगर, अबुल फजल एनक्लेव, जसोला विहार, कंचन कुंज, शाहीन बाग, आली गांव, आली विहार आदि इलाकों में लोग मच्छरों से परेशान हैं।

निगम के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस बार राजधानी में क्यूलेक्स मच्छर अधिक हैं। इनसे जापानी इनसेफलाइटिस का भी खतरा हो सकता है। इनके काटने से त्वचा संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं। मादा क्यूलेक्स के काटने से एरोबावायरस इन्फेक्शन होता है। यह जापानी एनसेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार और फाइलेरियासिस जैसी बीमारी होती है।

डीयू में दाखिले के लिए 61 देशों के 1324 छात्रों ने किया आवेदन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। डीयू प्रशासन की मानें तो कोरोना की दूसरी लहर में 61 देशों के 1324 छात्रों ने आवेदन किया। यह आंकड़ा पहले के मुकाबले कम है। गत वर्ष 1700 से अधिक छात्रों ने आवेदन किया था।

डीयू दाखिला समिति के अध्यक्ष प्रो राजीव गुप्ता ने बताया नीदरलैंड, हंगरी, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया से भी छात्रों ने दाखिले के लिए आवेदन किया है। अफगानिस्तान से सर्वाधिक 320 छात्रों ने आवेदन किया है। डीयू ने विदेशी छात्रों के लिए शैक्षणिक सत्र 2021-22 में स्नातक-स्नातकोत्तर, एमफिल, पीएचडी, डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्सेज में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया अप्रैल में शुरू की थी। विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले की

▶ अफगानिस्तान, नेपाल के सर्वाधिक छात्र

▶ दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, हंगरी, आस्ट्रेलिया के छात्रों ने भी दिखाई दिलचस्पी

पाठ्यक्रम	आवेदन की अंतिम तिथि
स्नातकोत्तर	15 जुलाई
एमफिल-पीएचडी	30 जुलाई
एक वर्षीय सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम	22 अगस्त
एसओएल	29 अगस्त
पार्ट टाइम पाठ्यक्रम	22 अगस्त

अंतिम तिथि अलग-अलग है। स्नातक पाठ्यक्रम में आवेदन की अंतिम दिन 31 मई थी। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इसे 30 जून तक बढ़ा दिया गया था। डीयू में विदेशी छात्रों के दाखिले के लिए पांच फीसदी कोटा होता है।

65 फीसद यात्री क्षमता के साथ अब घरेलू उड़ानें संचालित होंगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बढ़ती मांग के मद्देनजर यात्री क्षमता को बढ़ाकर 50 से 65 फीसद कर दिया है।

मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कर्नाटक के राज्यपाल बनाए गए थावरचंद गहलोत

बदलाव ▶ चार नए राज्यपाल बने, चार को सौंपी गई नए राज्यों की जिम्मेदारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मंत्रिमंडल विस्तार के पहले केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। गहलोत के साथ ही तीन अन्य नए राज्यपाल बनाए गए हैं और चार मौजूदा राज्यपालों को नए राज्यों में राजभवन की बागडोर सौंपी गई है। राज्यपालों की नियुक्ति में मोदी सरकार में सामाजिक समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के साथ-साथ मुस्लिम समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है।

मध्य प्रदेश से आने वाले थावरचंद गहलोत अनुसूचित जाति से आने वाले भाजपा के कद्दावर नेता हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के रूप में उन्होंने दलित और पिछड़े वर्ग के लिए नीतियों को अमली जामा पहनाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके पहले कलराज मिश्र और नजमा हेपतुल्ला भी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहने के बाद राज्यपाल बनाए जा चुके हैं। गहलोत के अलावा आंध्र प्रदेश के भाजपा के पूर्व सांसद हरिबाबू कंभांपति को मिजोरम का, गुजरात के मंगूभाई छगनभाई पटेल को मध्य प्रदेश का और गोवा के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। इसके अलावा चार राज्यपालों को नए राज्यों में भेजा गया है। इनमें मिजोरम के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई को गोवा का, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का, त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस को झारखंड का और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है।



राज्यपाल नियुक्त किए गए (ऊपरी पंक्ति में बाएं से) थावरचंद गहलोत (कर्नाटक), बंडारू दत्तात्रेय (हरियाणा), सत्यदेव नारायण आर्य (त्रिपुरा) और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर (हिमाचल प्रदेश)। (नीचे की पंक्ति में बाएं से) मंगूभाई छगनभाई पटेल (मध्य प्रदेश), रमेश बैस (झारखंड), हरिबाबू कंभांपति (मिजोरम), पीएस श्रीधरन पिल्लई (गोवा)। एएनआइ

देश में मौजूदा राज्यपालों में समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी देखी जा सकती है। थावरचंद गहलोत और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के साथ अनुसूचित जाति से आने वाले राज्यपालों की संख्या चार हो गई है। इनके अलावा त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य और उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य अनुसूचित जाति से हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए मंगूभाई छगनभाई पटेल अनुसूचित जनजाति से आते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुइया उइके भी अनुसूचित जनजाति से हैं।

बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, झारखंड के रमेश बैस, हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय, सिक्किम के गंगा प्रसाद चौरसिया और तेलंगाना की तमिलसाई सौंदरराजन पिछड़े वर्ग से हैं। इसी तरह से भारत में पहली बार जाट समुदाय के तीन राज्यपाल हैं। इनमें बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, गुजरात के आचार्य देवव्रत और मेघालय के सत्यपाल मलिक शामिल हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान और मणिपुर के नजमा हेपतुल्ला के रूप में दो मुस्लिम बुद्धिजीवियों को इसमें जगह मिली है। राज्यपालों की सूची में हरिबाबू कंभांपति और बंडारू दत्तात्रेय तेलुगु का प्रतिनिधित्व करते हैं।

गुजरात की मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं मंगूभाई

> राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने मंगलवार को आठ राज्यपालों की नियुक्ति की है। इनमें चार को पहली बार राज्यपाल बनाया गया है, जबकि चार के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। आइए जानते हैं इनके बारे में...

मंगूभाई पटेल : दक्षिण गुजरात के नवसारी जिले से पांच बार विधायक और चार बार राज्य सरकार में मंत्री रहे मंगूभाई पटेल अल्पभाषी व मिलनसार व्यक्तित्व के हैं। गुजरात की तत्कालीन नरेंद्र मोदी सरकार में वन एवं पर्यावरण तथा अनुसूचित जनजाति विकास मंत्रालय का वर्षों तक पदभार संभालने वाले मंगूभाई की आदिवासी समुदाय में अच्छी पैठ है। गुजरात की राजनीति में उनकी छवि स्वच्छ व ईमानदार नेता की रही है।

थावरचंद गहलोत : शख्सीयत में विनम्रता और सख्ती का संतुलित समिश्रण है। मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गहलोत ने ग्रासिम इंडस्ट्रीज में मजदूरी भी की। इसी कंपनी श्रमिक संघ के कोषाध्यक्ष बने। भारतीय मजदूर संघ से जुड़े। कई श्रमिक आंदोलनों की अगुआई की। आपातकाल में जेल भी गए। 1996 से 2009 के बीच शाजापुर लोकसभा सीट से लगातार चुनाव जीतते रहे। 2012 व 2018 में राज्यसभा के लिए चुने गए। भाजपा महासचिव रहते हुए दिल्ली व कर्नाटक के प्रभारी बनाए गए। अरुण जेटली के निधन के बाद संसद के उच्च सदन का नेता बनाए गए।

हरिबाबू कंभांपति : आंध्र प्रदेश विवि में एसोसिएट प्रोफेसर रहे कंभापति 2014 में भाजपा के टिकट से सांसद चुने गए। वह आंध्र प्रदेश विस के भी सदस्य रहे। आंध्र प्रदेश के गठन के लिए आंदोलन में हिस्सा लिया। भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष रह चुके हैं। शिक्षा, स्वच्छ पेयजल और कौशल विकास के क्षेत्र में काम के जरिये लोकप्रियता हासिल की।

राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर : 2012-15 तक गोवा विधानसभा के स्पीकर रहे। अक्टूबर 2015 से 2017 तक वन पर्यावरण एवं पंचायती राज मंत्री का दायित्व संभाला। बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे अर्लेकर वर्ष 1980 के आसपास भाजपा में शामिल हुए। बतौर स्पीकर गोवा विधानसभा को देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बना चुके हैं।

पीएस श्रीधरन पिल्लई : आपातकाल में इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठाने वाले पिल्लई ने संगठन में खूब काम किया है। वह लेखक भी हैं। उनकी किताब का विमोचन पीएम मोदी कर चुके हैं। केरल से ताल्लुक रखने वाले पिल्लई भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कालेज के दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और महासचिव बनाए गए। वह भाजपा के लक्ष्यद्वीप प्रभारी भी रह चुके हैं।

सत्यदेव नारायण आर्य : मूल रूप से बिहार के रहने वाले सत्यदेव नारायण राजगीर विधानसभा सीट से आठ बार चुनाव जीत चुके हैं। बिहार सरकार में दो बार मंत्री रहे सत्यदेव राजगीर के पहले और नालंदा के दूसरे ऐसे शख्स हैं, जिन्हें राज्यपाल बनाया गया है। युवावस्था में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और बिहार की सियासत में अलग छवि बनाई।

रमेश बैस : पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके बैस रायपुर नगर निगम, मध्य प्रदेश विधानसभा व लोकसभा चुनावों में जीत का परचम फहरा चुके हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता विद्याचरण शुक्ल व श्यामाचरण शुक्ल जैसे नेताओं को हराया है। भाजपा के सामन्य कार्यकर्ता के रूप में राजनीति की शुरुआत करने वाले बैस कभी चुनाव नहीं हारे। दिवंगत भाजपा नेता सुषमा स्वराज बैस को अपना भाई मानती रहीं।

बंडारू दत्तात्रेय : युवावस्था में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने वाले दत्तात्रेय आपतकाल के दौरान जेल में भी रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी सरकार में मंत्री भी रहे। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री बनाए गए। चार बार सांसद रह चुके दत्तात्रेय मूल रूप से तेलंगाना के रहने वाले हैं। हैदराबाद स्थित उस्मानिया विवि से बीएससी की डिग्री लेने के बाद संघ प्रचारक बन गए। वर्ष 1980 में भाजपा की सदस्यता ली और आंध्र प्रदेश इकाई के सचिव बन गए। अगले ही साल पार्टी ने महासचिव बना दिया। दो बार आंध्र प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे और फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचे। (जेएनएन)

सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग मंत्रालय

नई दिल्ली, प्रेट्र : मोदी सरकार ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक नया मंत्रालय सृजित करने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल में बुधवार को बड़ा फेरबदल होने के बारे में चर्चा के बीच सरकारी सूत्रों ने कहा कि नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए सृजित किया जा रहा है।

सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। नए मंत्रालय के लिए एक प्रभारी मंत्री को बुधवार को नामित किया जाएगा। नया मंत्रालय सहकारिता को एक सच्चे, जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले जन आधारित आंदोलन में तब्दील करेगा। मंत्रालय सहकारिता के लिए कारोबार को आसान बनाने की खातिर प्रक्रिया को कारगर करेगा और बहु-राज्य सहकारिताओं के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।

ब्रिटिश सेना प्रमुख से मिले नरवणे, रक्षा सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा

लंदन, प्रेट्र : सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने ब्रिटेन के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल सर निकोलस कार्टर से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर विचार साझा किए। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग ने एक बयान में बताया कि जनरल नरवणे पांच जुलाई को ब्रिटेन की दो दिवसीय यात्रा पर पहुंचे। यूरोपीय देशों की अपनी यात्रा के तहत ब्रिटेन दौरे के दौरान नरवणे का देश के रक्षा मंत्री बेन वालेस और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर मार्क कार्लटन-स्मिथ से मुलाकात का भी कार्यक्रम है।

> ▶ जनरल सर कार्टर से की मुलाकात

इसके अलावा, भारतीय सेना के अतिरिक्त जनसूचना महानिदेशालय ने मंगलवार को ट्वीट किया, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल सर निकोलस कार्टर से बातचीत की और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर विचारों का आदान-प्रदान किया। इससे पहले जनरल नरवणे ने ब्रिटिश सेना द्वारा किए गए उनके स्वागत के तहत हॉर्स गार्ड्स परेड स्क्वायर पर ग्रेनेडियर गार्ड्स द्वारा दिए गए गॉर्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। जनरल नरवणे ब्रिटिश सेना की विभिन्न इकाइयों का दौरा करेंगे और परस्पर हितों के मुद्दों पर चर्चा करेंगे।



ब्रिटेन की यात्रा पर गए सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे (बाएं) ने वहां के सशस्त्र बलों के चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल सर निकोलस कार्टर से मुलाकात की। प्रेट्र

अपने यूरोप दौरे के दूसरे चरण में बुधवार और गुरुवार को जनरल नरवणे इटली की सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और चीफ ऑफ स्टाफ से महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। भारतीय सेना ने दौरे से पूर्व जारी किए गए एक बयान में कहा था कि सेना प्रमुख प्रसिद्ध शहर कैसिनो में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन करेंगे और उन्हें रोम में इतालवी सेना के काउंटर आईईडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा भी जानकारी दी जाएगी।

महाराष्ट्र में भाजपा विधायकों ने चलाई समानांतर विधानसभा

राज्य ब्यूरो, मुंबई

> ▶ विपक्षी दल ने अपने विधायकों को निलंबित करने का किया विरोध
>
> ▶ फड़नवीस बोले, हमने समानांतर विधानसभा के जरिये सरकार के चेहरे से पर्दा हटाया



मुंबई में मंगलवार को विधानसभा के बाहर भाजपा ने अपने 12 सदस्यों के निलंबन के विरोध में समानांतर सदन चलाया। एएनआइ

महाराष्ट्र विधानभवन परिसर में मंगलवार को एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। एक तरफ सदन के अंदर महाविकास अघाड़ी के विधायक कार्रवाई में हिस्सा ले रहे थे। दूसरी ओर विपक्षी भाजपा के विधायक विधानसभा के बाहर समानांतर सदन चलाते दिखाई दे रहे थे।

महाराष्ट्र विधानमंडल के मानसून सत्र का मंगलवार को दूसरा एवं अंतिम दिन था। पहले दिन विपक्षी दल भाजपा के 12 विधायकों को साल भर के लिए निलंबित कर दिया गया था। इसके विरोध में मंगलवार को सभी भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर पांच घंटे तक समानांतर विधानसभा चलाई। समानांतर सत्र की अध्यक्षता वरिष्ठ भाजपा विधायक कालीदास कोलंबकर ने की। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि हमने इस समानांतर विधानसभा के जरिये सरकार के चेहरे से पर्दा हटाने का काम किया है। हमारा आंदोलन किसानों, विद्यार्थियों, मराठा नौजवानों एवं अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याएं पूरी होने तक जारी रहेगा। फड़नवीस ने महाविकास अघाड़ी सरकार को कौरव की उपमा देते हुए कहा कि ठाकरे सरकार का अहंकार दुर्योधन सरीखा है। जैसे दुर्योधन का अहंकार उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा था, वैसे ही इस सरकार का अहंकार भी सिर चढ़कर बोल रहा है। दूसरी ओर, सीएम उद्धव ठाकरे ने सत्र के पहले दिन हुए घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि कल जो कुछ भी विस में कार्यवाहक अध्यक्ष के साथ हुआ, वह महाराष्ट्र की परंपरा को शर्मिंदा करने वाला था। यह अपनी संस्कृति नहीं है। हम उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार देते हैं। बता दें कि उद्धव ठाकरे सोमवार को विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष के साथ हुए दुर्व्यवहार का जिक्र कर रहे थे, जिसके बाद भाजपा के 12 विधायकों को साल भर के लिए निलंबित कर दिया गया।

जनजातियों को वन अधिकार के लिए केंद्र सरकार का साझा अभियान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जनजातियों को जंगल से जोड़ने और उससे जुड़े उनके अधिकारों को प्रदान करने के लिए केंद्र ने फिर एक बड़ी पहल की है, जिसमें वन एवं पर्यावरण और जनजातीय मामले के मंत्रालय एक साथ मिलकर वन अधिकार कानूनों को पूरी तरह जमीन पर उतारने के लिए काम करेंगे। दोनों ही मंत्रालयों ने इसे लेकर एक साझा सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इसके साथ ही राज्यों को भी वन अधिकारों के अमल के लिए मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इस मौके पर कहा कि वन अधिकार कानून वैसे तो वर्ष 2006 में बना था, लेकिन अब तक उसकी कुछ ही बातें लागू हो पाई हैं। ऐसे में इसे पूरी लागू करने के लिए यह नई पहल की गई है। उन्होंने कहा कि इसकी जिन बातों पर अमल नहीं हो सका, उसके पीछे की वजह दोनों विभागों में समन्वय न होना था। वन वासियों का विकास तभी होगा जब उन्हें शिक्षा के साथ वनों का अधिकार भी मिलेगा। खासबात यह है कि जनजातियों को वन अधिकार देने के लिए केंद्र सरकार ने 2006 में ही कानून लाया था। इस दौरान राज्यों को वनोपज को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी राज्यों को इसके लिए अपनी एक नोडल एजेंसी गठित करने का भी सुझाव दिया गया है।

वन एवं पर्यावरण मंत्री जावडेकर ने जनजातियों के विकास के लिए मोदी सरकार के उठाए गए कदमों का एक ब्योरा भी पेश किया। साथ ही बताया कि सात सालों में मोदी सरकार ने पांच लाख से ज्यादा जनजातियों को जमीन के पट्टे दिए हैं। चार लाख से ज्यादा आदिवासियों को वन-धन योजना का लाभ दिया है। वन उपजों पर मिलने वाले समर्थन मूल्य का भी दायरा बढाया है। पहले सिर्फ दस वनोपज पर ही समर्थन मूल्य मिलता था। अब इस योजना में 68 वनोपज को शामिल कर दिया गया है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के साथ हुए इस करार के मौके पर जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा, दोनों ही विभागों के राज्य मंत्री और सचिव भी मौजूद रहे।

> **मिलेगा हक**
>
> ▶ वन एवं पर्यावरण व जनजातीय मामले के मंत्रालय मिलकर करेंगे काम
>
> ▶ वर्ष 2006 में बने कानून पर अब तक ठीक से नहीं हुआ अमल



केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर। जागरण आर्काइव

'मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों में रहने वाले लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करें'

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र को यह सुनिश्चित करने को कहा कि मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों में रह रहे लोगों की कोरोना जांच की जाए और उनका पूर्ण टीकाकरण हो। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों से लोगों को भिक्षुक गृह भेजे जाने के मामले का गंभीरता से संज्ञान लिया और तुरंत इसे रोकने का निर्देश दिया। कहा कि यह नुकसानदेह है और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के प्रविधानों के खिलाफ है। शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 12 जुलाई को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की बैठक में शामिल होने और पूर्ण सहयोग करने का निर्देश भी दिया। पीठ ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ऐसे केंद्रों में जो लोग ठीक हो गए हैं, लेकिन अब भी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में हैं या जिन्हें अब भी उपचार की आवश्यकता है, उनके बारे में प्रस्तुत आंकड़ों में विसंगतियों को दूर करने को भी कहा। अदालत ने कहा कि वह अब इस मामले की निगरानी करेगी और तीन सप्ताह बाद मामले पर सुनवाई करेगी, क्योंकि यह बेहद संवेदनशील मुद्दा है।

फड़नवीस के कार्यकाल में हुई फोन टैपिंग की जांच कराने के आदेश

राज्य ब्यूरो, मुंबई

> ▶ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने विस में उठाया फोन टैपिंग का मुद्दा

महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार भाजपा के कार्यकाल में हुई प्रमुख व्यक्तियों की फोन टैपिंग मामले की जांच कराएगी। यह आदेश गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने महाराष्ट्र विधानसभा में दिया।

मंगलवार को मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने फोन टैपिंग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 2016-17 में विधायकों-सांसदों के फोन टैप किए जाते थे। बता दें कि उस समय राज्य में देवेंद्र फड़नवीस की सरकार थी। पटोले का आरोप था कि उस दौरान समाज के लिए घातक लोगों के फोन टैप करने के नाम पर सांसदों-विधायकों के फोन टैप किए जाते थे। इसी कड़ी में मेरा नंबर 'अमजद खान' के नाम से टैप किया गया। पटोले ने सवाल उठाया कि यह फोन टैपिंग किसके आदेश पर की जाती रही? इसका सूत्रधार कौन था? पटोले ने इन सवालों के साथ पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग सदन में उठाई। उनके इस प्रश्न पर गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने इस पूरे प्रकरण की जांच का आदेश देते हुए कहा कि फोन टैपिंग एक गंभीर मामला है। इसका आदेश आसानी से नहीं दिया जाना चाहिए। पाटिल के अनुसार वह बुधवार को उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पर चर्चा करेंगे।

बता दें कि राजनीतिक हलकों में यह मामला महाविकास अघाड़ी सरकार के ही कार्यकाल के शुरुआती दिनों में हुई फोन टैपिंग की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। उस दौरान महाराष्ट्र पुलिस में इंटेलीजेंस की प्रभारी रहीं आइपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला ने गृह विभाग की अनुमति से कुछ लोगों के फोन टैप किए थे। इस फोन टैपिंग से ही पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले में हस्तक्षेप की जानकारी मिली थी। रश्मि शुक्ला ने यह रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री को दी थी। लेकिन बाद में यह रिपोर्ट उन्हीं गृह मंत्री के पास जा पहुंची थी, जिनके खिलाफ यह रिपोर्ट तैयार की गई थी। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में इस रिपोर्ट का भी जिक्र किया था। बाद में यह रिपोर्ट बांबे हाई कोर्ट के सामने भी पेश की गई। अब उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआइ अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है। इसी कड़ी में वह रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट की भी जांच करना चाहती है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार सीबीआइ जांच का दायरा बढ़ाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुकी है।

स्मरण

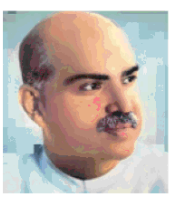
श्यामा प्रसाद की जयंती पर मोदी और शाह ने दी श्रद्धांजलि

> मोदी बोले– देश की अखंडता व विकास को समर्पित रहा मुखर्जी का जीवन, शाह ने कहा– जनसंघ के रूप में बोया बीज आज बन चुका भाजपा रूपी वटवृक्ष

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 120वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक विद्वान और बुद्धिजीवी के रूप में याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके उच्च विचारों ने पूरे देश में लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनके अनुसार श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन भारत की अखंडता और विकास को समर्पित कर दिया था। वहीं अमित शाह ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत का फिर से विभाजन होने से बचा लिया।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कालजयी व्यक्तित्व बताते हुए अमित शाह ने कहा कि उनके लिए देशहित से ऊपर कुछ नहीं था। आजादी के तत्काल बाद एक राष्ट्र एक निशान और एक विधान का नारा देकर उन्होंने देश में पनप रही विभाजनकारी सोच का कड़ा प्रहार किया। देश की अखंडता के लिए उनके बलिदान और संघर्ष के कारण ही बंगाल और कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग हैं।



भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जागरण आर्काइव

उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का शिल्पी बताया और कहा कि उनके ये विचार चिरकाल तक प्रासंगिक रहेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी दूरदर्शी सोच से देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास की मजबूत नींव रखने और सामरिक रूप से भारत को सशक्त बनाने में अहम योगदान दिया। शाह के अनुसार श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्पष्ट मानना था कि यदि हम अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी सभ्यता, अपनी नींव और अपने इतिहास को संरक्षित नहीं रख सकते, तो हम अपने देश का कदापि भला नहीं कर सकते।

अमित शाह के अनुसार श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सत्ता को छोड़कर अपने सिद्धांतों और देश सेवा के लिए संघर्ष का रास्ता चुना और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का ध्येय लेकर जनसंघ की स्थापना की। शाह के अनुसार 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ के रूप जो बोया था, वही आज भाजपा रूपी वटवृक्ष बनकर देश को विकास पथ पर आगे ले जा रहा है।

नड्डा ने कहा, मोदी सरकार ने पूरा किया डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना

संवाद सूत्र, कुल्लू : भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा जनसंघ के संस्थापक डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 'एक देश, एक विधान, एक प्रधान व एक निशान' का जो सपना देखा था, नरेंद्र मोदी सरकार ने उसे पूरा कर दिखाया है। देश की एकता व अखंडता के लिए डा. मुखर्जी द्वारा प्रशस्त जीवनपथ पर अग्रसर होना सभी का दायित्व है। डा. मुखर्जी को कृतज्ञ राष्ट्र और देशभक्तों की ओर से यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नड्डा ने मंगलवार को कुल्लू के पिरडी बूथ में डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर रुद्राक्ष का पौधा लगाने के बाद कहा कि जम्मू-कश्मीर की समस्या को पहचानने तथा इसके समूल निस्तारण के लिए पुरजोर आवाज उठाने वाले डा. मुखर्जी ही थे। बंगाल विभाजन की परिस्थिति के बीच भारत के हितों का पक्षधर बनकर अगर कोई खड़ा हुआ तो वह डा. मुखर्जी ही थे। आजादी के बाद सत्ता में आई कांग्रेस द्वारा देश पर थोपी जा रही गैर भारतीय तथा आयातित विचारधाराओं का विरोध कर भारत, भारतीय तथा भारतीयता के विचारों के अनुरूप राजनीतिक विकल्प देश को देने वालों में अग्रणी डा. मुखर्जी ही थे। डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत पर उनकी माता ने उस समय के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से जांच की मांग की थी। पत्र भी लिखा था, मगर जांच नहीं हुई।

कह के रहेंगे — माधव जोशी



98 सदस्य हो सकते हैं बंगाल में विधान परिषद बनने की सूरत में। लेकिन इसके गठन की संवैधानिक प्रक्रिया अभी काफी लंबी है। इसलिए बहुत कुछ केंद्र के रुख पर निर्भर करेगा।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 7 जुलाई, 2021

सोनिया गांधी-कैप्टन की मुलाकात में तय हुआ सुलह का फार्मूला

किस्सा पंजाब ▸ हाईकमान का हर फैसला मानने की घोषणा कर अमरिंदर ने दिखाई नरमी

पार्टी नेतृत्व ने भी दिया संदेश कैप्टन ही रहेंगे चुनावी चेहरा

संजय मिश्र, नई दिल्ली



कांग्रेस की पंजाब इकाई में अंतर्कलह के बीच मंगलवार को नई दिल्ली में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बाहर निकलते मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। प्रेट्र

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे में पार्टी के घमासान के समाधान के लिए हाईकमान के फार्मूले और फैसले मानने का एलान कर दिया है। कैप्टन के इस एलान से पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू की बड़ी और नई भूमिका का रास्ता लगभग साफ हो गया है। साथ ही अमरिंदर और सिद्धू के बीच सियासी संतुलन साधने के लिए हाईकमान ने यह भी साफ कर दिया कि पंजाब विधानसभा के चुनाव में अमरिंदर ही कांग्रेस के चुनावी कैप्टन रहेंगे। अमरिंदर ने चुनाव के लिए अपनी पूरी तैयारी का खम ठोक इसका संदेश भी दिया। पंजाब में कांग्रेस का झगड़ा सुलझाने के लिए सोनिया और कैप्टन की हुई बैठक के बाद सिद्धू को संगठन में बड़ी भूमिका सौंपे जाने की उम्मीद है।

सोनिया गांधी और कैप्टन की मुलाकात में पंजाब का झगड़ा सुलझाने पर बनी सहमति के बाद अब हाईकमान सिद्धू की नई भूमिका और प्रदेश कांग्रेस में बदलाव से जुड़े फैसलों की जल्द ही घोषणा करेगा। दस जनपथ पर सोनिया गांधी से हुई करीब डेढ़ घंटे की बातचीत के बाद बाहर निकले कैप्टन अमरिंदर ने पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के साथ अपनी सरकार के विकास कार्यों और राजनीतिक मसलों को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हम चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार हैं और पंजाब में पार्टी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जो भी फैसला लेंगी हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाईकमान का जो भी फैसला होगा उस पर पूरी तरह अमल करेंगे। कैप्टन ने इस बयान के जरिए सूबे में पार्टी का झगड़ा सुलझाने के लिए अपना रुख नरम करने का संदेश दे दिया। वैसे मुख्यमंत्री ने पंजाब में पार्टी को लेकर हाईकमान के किसी फैसले को मानने की बात से यह स्पष्ट कर दिया कि सिद्धू की नई राजनीतिक भूमिका सरकार में नहीं कांग्रेस संगठन में होगी। गौरतलब है कि सुलह फार्मूले में एक विकल्प सिद्धू की उपमुख्यमंत्री के तौर पर सरकार में वापसी की थी मगर राहुल और प्रियंका के जरिये सियासी दांव चल रहे सिद्धू ने बाद में इसकी जगह संगठन में अहम भूमिका के लिए पेशबंदी शुरू कर दी। चर्चा है कि उन्हें पंजाब प्रदेश कांग्रेस अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है।

सिद्धू की वापसी का रास्ता बनाने के लिए ही सोनिया गांधी की कैप्टन से होने वाली मुलाकात के कुछ घंटे पहले राहुल ने दस जनपथ जाकर कांग्रेस अध्यक्ष से बातचीत की थी। प्रियंका भी सक्रिय रहीं। सोनिया और कैप्टन की आधे घंटे चली मुलाकात के बाद पंजाब का झगड़ा सुलझाने को बनी तीन सदस्यीय समिति के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में शामिल होने पहुंचे। तीनों की बातचीत में सिद्धू को समायोजित करने के फार्मूले पर अमरिंदर ने हामी भर दी।

हालांकि कैप्टन ने हाईकमान का फैसला सिर माथे पर होने की चाहे बात कही हो मगर जब पत्रकारों ने सिद्धू के बारे में उनसे पूछा तो अमरिंदर ने एक तरह से बेरुखी दिखाते हुए कहा- 'सिद्धू साहब के बारे में मैं कुछ नहीं जानता।'

इस्तीफा साथ लेकर सोनिया से मिलने गए थे कैप्टन

इंद्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मंगलवार को पार्टी के अंतर्कलह को पूरी तरह निपटाने के इरादे से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के मुलाकात करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि वह इस्तीफा तक ले गए थे, लेकिन सोनिया से मुलाकात के बाद काफी हद तक संतुष्ट नजर आए।

विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री कैबिनेट में बदलाव करने के भी इच्छुक हैं। वह मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर एक सूची साथ ले गए थे। इस सूची में माझा क्षेत्र के कुछ मंत्रियों के पर कतरने की तैयारी थी। माझा से ही कांग्रेस सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री हैं जिनमें सुखविंदर सिंह सरकारिया, ओपी सोनी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा और अरुणा चौधरी के नाम शामिल हैं। यह पांचों मंत्री केवल दो जिलों अमृतसर व गुरदासपुर से संबंध रखते हैं और किसी समय कैप्टन अमरिंदर सिंह के खास रहे हैं। परंतु अब उनका विरोध कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को भी माझा के कोटे से ही मंत्री बनाया गया था।

कैप्टन के साथ दिल्ली गए विधायक डा. राजकुमार वेरका ने मीडिया से बात करते हुए संकेत दिए कि कैबिनेट में बड़ा बदलाव हो सकता है। उन्होंने पार्टी के संगठन में भी बड़े बदलाव के संकेत दिए परंतु कैप्टन सिंह ने बैठक के बाद मीडिया के साथ बातचीत में इसे लेकर कुछ नहीं कहा। हालांकि जानकार बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री किसी भी सूरत में सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनते नहीं देखना चाहते हैं।

उत्तराखंड में सीएम ने पोटली से निकाले हैवीवेट विभाग

मिशन 2022

- सतपाल महाराज, डा. हरक सिंह, यशपाल आर्य, डा. धन सिंह रावत व यतीश्वरानंद का बढ़ा वजन
- पुराने विभाग रखे यथावत, पांच मंत्रियों को मिला वजनदार विभाग

राज्य ब्यूरो, देहरादून

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चौथे दिन के होमवर्क के बाद अपने मंत्रिमंडल के 11 मंत्रियों के लिए विभागों का बंटवारा कर दिया। महज छह महीने बाद प्रदेश में चुनाव होने हैं, मिशन 2022 को ध्यान में रखकर युवा मुख्यमंत्री ने अनुभवी सहयोगियों को कार्य आवंटन में दरियादिली के साथ दूरदर्शिता भी दिखाई। 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद पहली दफा स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा, ग्राम्य विकास जैसे हैवीवेट विभाग मुख्यमंत्री की पोटली से बाहर निकले हैं।

गृह, वित्त, नियोजन व तकनीकी शिक्षा समेत 12 विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं। सभी 11 मंत्रियों के पिछले विभागों से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। खफा चल रहे वरिष्ठों के सम्मान का ध्यान रखते हुए बड़े विभागों से उन्हें नवाजा गया है।

मंत्रिमंडल में सतपाल महाराज, डा. हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, डा. धन सिंह रावत और स्वामी यतीश्वरानंद का वजन बढ़ा है। धामी ने पूर्व मुख्यमंत्रियों त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत की तुलना में अपने सहयोगियों पर ज्यादा भरोसा दिखाया है।

चुनाव से चंद महीनों पहले मुख्यमंत्री पद की अहम जिम्मेदारी संभालने वाले पुष्कर सिंह धामी ने पोर्टफोलियो वितरण के जरिये चुनौतियों से निपटने की अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी। कम समय में विकास कार्यों को अंजाम देने की चुनौती को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने विभागों के बंटवारे में सतर्कता बरती।



पुष्कर सिंह धामी की फाइल फोटो।

अनुभवी मंत्रियों की नाराजगी दूर करने के लिए महत्वपूर्ण विभाग सौंपकर उन्हें परफारमेंस साबित करने का अवसर भी दिया है। पिछले तीरथ मंत्रिमंडल के बाद अब धामी मंत्रिमंडल में शामिल सतपाल महाराज को लोक निर्माण विभाग, डा. हरक सिंह रावत को ऊर्जा व वैकल्पिक ऊर्जा, यशपाल आर्य को आबकारी, डा. धन सिंह रावत को चिकित्सा स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा और यतीश्वरानंद को ग्राम्य विकास के रूप में अतिरिक्त विभाग दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने अपने पास 12 विभाग रखे हैं।

उप्र में एमएलसी के लिए चर्चा में कई नाम, नहीं लगी अंतिम मुहर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- भाजपा कोर कमेटी की बैठक में ब्लाक प्रमुख चुनाव की रणनीति पर भी मंथन

सेवा कार्यों के जरिये जनता से जुड़ाव बढ़ाने की नीति पहले ही तय कर चुकी भाजपा की कोर कमेटी एक बार फिर विचार-मंथन के लिए बैठी। विधानसभा चुनाव के लिए क्षेत्रीय-जातीय समीकरण साधने के हर प्रयास में जुटी पार्टी ने विधान परिषद की चार रिक्त सीटों पर मनोनयन के लिए इसी आधार पर कई नामों पर चर्चा की, लेकिन अभी नाम तय नहीं हो सका। इसी तरह ब्लाक प्रमुख चुनाव में भी अधिक से अधिक सीटें जीतने की रणनीति पर विचार-विमर्श चला।

भाजपा कोर कमेटी की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डा. दिनेश शर्मा शामिल हुए। दोपहर से ही चर्चा थी कि विधान परिषद की चार रिक्त सीटों पर मनोनयन के लिए नाम कोर कमेटी तय करेगी।

सूत्रों ने बताया कि बैठक में संगठन के कई पदाधिकारी-कार्यकर्ताओं के नामों पर चर्चा की गई। इसमें जोर था कि संगठन में पदाधिकारी बनाने में जिस तरह से क्षेत्रीय-जातीय संतुलन का ध्यान रखा गया, उसी तरह विधान परिषद सदस्य बनाने में भी संतुलन रहे। इस आधार कई नामों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई नाम तय नहीं हो सका।

पंजाब में आप के बागी विधायकों का इस्तीफा नहीं हुआ मंजूर

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : कांग्रेस में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के तीनों बागी विधायकों सुखपाल सिंह खैहरा, पिरमल सिंह खालसा और जगदेव सिंह कमालू के विधायक पद से इस्तीफों पर मंगलवार को भी कार्रवाई नहीं हो सकी। पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा के पी सिंह मंगलवार को चंडीगढ़ से बाहर होने के कारण विधानसभा में नहीं आए। तीनों विधायकों को मंगलवार को स्पीकर के सामने पेश होना था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि स्पीकर विधानसभा नहीं आए हैं तो वह भी नहीं पहुंचे। इन विधायकों की सुनवाई 20 जुलाई तक स्थगित कर दी गई है। इन तीनों को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस में शामिल किया था और इन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया।

बंगाल विस से पारित हुआ विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- ममता सरकार के प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 196 वोट, विरोध में 69
- ममता बनर्जी ने चुनावी घोषणा पत्र में इसके गठन का किया था वादा

बंगाल में तीसरी बार सत्ता में आई ममता बनर्जी सरकार द्वारा राज्य विधान परिषद के गठन के लिए मंगलवार को पेश प्रस्ताव विधानसभा से पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत यह प्रस्ताव पेश किया। मुख्य विपक्षी भाजपा ने इसका विरोध किया। चर्चा के बाद जब मतदान हुआ तो 69 के मुकाबले 196 मतों से यह प्रस्ताव पारित हो गया।

गौरतलब है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने विधान परिषद के गठन को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था। पांच मई को तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बमुश्किल 12 दिन बाद ही ममता सरकार को विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी। इसी कड़ी में मंगलवार को इसे विधानसभा में पेश किया गया। गौरतलब है कि बंगाल में पहले विधान परिषद की व्यवस्था थी, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से इसे 21 मार्च, 1969 को खत्म कर दिया गया था।

इन तर्कों के साथ भाजपा ने किया विरोध : प्रस्ताव का विरोध करते हुए भाजपा विधायक दल के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस पिछले दरवाजे की राजनीति करना चाहती है ताकि विधानसभा चुनावों में हारने के बावजूद नेता निर्वाचित हो जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि इस कदम से राज्य के राजस्व पर असर पड़ेगा। भाजपा विधायकों ने इस दौरान सदन में सीएम की अनुपस्थिति को लेकर भी हो-हल्ला मचाया। आइएसएफ के एकमात्र विधायक नौशाद सिद्दीकी ने भी प्रस्ताव का विरोध किया।

संसद के दोनों सदनों से भी बिल को कराना होगा पारित

विधानसभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद भी विधान परिषद का गठन इतना आसान नहीं है। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इसके बाद इसे केंद्र के पास भेजा जाएगा। ममता सरकार के सामने असल चुनौती इसे संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराने की होगी। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी भी जरूरी है। इसके बाद ही विधान परिषद के गठन का रास्ता साफ हो पाएगा। गौरतलब है कि बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। यदि विधान परिषद का गठन होता है तो नियम के अनुसार उसमें 98 सदस्य होंगे।

छह राज्यों में है विधान परिषद की व्यवस्था

मौजूदा समय में छह राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है। इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना शामिल हैं। इससे पहले जम्मू-कश्मीर में भी विधान परिषद थी, लेकिन पांच अगस्त, 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसकी मान्यता खत्म हो गई।

हिंसा मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर दायर हुई पुनर्विचार याचिका

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है, जिसमें चुनाव के बाद हिंसा को लेकर दिए गए निर्देश पर फिर से सुनवाई की अपील की गई है।

जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार की ओर से पुनर्विचार की अपील कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष की गई है। इसमें दो जुलाई के दिशा-निर्देशों पर पुनर्विचार की अपील की गई है। याचिका में कहा गया है कि अदालत का निर्देश एकतरफा था। राज्य सरकार से कोई राय नहीं ली गई थी। इस मामले की अगले हफ्ते सुनवाई होगी।

गौरतलब है कि हाई कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर पुलिस को सभी हिंसा पीड़ितों की शिकायतों को दर्ज करने के साथ राज्य सरकार को घायलों को चिकित्सा एवं सभी पीड़ितों को राशन मुहैया कराने का निर्देश दिया गया था। साथ ही हाई कोर्ट ने मानवाधिकार आयोग की जांच की अवधि को भी 13 जुलाई तक बढ़ा दिया। अब ममता सरकार ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

'आयोग भाजपा की मदद नहीं करता तो वह 30 सीट भी नहीं जीत पाती'

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को भाजपा पर एक बार फिर हमला बोलते हुए कहा कि उसके विधायक शिष्टाचार और शालीनता नहीं जानते। विधानसभा में पिछले दिनों राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अभिभाषण के दौरान हुए हंगामे से यह बात जाहिर हो गई है। ममता ने चुनाव आयोग व मानवाधिकार आयोग को भी निशाने पर लिया और केंद्र के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि चुनाव आयोग मदद नहीं करता तो भाजपा बंगाल विधानसभा के चुनाव में 30 सीट भी नहीं जीत पाती।

विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मंगलवार को ममता ने कहा कि भाजपा ने बंगाल पर कब्जा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र के इशारे पर चुनाव आयोग ने आठ चरणों में चुनाव कराने से लेकर पुलिस अधीक्षकों से लेकर जिलाधिकारियों तक के तबादले कर डाले। ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि मैंने ऐसा पीएम नहीं देखा है, जिसकी सब जगह तस्वीर लगानी होगी। दूसरी ओर, उन्होने ने चुनाव के दौरान काफी लोकप्रिय हुए 'खेला होबे' नारे के नाम पर राज्य में हर साल 'खेला होबे' दिवस मनाने की भी मंगलवार को विधानसभा में घोषणा की।



ममता ने मानवाधिकार आयोग पर भी लगाया केंद्र के इशारे पर काम करने का आरोप

अब सांसदों के लिए भी 'एक व्यक्ति, एक पद' की नीति पेश करेंगी ममता

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी सांसदों के लिए भी 'एक व्यक्ति, एक पद' की नीति पेश करने जा रही हैं। गौरतलब है कि टीएमसी ने बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पार्टी में 'एक व्यक्ति, एक पद' की नीति लागू कर दी थी। अलबत्ता, ममता इस दायरे से बाहर हैं। वह मुख्यमंत्री के साथ ही पार्टी की अध्यक्ष बनी रहेंगी। सूत्रों के मुताबिक, नई नीति के आधार पर टीएमसी लोकसभा और राज्यसभा में संसदीय दल के नेता, उपनेता और मुख्य सचेतक को भी बदल सकती हैं। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होगा।

हिंसा के मुद्दे पर भाजपा व टीएमसी में भिड़ंत, बहिष्कार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर भाजपा आक्रामक है। मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने साथ ही भाजपा विधायकों ने हिंसा पर चर्चा की मांग उठाई। हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने चर्चा के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद भाजपा विधायकों ने विरोध जताते हुए हंगामा किया। इस दौरान विपक्षी भाजपा और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के विधायक आपस में भिड़ भी गए।

चुनाव बाद जारी हिंसा के मसले पर भाजपा विधायकों ने जहां ममता सरकार को घेरा, वहीं टीएमसी की तरफ से आरोपों को खारिज कर दिया गया। बाद में प्रतिपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सभी भाजपा विधायक सदन से बहिष्कार कर गए। सुवेंदु ने आरोप लगाया कि उन्हें तृणमूल विधायकों ने बोलने से भी रोका।

इससे पहले विधानसभा में हंगामा भाजपा विधायक मिहिर गोस्वामी के भाषण के दौरान भी हुआ। सदन की कार्यवाही के दौरान मिहिर गोस्वामी बोलने लगे तो टीएमसी विधायकों ने उनके दल बदलने को लेकर कटाक्ष किया।

बिहार में संभलकर चल रही भाजपा, सवाल है लोजपा के कोर वोटरों का

राज्य ब्यूरो, पटना

- अनुसूचित जाति के मतदाताओं के कारण चिराग और पारस गुट के बारे में बोलने से परहेज कर रहे भाजपा नेता

लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के दो खेमों के बीच से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) चतुराई से निकल जाने की जुगत में है। दोनों खेमों के एक ही बिरादरी के मतदाता एकमुश्त मतदान करते हैं। पिछले चुनावों में भाजपा को इसका फायदा मिलता रहा है और वह आगे भी इसे बचाए रखना चाहती है। यही कारण है कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बारे में किसी तरह की टीका-टिप्पणी से भाजपा के नेता परहेज कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल में संभावित विस्तार को लेकर लोजपा के दोनों गुटों में तकरार चल रही है। दिल्ली से पटना तक सियासी सरगर्मी के बीच भाजपा के लिए धर्म-संकट की स्थिति है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में रामविलास पासवान की जगह बहुत पहले से रिक्त है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में लोजपा उसकी स्वाभाविक हकदार है, लेकिन सवाल यह है कि चिराग और पारस गुट में से किसे प्रतिनिधित्व दिया जाए?

लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान अपनी बिरादरी के दम पर राजनीति में एक मुकाम भी पाए और शोहरत भी। अनुसूचित जाति की पासवान बिरादरी का वोट बैंक एक बार फिर चर्चा में है। लोजपा के इस कोर वोट बैंक पर भाजपा की निगाह लगी हुई है। कुल मतदाताओं में इनकी संख्या चार से पांच फीसद है। ये मतदाता कई सीटों पर जीत-हार को प्रभावित करने की हैसियत रखते हैं। भाजपा की रणनीति यह है कि किसी भी सूरत में रामविलास पासवान के समर्थक वोटरों को अपने साथ जोड़े रखा जाए। माना जा रहा है कि चिराग और पारस के झगड़े का असर आने वाले दिनों में लोजपा के वोट बैंक पर पड़ सकता है। राज्य में अजा के 16 फीसद मतदाता हैं, जो 22 उप जातियों में बंटे हुए हैं। उनमें पासवान, मुसहर, भुइयां, डोम, धोबी और नट शामिल हैं। इन्हें अपने साथ जोड़ने का ध्यान रखते हुए भाजपा बिसात बिछाए हुई है।



पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान।

केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगा जदयू

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को स्पष्ट संकेत दिया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में जदयू को भी स्थान मिलने जा रहा है। मंत्रियों की संख्या, विभागों का बंटवारा और फार्मूला आदि के बारे में उन्होंने इसे प्रधानमंत्री का एकाधिकार बताया और कहा कि इसके लिए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह अधिकृत हैं।

पारस को मंत्री बनाया गया तो कोर्ट जाएंगे चिराग

लोजपा में टूट के बाद पटना में पहली प्रेस कांफ्रेंस में चिराग पासवान का अंदाज बेहद आक्रामक था। चाचा पशुपति कुमार पारस और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर पारस को लोजपा कोटे से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो वह अदालत जाएंगे। अगर उन्हें मंत्री बनाना है तो जदयू में शामिल कराकर बनाएं, लेकिन लोजपा से नहीं।

सियासत

फड़नवीस और चंद्रकांत पाटिल की उपस्थिति में आज हो सकते हैं भाजपा में शामिल, अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद कांग्रेस के रुख का विरोध करते हुए दिया था पार्टी से इस्तीफा

मुंबई में भाजपा का हिंदीभाषी चेहरा बनेंगे कृपाशंकर सिंह

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह भाजपा में प्रवेश करने जा रहे हैं। सिंह ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद कांग्रेस के रुख का विरोध करते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। माना जा रहा है कि सिंह के भाजपा प्रवेश से बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के आगामी चुनाव में समीकरण बदल सकते हैं।

कांग्रेस में लंबी पारी खेल चुके मूलतः उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी कृपाशंकर सिंह कांग्रेस छोड़ने के बाद अब तक किसी अन्य पार्टी में नहीं गए। हालांकि कांग्रेस की ओर से उन पर यह आरोप भी लगाया गया कि वह चुनाव जीतने की गरज से भाजपा या शिवसेना में जाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ा।



कृपाशंकर सिंह की फाइल फोटो।

पता चला है कि पिछले कुछ महीनों में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हो चुकी है। पिछले कुछ समय से वह पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के भी लगातार संपर्क में हैं। अब उनका भाजपा में जाना तय हो गया है। बुधवार को दोपहर 12 बजे वह फड़नवीस एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की उपस्थिति में भाजपा का दामन थाम सकते हैं।

कृपाशंकर सिंह का भाजपा प्रवेश अगले साल होने जा रहे बीएमसी चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा पिछले चुनाव में शिवसेना से सिर्फ चंद सीटों से पीछे रह गई थी। इस बार वह बीएमसी पर कब्जा कर शिवसेना को सबक सिखाना चाहती है। खासतौर से पिछले विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना ने जिस तरह से पाला बदला है, भाजपा उसका बदला लेना चाहती है। मुंबई में कई वार्ड ऐसे हैं, जहां हिंदीभाषी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मूलतः यह वर्ग कांग्रेस से ही जुड़ा रहा है। 2014 के बाद मोदी के नाम पर हिंदीभाषियों का रुझान तो भाजपा की ओर हुआ है, लेकिन मुंबई भाजपा में कोई प्रभावी हिंदीभाषी चेहरा न होने के कारण वह भाजपा से पूरी तरह जुड़ नहीं पा रहा है। भाजपा अब कृपाशंकर को लाकर इसी कमी को दूर करना चाहती है।

मुंबई की करीब सवा करोड़ आबादी में हिंदीभाषियों की संख्या 40 लाख के लगभग आंकी जाती है।

मूलतः रायबरेली निवासी डा. राममनोहर त्रिपाठी के बाद कृपाशंकर सिंह ही निर्विवाद हिंदीभाषी नेता के रूप में उभरकर सामने आ सके हैं। उनके मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष रहते कांग्रेस-राकांपा गठबंधन मुंबई की सभी छह लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रहा था। इनमें पांच सीटें कांग्रेस ने और एक उसकी सहयोगी राकांपा ने जीती थी। उनके मुंबई अध्यक्ष रहते विधानसभा चुनाव में भी मुंबई की 34 में से 22 सीटें कांग्रेस ने जीती थीं। इनमें सर्वाधिक छह हिंदीभाषी विधायक भी पहली बार ही चुनकर आए थे। यहां तक कि बीएमसी चुनाव में भी उनके कार्यकाल के दौरान 18 हिंदीभाषी सभासद चुनकर आए थे। अब भाजपा सिंह की इसी संगठन क्षमता का इस्तेमाल कर मुंबई का समीकरण अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही है।

मंत्री को बोले अपशब्द, अब तक सात सपाई गिरफ्तार, लगा पाक्सो एक्ट

जागरण संवाददाता, बलिया

- जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी, पूर्व मंत्री अंबिका समेत 10 सपा कार्यकर्ता हैं नामजद

जिला पंचायत के चुनाव में इस बार वह हुआ, जो पहले कभी बलिया में नहीं हुआ। अध्यक्ष पद के सपा प्रत्याशी चुनाव जीत गए, लेकिन उन पर अपशब्द बोलने के संगीन आरोप भी लगे। उप्र के खेल मंत्री उपेन्द्र तिवारी को मतदान के दिन अपशब्द बोले गए। यह हरकत किसी एक सपाई ने नहीं, बल्कि सैकड़ों ने की, अपशब्दों के सरेआम खूब नारे लगे।

मामले में पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया। शनिवार से अब तक कई कड़े फैसले लिए गए हैं। उन्हें सबक सिखाया जा रहा है, जिन्होंने ऐसी ओछी हरकत की है। खेल मंत्री उपेन्द्र तिवारी को अपशब्द बोलने के मामले में नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी, उनके पिता पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी समेत 10 सपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया। एक के बाद एक ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां भी चल रही हैं। छह थानों की पुलिस के अलावा एसओजी और खुफिया इकाइयों को अलर्ट मोड में रखा गया है। पांच आरोपित सोमवार तक गिरफ्तार कर लिए गए थे। हालांकि उन्हें कोर्ट से जमानत भी मिल चुकी है। दो आरोपित मंगलवार को पकड़े गए हैं। उन्हें बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पाक्सो एक्ट भी लगा दिया गया है। अभी आरोपित पूर्व मंत्री अंबिका और उनके पुत्र आनंद को शिकंजे में लेना बाकी है। प्रशासन कड़ी सजा देने की मुहिम छेड़ चुका है। पिछले तीन दिनों में पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी भी पलटवार कर चुके हैं, वह मंत्री उपेन्द्र पर भी अपशब्द कहने का संगीन आरोप लगा चुके हैं।

22 हजार से ज्यादा रिक्त पदों पर होगी भर्ती उत्तराखंड में। धामी मंत्रिमंडल की पहली बैठक में बेरोजगारों, अतिथि शिक्षकों को तोहफा।13 हजार पदों पर तत्काल भर्ती करने के निर्देश

न्यूज गैलरी

हावड़ा में जहरीली गैस के रिसाव से तीन की मौत

कोलकाता : बंगाल में निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक की खोदाई के दौरान जहरीली गैस के रिसाव होने से तीन मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गया। घटना हावड़ा के अमता के अंतर्गत झमटिया ग्राम पंचायत धर्मपोता गांव की है। पुलिस के अनुसार सभी मजदूर बीरभूम जिले के रहने वाले हैं। (राब्यू)

अपनी जन्मतिथि पर दलाई लामा का दुनिया को संदेश

धर्मशाला : तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा है कि जीवन में ईमानदारी, करुणा व अहिंसा का अहम स्थान है। उन्होंने कहा, वह स्वयं मृत्यु तक अहिंसा और करुणा के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मित्र भी जीवनभर अहिंसा व करुणा बनाए रखेंगे। तिब्बती धर्मगुरु मंगलवार को 86वीं जन्मतिथि पर विश्वभर के लोगों को आनलाइन संदेश दे रहे थे। (जासं)

भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 20 नवंबर से

मुंबई : सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मंगलवार को 52वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल (इफ्फी) के आयोजन, उसके नियमों से संबंधी विवरण और पोस्टर जारी किए। इस साल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 20 से 28 नवंबर तक गोवा में किया जाएगा। कोविड-19 की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए पिछले वर्ष की तरह इस बार भी फेस्टिवल का आयोजन हाइब्रिड फार्मेट (वर्चुअल और वास्तविकता का मिलाजुला प्रारूप) में किया जाएगा। (एंटरटेनमेंट ब्यूरो)

मंत्री व स्वजन को अपशब्द कहने पर दस पर पाक्सो एक्ट

बलिया : उप्र के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी और उनके स्वजन को अपशब्द कहे जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। मंगलवार को वादी के बयान के आधार पर मुकदमे में कई और धाराएं बढ़ा दी गई हैं। नाबालिग पर टिप्पणी करने के कारण नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी और उनके पिता उप्र के पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी समेत सभी आरोपितों पर प्रोटेक्शन आफ चाइल्ड फ्राम सेक्सुअल आफेंस (पाक्सो) एक्ट लगा दिया गया है।, (जासं)

एक ही आइडी से बने 2.38 लाख के ट्रेन टिकट बरामद

प्रतापगढ़ : ई-टिकट का अवैध कारोबार करने वाले प्रतापगढ़ में दो सहज जनसेवा केंद्र संचालकों को रेलवे की क्राइम ब्रांच वाराणसी टीम ने गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 2.38 लाख रुपये कीमत के ई-टिकट बरामद हुए हैं। अधिकांश टिकट दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता की यात्रा के लिए हैं। सभी एक ही आइडी (पहचान पत्र) से बनाए गए हैं। पूछताछ के बाद दोनों को आरपीएफ प्रतापगढ़ को सौंप दिया गया। मंगलवार को प्रयागराज रेलवे कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। पूछताछ में कई और लोगों के नाम सामने आए हैं। (जासं)

मोतिहारी में स्थिति गंभीर, समस्तीपुर में कटान

मुजफ्फरपुर: उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में नदियां कहर बरपा रही हैं। दरभंगा और समस्तीपुर में भी कटान शुरू हो गया है। मंगलवार को दोपहर बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। मधुबनी का बेनीपट्टी अनुमंडल बाढ़ से ज्यादा प्रभावित है। मधवापुर के अंदौली व बसवरिया में धौंस नदी का तटबंध टूटने से करीब दो दर्जन से अधिक गांवों में करीब 50 हजार से अधिक आबादी प्रभावित हैं। अंधरी, सहरौल, भगवतीपुर आदि जगहों पर सड़कें टूट चुकी हैं। जयनगर में ट्रैक पर पानी रहने से दूसरे दिन भी ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा। मंगलवार को वाल्मीकिनगर में गंडक बराज से एक लाख, 52 हजार, 900 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। शिवहर शहर स्थित जल संसाधन विभाग के कार्यालय में पानी घुस गया है। जेल का पानी निकल गया है। (जासं)

उमर गौतम के मदरसे की खोज में 30 से अधिक रडार पर

मतांतरण मामला ▶ गाजियाबाद के सभी 30 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर होगी एफआइआर

हसीन शाह, गाजियाबाद

मतांतरण के मुख्य सूत्रधार उमर गौतम के मदरसे की खोज में गाजियाबाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के रडार पर 30 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे आए हैं। विभाग इनके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराएगा। मदरसों को नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों को अंदेशा है कि उमर गौतम का मसूरी इलाके में मदरसा संचालित है या फिर वह मदरसों को फंडिंग करता था। लेकिन विभाग के पास उमर गौतम के मदरसे की अभी कोई जानकारी नहीं है।


उमर गौतम। फाइल

एजेंसियों को इनपुट मिला था कि उमर का गाजियाबाद में भी मदरसा संचालित है। इस प्रकार की जानकारी मिलने पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सतर्क हो गया। विभाग ने गाजियाबाद में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। जिले में अब तक 30 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले। इन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई का खाका खींच दिया गया है। मदरसों की संख्या इससे अधिक भी हो सकती है। विभागीय अफसर के अनुसार पूर्व में भी विभाग ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने के लिए नोटिस जारी किए थे। लेकिन फिर से चोरी-छिपे मदरसे संचालित होने शुरू हो गए। मसूरी, लोनी और भोजपुर इलाके में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या अधिक है।

> केवल मान्यता प्राप्त मदरसे ही जिले में संचालित होंगे। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को चिह्नित कर उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने का निर्णय लिया गया है। इन मदरसों को नोटिस भी भेजे जाएंगे। अभी चार मदरसों पर कार्रवाई करने के लिए पत्र मिला है। कार्रवाई करने के लिए पुलिस से बात हो गई हैं।
>
> -अमृता सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गाजियाबाद

नहीं लेना चाहते मान्यता: ज्यादातर गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मान्यता के लिए आवेदन करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि मान्यता मिलने पर उन्हें विभाग के नियमों का पालन करना होता है। चंदे का हिसाब देना होता है। उनमें एनसीईआरटी की पुस्तकें ही पढ़ाई जाएंगी। उधर, अल्पसंख्यक विभाग को चार मदरसों पर कार्रवाई करने के लिए पत्र प्राप्त हुआ। पत्र में जिन मदरसों का नाम लिखा हुआ है, विभाग ने उनका नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया है। कार्रवाई के बाद इन मदरसों का नाम खोला जाएगा। अल्पसंख्यक विभाग ने मदरसों पर कार्रवाई के लिए पुलिस से संपर्क किया है।

35 मदरसों को बनाया आधुनिक: शासन के आदेश पर जिले में 35 मदरसों का आधुनिकीकरण किया गया है। इन मदरसों में स्काउट गाइड शुरू कराने का भी आदेश हुआ था। मदरसों में एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं। मदरसों की शिक्षा पर विभाग की निगरानी रहती है।

लव जिहाद के आरोपित पर सुबूतों से कसेगा शिकंजा

जागरण संवाददाता, आगरा

आगरा में पूर्व आइएएस अधिकारी की बेटी को लव जिहाद के जाल में फंसाने वाले आरिफ हाशमी पर सुबूतों के आधार पर चौतरफा शिकंजा कसा जाएगा। इंस्पेक्टर सदर अजय कौशल ने बताया कि पीड़िता के कोर्ट में दिए गए बयानों का अवलोकन कर लिया गया है। इन्हें विवेचना में शामिल किया जा रहा है। आरोपित के खिलाफ मजबूत साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। इनसे आरोपित कानून से बच नहीं पाएगा।

सुबूत नंबर-एक

शादी का प्रमाण पत्र : लखनऊ निवासी आरिफ हाशमी ने पूर्व आइएएस अधिकारी की विवाहित बेटी से 2010 में लखनऊ के अलीगंज स्थित आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। यहां दस्तावेज में आरिफ ने अपना नाम आदित्य आर्य लिखाया था। पुलिस यहां से शादी का प्रमाण पत्र लेगी, जिससे यह साबित होगा कि उसने धोखाधड़ी और कूटरचना कर सिर्फ शादी के लिए अपना नाम बदला था।

सुबूत नंबर-दो

निकाहनामा : मंदिर में शादी के एक वर्ष बाद आरिफ ने अजमेर में महिला का मतांतरण कराया, उससे निकाह किया। पुलिस यहां से निकाहनामा और मतांतरण संबंधी दस्तावेज प्राप्त करेगी। इससे विधि विरुद्ध धर्मांतरण अधिनियम का आरोप साबित होगा।

सुबूत नंबर-तीन

पीड़िता द्वारा दिए गए वीडियो और फोटो : आरिफ होटल में लड़कियों को बुलाकर अय्याशी करता था, पीड़िता ने इसके कुछ वीडियो पुलिस को दिए हैं। साथ ही कुछ फोटो भी दिए हैं, जो आरोपित द्वारा उसे दी गई यातनाओं को प्रमाणित करते हैं।

सुबूत नंबर-चार

आरोपित के मोबाइल से मिले फर्जी पत्र : आरोपित के मोबाइल से कुछ फर्जी पत्र व अन्य दस्तावेज मिले हैं। इनको आरोपित ने अधिकारियों पर रौब जमाने के लिए मोबाइल में सेव कर रखा था। वह किस तरह लोगों को जाल में फंसाता था, यह दिखाने के लिए पुलिस की विवेचना में ये पत्र भी काम आएंगे।

सुबूत नंबर-पांच

पीड़िता और होटल कर्मचारियों के बयान : पीड़िता के पुलिस ने बयान दर्ज करने के बाद उसके कोर्ट में भी कलमबंद बयान करा दिए हैं। उसके यह बयान विवेचना में अहम हैं। पुलिस होटल के कर्मचारियों के भी बयान लेगी, जहां आरोपित रहता था। वह किस तरह पीड़िता को टार्चर करता था, यह उनके बयान में सामने आएगा।

चेन बनाकर चलाया जाता था 'नेटवर्क'

खतरनाक मतांतरण

आशुतोष गुप्ता, गाजियाबाद

मतांतरण के खेल में गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी के साथ सनसनीखेज जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। प्रदेशों व जिलों में मतांतरण कराने के लिए बाकायदा नेटवर्क फैलाया गया था। चेन बनाकर जिलों व प्रदेशों में सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। यह सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में मतांतरण के लिए लोगों को उकसाते थे और प्रचार करते थे। उमर गौतम इस नेटवर्क का सरगना है। इसके साथ ही उसके कई सहयोगी इस नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते थे। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली समेत हरियाणा के अधिकांश जिलों में इनके प्रतिनिधि काम कर रहे थे। एजेंसियां सभी नेटवर्क को तस्दीक करने में जुटी हुई हैं। बड़ी संख्या में पुलिस व एजेंसियों के अधिकारी मतांतरण की चेन से जुड़े सदस्यों को पकड़ने के लिए काम कर रहे हैं। जांच में लगातार एजेंसियों को नए नए तथ्य मिल रहे हैं। आरोपितों का केंद्र दिल्ली था, यहीं से सभी प्रदेशों व जिलों में फंडिंग की जाती थी। जांच में आया है कि गाजियाबाद में सलीमुद्दीन के माध्यम से मतांतरण का खेल चल रहा था।

आगरा में मुहल्लों से इंटरनेट मीडिया तक लव जिहाद का जाल

जागरण संवाददाता, आगरा : ताजनगरी में लव जिहाद का जाल मुहल्लों से लेकर इंटरनेट मीडिया तक फैला हुआ है। मुस्लिम युवक अलग-अलग तरीकों से किशोरियों और युवतियों को हिंदू नाम रखकर जाल में फंसाते हैं। दोस्ती कर उनका भरोसा जीतते हैं, ब्रेन वाश कर स्वजन से बगावत कराते हैं। अपने साथ ले जाकर मतांतरण करा निकाह कर लेते हैं। कुछ दिनों में सचाई सामने आती है तब तक युवतियां दलदल में फंस चुकी होती हैं। अब प्रदेश में विधि विरुद्ध धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम लागू होने के बाद ऐसे मामले थाने तक पहुंचने लगे हैं।

इंटरनेट मीडिया पर तमाम मुस्लिम युवकों ने हिंदू नामों से प्रोफाइल बना रखे हैं। फेसबुक या अन्य इंटरनेट मीडिया के माध्यम से युवतियों और किशोरियों से संपर्क करते हैं। दोस्ती होने पर लगातार उन्हें अपनी लुभावनी बातों में फंसाते हैं। फुसलाकर अपने साथ ले जाकर निकाह कर लेते हैं। सच्चाई सामने आने पर जब पीड़िता विरोध करती है तब उत्पीड़न करते हैं।

लव जिहाद के कुछ उदाहरण: आगरा में एक 16 वर्षीय किशोरी के घर नसीराबाद निवासी कासिम का आना था। हिंदू नाम से उसने किशोरी से दोस्ती कर ली। फुसलाकर अपने साथ ले गया। 17 वर्षीय किशोरी से इंटरनेट मीडिया के माध्यम से एक वर्ष पहले सहारनपुर के युवक इकरार ने रवि नाम बताकर दोस्ती की।

जम्मू-कश्मीर में परिसीमन आयोग से नहीं मिलेगी पीडीपी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मंगलवार को परिसीमन आयोग जैसे ही श्रीनगर पहुंचा तो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने उसकी वैधता पर सवाल उठाते हुए उससे मुलाकात से ही इन्कार कर दिया। सिर्फ यही नहीं, पीडीपी ने आरोप लगाया है कि परिसीमन की प्रक्रिया का परिणाम पहले से ही तय है और यह एक राजनीतिक दल विशेष के हितों के संरक्षण जबकि दूसरे एक वर्ग को राजनीतिक रूप से कमजोर बनाने के लिए हो रहा है। पीडीपी ने सर्वदलीय बैठक पर भी असंतोष जताया है और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विश्वास बहाली का कोई कदम न उठाए जाने से यह सिर्फ एक फोटो सेशन तक सीमित होकर रह गई है। सर्वदलीय बैठक गत 24 जून को हुई थी।

हालांकि, पीडीपी सोमवार की शाम को ही संकेत दे दिया था कि वह परिसीमन आयोग से मुलाकात नहीं करेगी, लेकिन उसने कोई एलान नहीं किया था। अलबत्ता, मंगलवार की दोपहर को पीडीपी के महासचिव गुलाम नबी लोन हंजूरा ने परिसीमन आयोग की अध्यक्ष जस्टिस (सेवानिवृत्त) रंजना देसाई को पत्र लिखकर कहा कि आयोग का फैसला पहले से ही तय है। इसलिए मुलाकात का कोई औचित्य नहीं है। आयोग को लिखे पत्र में पीडीपी ने अनुच्छेद 370 और 35ए को समाप्त करने का रोना रोया गया है। यह भी राग अलापा गया है कि 200 साल पुराने जम्मू-कश्मीर राज्य को भंग कर विभाजित कर दिया गया। लोन ने अपने पत्र में परिसीमन को उसी प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। साथ ही कहा कि इसलिए ही हमारी राय में परिसीमन आयोग की संवैधानिक और कानूनी मान्यता नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि देशभर में परिसीमन की प्रक्रिया को 2026 तक रोका गया है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में अपवाद के तौर पर यह प्रक्रिया शुरू की गई है। यहां आम लोगों में पहले से ही एक धारणा है कि परिसीमन आयोग सिर्फ औपचारिकता के लिए है।


जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मंगलवार को परिसीमन आयोग श्रीनगर पहुंचा। इस आयोग की अध्यक्ष जस्टिस (सेवानिवृत्त) रंजना देसाई हैं। एएनआइ

महबूबा मुफ्ती की मां को ईडी का नोटिस: परिसीमन आयोग से मुलाकात से इन्कार करने के चंद घंटे बाद मंगलवार दोपहर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का एक नोटिस पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के निवास पर पहुंचा।

आयोग ने राजनीतिक दलों का रुख टटोला

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : परिसीमन आयोग ने मंगलवार को अपने जम्मू कश्मीर मिशन को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सिर्फ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और अवामी नेशनल कांफ्रेंस (एएनसी) ही मुलाकात के लिए नहीं पहुंची। पीडीपी और एएनसी दोनों ही गुपकार एलांयस के घटक हैं और दोनों ने ही आयोग की वैधता को चुनौती देते हुए इससे मुलाकात से इन्कार कर दिया है। अन्य सभी ने आयोग के सदस्यों से अलग-अलग मुलाकात की। सभी ने आयोग की वैधता पर सवाल तो उठाया, लेकिन परिसीमन की प्रक्रिया पर सहमति जताते हुए इसे पूरी तरह निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी बनाने की मांग की। इस दौरान अनुसूचित जनजातियों और जातियों से न्याय, अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखने, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए समान आबादी का फार्मूला, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा और उसके बाद ही चुनाव कराए जाने जैसे मुद्दे उठाए गए।

स्मारक घोटाले में बसपा के दो पूर्व मंत्रियों से पूछताछ की तैयारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

▶ चुनाव नजदीक आते ही बढ़ी जांच एजेंसियों की सक्रियता, रिवरफ्रंट घोटाले में आई अचानक तेजी से भी हलचल

उप्र में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियों के साथ जांच एजेंसियों की सक्रियता भी बढ़ने लगी है। जांच एजेंसियों ने कई बड़े घोटालों की जांचों में अपने कदम बढ़ाए हैं। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज हो गई है। इसी बीच स्मारक घोटाले को लेकर बसपा शासनकाल के दो पूर्व मंत्रियों से भी पूछताछ की तैयारी है।

रिवरफ्रंट घोटाले में दूसरी एफआइआर दर्ज करने के बाद सीबीआइ ने सोमवार को आरोपितों के 49 ठिकानों पर छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की है। इसके बाद इस घोटाले में अब कई बड़ों की भूमिका की छानबीन के संकेत मिले हैं। ऐसे ही बसपा शासनकाल में हुए करीब 1400 करोड़ रुपये के स्मारक घोटाले की जांच सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) करीब सात वर्षों से कर रहा है। लोकायुक्त संगठन ने 2013 में स्मारकों के निर्माण में धांधली के आरोपों की जांच की थी। लोकायुक्त की जांच में करीब 1400 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया था। बाद में विजिलेंस ने एक जनवरी, 2014 को लखनऊ के गोमतीनगर थाने में स्मारक घोटाले में 199 आरोपितों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराकर जांच शुरू की थी।

एफआइआर में बसपा सरकार के पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी व बाबू सिंह कुशवाहा भी नामजद हैं। विजिलेंस ने कई बार इस मामले की जांच में तेजी पकड़ी और निर्माण निगम के कई तत्कालीन अधिकारियों पर शिकंजा भी कसा, लेकिन जांच कभी बड़ों तक नहीं पहुंच सकी। अब विजिलेंस ने इसी माह पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी व बाबू सिंह कुशवाहा को पूछताछ के लिए तलब किया है। स्मारक घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी कर रहा है। सपा शासनकाल में हुए खनन घोटाले की सीबीआइ जांच चल रही है और इस मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति जेल में हैं।

तीन दिन की बिजली कटौती से उद्योगपति नाराज

जागरण टीम, जालंधर

पंजाब में बिजली संकट

पंजाब में जारी बिजली संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उद्योगों में तीन दिन के लिए बिजली कटौती से उद्योगपति काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि उद्योग पहले ही कोरोना के कारण नुकसान में चल रहा है। अब लगातार बिजली कटौती होती रही तो मंदी आ जाएगी।

गौरतलब है कि पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने उद्योगों में तीन दिन का आफ-डे रखा है। औद्योगिक इकाइयों को कहा गया है कि सात जुलाई सुबह आठ बजे से 10 जुलाई सुबह आठ बजे तक उत्पादन बंद रखें। जालंधर इंडस्ट्रियल फोकल प्वाइंट एक्सटेंशन एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पत्र लिखकर 500 किलोवाट या उससे कम क्षमता वाले उद्योगों को हर हाल में चालू रखने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह सग्गू के मुताबिक उद्योग जगत को रोज 500 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। लुधियाना के एवन साइकिल लिमिटेड के सीएमडी ओंकार सिंह पाहवा के मुताबिक बिजली की तीस फीसद क्षमता से काम करने में कई कठिनाइयां होंगी। सरकार तत्काल उचित कदम उठाए। पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के प्रधान प्यारे लाल सेठ का कहना है कि पावर कट की वजह से इंडस्ट्री में मंदी आ सकती है।

सरकार ने बिजली खरीद के लिए पीएसपीसीएल को दिए 309 करोड़: पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीसपीसीएल) के सीएमडी ए. वेणु प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने पीएसपीसीएल को अतिरिक्त बिजली खरीदने के लिए 309 करोड़ रुपये दिए हैं। दावा किया कि घरेलू व कृषि के लिए बिजली की जरूरत को पूरा करने में कामयाब रहे हैं।

तेरह हजार मेगावाट तक रही मांग, 500 मेगावाट की कमी: मंगलवार को राज्य में बिजली की मांग 12,500 मेगावाट से 13,000 मेगावाट तक रही। कुल 12447 मेगावाट बिजली की सप्लाई की गई। करीब 500 मेगावाट की कमी रही। राज्य के विभिन्न प्लांटों से 5088 मेगावाट बिजली प्राप्त हुई, जबकि अन्य राज्यों से 7386 मेगावाट बिजली खरीदी गई।

बिजली संकट का कारण: पावरकाम ने इस वर्ष एक दिन में अधिकतम 13500 मेगावाट बिजली खपत का अनुमान लगाया था, लेकिन बारिश न होने के कारण ट्यूबवेल ज्यादा चलने से खपत 15000 मेगावाट को भी पार कर गई। रोपड़ व तलवंडी साबो प्लांटों की यूनिटें बंद होने से भी संकट बढ़ा। ट्रांसमिशन लाइनों की क्षमता 13500 होना भी आपूर्ति नहीं कर पाने का कारण बना।

सिद्धू ने फिर किया हमला: राब्यू, चंडीगढ़ : मंगलवार को जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठक कर रहे थे।

शिवपाल के करीबी ठेकेदार से चार घंटे पूछताछ

जागरण संवाददाता, इटावा

पूर्व मंत्री और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (प्रसपा) के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के करीबी बताए जा रहे ठेकेदार पुनीत अग्रवाल से गोमती रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर सीबीआइ टीम ने सोमवार देर रात चार घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद टीम कुछ कागजात लेकर लौट गई। ठेकेदार की फर्म की ओर से किए गए कार्यों के कागजातों की भी पड़ताल की।

सूत्रों के मुताबिक, सीबीआइ अफसर पुनीत से उसके घर में देर रात तक अलग कमरे में बैठकर पूछताछ करते रहे। इस दौरान टीम ने पुनीत से 15 सवालों के जवाब लिए। सीबीआइ टीम अपने साथ कंप्यूटर प्रिंटर, फोटो कापी व लेमिनेशन मशीन भी लाई थी। पूछताछ के दौरान पुनीत के वकील भी लगातार साथ में रहे। सोमवार को चर्चा थी कि पुनीत सीबीआइ टीम के आने के बाद गायब हो गए, लेकिन वह पिछले चार दिन से हरिद्वार में थे।

जिस फर्म को चाहा काम दिलवा दिया

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

सीबीआइ जांच में यह बात पहले ही सामने आ चुकी है कि नामजद आरोपित सिंचाई विभाग के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता रूप सिंह यादव, शिवमंगल यादव, जीवन राम यादव, अखिल रमन, तत्कालीन चीफ इंजीनियर ओम वर्मा, काजिम अली, एसएन शर्मा व अन्य अधिकारियों ने जिस फर्म को चाहा उसे काम दिलवा दिया। कार्यों के आवंटन के लिए बनी समिति के अध्यक्ष जिसे चाहते थे, उसे काम दे देते थे और उनके अप्रूवल पर समिति के अन्य सदस्य सहमति दे देते थे। जिन कामों के टेंडर की कागजी प्रक्रिया पूरी भी की गई, उनमें दो बोगस फर्में भी शामिल की जाती थीं। 30 से 35 टेंडर की सूचना के लिए फर्जी अखबार छपवाए गए थे। सीबीआइ अधिकारियों के गले से अब यह बात नहीं उतर रही है कि इतना बड़ा खेल इंजीनियर अपने स्तर से करते रहे और विभाग के बड़ों को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब गोमतीनगर रिवरफ्रंट परियोजना की शुरुआत हुई थी, तब सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव व प्रमुख सचिव सिंचाई दीपक सिंघल थे।

407 करोड़ के कार्यों में घपला: सपा शासनकाल में 1500 करोड़ रुपये की गोमती रिवरफ्रंट परियोजना से जुड़े करीब 407 करोड़ रुपये के कार्यों में घपला पकड़ा गया है। सीबीआइ लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने 407 करोड़ रुपये के 661 कार्यों की आरंभिक जांच के बाद बीती दो जुलाई को सिंचाई विभाग के 16 तत्कालीन अधिकारियों व कर्मियों समेत कुल 189 आरोपितों के विरुद्ध अपनी दूसरी एफआइआर दर्ज की थी।

तलाशे जाएंगे फर्म संचालकों के रसूख भी: सीबीआइ ने सोमवार को पहले चरण में उन फर्म संचालकों के घर छापे मारे, जिन्हें 15 से 20 करोड़ रुपये या उससे अधिक कीमत के काम आवंटित हुए थे।

स्टेन स्वामी की मौत पर 10 दलों के नेताओं का राष्ट्रपति को पत्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत 10 विपक्षी दलों के नेताओं ने मंगलवार को राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द को पत्र लिखकर फादर स्टेन स्वामी की मौत पर 'नाराजगी' जताई और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने में उनके हस्तक्षेप की मांग की।

हस्ताक्षर करने वालों में राकांपा प्रमुख शरद पवार, पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल एस नेता एचडी देवेगौड़ा और नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (टीएमसी), तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन (डीएमके) और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन (झामुमो), डी राजा (भाकपा), सीताराम येचुरी (माकपा) के अलावा तेजस्वी यादव (राजद) ने भी पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।।

विपक्षी नेताओं ने अपने संयुक्त पत्र में कहा कि हम सभी स्टेन स्वामी की हिरासत में मौत पर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त करते हुए आपको गहरी पीड़ा में लिख रहे हैं। हम भारत के राष्ट्रपति के रूप में आपसे तत्काल हस्तक्षेप का आग्रह कर रहे हैं कि आप अपनी सरकार को स्टेन स्वामी पर मुकदमे थोपने, जेल में उनकी निरंतर नजरबंदी और अमानवीय व्यवहार के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दें।

सवाल उठा रहे लोगों को सरकार ने दिया जवाब

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार स्टैन स्वामी की हिरासत में इलाज के दौरान हुई मौत के बाद देश के अंदर राजनीतिक दलों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ संगठनों की ओर से उठाए जा रहे सवाल और आरोपों को सरकार ने कड़े शब्दों में खारिज किया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ और यूरोपीय संघ जैसे मंचों से स्टैन स्वामी की मौत को मानवाधिकार का हनन बताने का खंडन करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने स्पष्ट किया कि स्टैन स्वामी के ऊपर लगे आरोपों की गंभीरता और सबूत को देखते हुए अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।

उनका इलाज एक निजी अस्पताल में डेढ़ महीने से चल रहा था और इसकी निगरानी हाई कोर्ट कर रहा था। बागची ने कहा कि स्टैन स्वामी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने पूरी तरह से कानून का पालन करते हुए गिरफ्तार किया था। उसके बाद स्टैन स्वामी की ओर से विभिन्न अदालतों में जमानत की अर्जी लगाई गई, लेकिन आरोपों की गंभीरता और सुबूतों को देखते हुए अदालतों ने जमानत देने से इन्कार कर दिया।

ध्यान रहे कि उनपर देश में हिंसा फैलाने और प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने का आरोप था। बागची ने कहा कि भारत में संस्थाएं सिर्फ कानून का उल्लंघन होने की स्थिति में ही कार्रवाई करती है। यदि कोई सही तरीके से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती।

भारत में अदालतें स्टैन स्वामी की याचिका को गंभीरता से सुन रही थीं और बांबे हाईकोर्ट ने उनकी सेहत को देखते हुए 28 मई को ही निजी अस्पताल में उनका हर संभव इलाज भी किया जा रहा था। अदालत लगातार उनकी निगरानी भी कर रहा था। इसके बावजूद बीमारी की जटिलताओं के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस घटना को मानवाधिकारों के हनन से जोड़कर देखने वालों को जवाब देते हुए प्रवक्ता ने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रणाली की निगरानी के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका है।

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को सराहा, सेवाभाव की दी सीख

जागरण संवाददाता, चित्रकूट

मंथन

- सात दिवसीय प्रवास के दौरान पहले तीन दिन स्थानीय स्वयंसेवकों के साथ विचार-विमर्श करेंगे
- अखिल भारतीय संघ टोली पदाधिकारी व क्षेत्र प्रचारक एक साथ बैठेंगे

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत नौ जुलाई से शुरू हो रही प्रांत प्रचारक बैठक में शामिल होने के लिए तीन दिन पहले ही मंगलवार को चित्रकूट पहुंच गए। सुबह छह बजे ट्रेन से उतर कर वह सीधे आरोग्यधाम में संघ की शाखा में गए। वहां ध्वज प्रणाम के साथ प्रार्थना की। स्वयंसेवकों को सराहा और सेवाभाव की सीख दी। कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। अब वह सात दिवसीय प्रवास के दौरान पहले तीन दिन स्थानीय स्वयंसेवकों के साथ विचार-विमर्श करेंगे। इसके बाद मुख्य बैठक में शामिल होंगे।

चित्रकूट जिले की सीमा से सटे मध्यप्रदेश के सतना जिले में स्थित दीनदयाल शोध संस्थान (डीआरआइ) के आरोग्यधाम में नौ से 12 जुलाई तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारकों की बैठक है। अखिल भारतीय संघ टोली पदाधिकारी व क्षेत्र प्रचारक एक साथ बैठेंगे, जबकि प्रांत प्रचारक वर्चुअल जुड़ कर अपने कार्यों का आकलन करेंगे। साथ ही आगामी कार्ययोजना को मूर्तरूप देंगे।


चित्रकूट धाम कर्वी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के बाद बाहर निकलते आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। जागरण

दैनिक जागरण
बुधवार 7 जुलाई, 2021
www.jagran.com

न्यूज गैलरी

पुरी के अलावा और कहीं नहीं निकलेगी रथयात्रा

भुवनेश्वर : ओडिशा में जगन्नाथ धाम पुरी के अलावा अन्य जगहों पर रथयात्रा के आयोजन के लिए दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया। पुरी के अलावा राज्य में और कहीं भी रथयात्रा नहीं निकाली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता में गठित खंडपीठ ने इसे खारिज कर दिया है। (जासं)

बंद किए जाएंगे निजी कोविड केयर सेंटर

ओडिशा : ओडिशा के अधिकतर सरकारी और निजी कोविड केयर सेंटर बंद कर दिए जाएंगे। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए केवल कुछ चुनिंदा प्रमुख कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड केयर सेंटर खुले रहेंगे। इसके अलावा कोविड मरीज की नगण्य संख्या वाले कोविड अस्पताल भी बंद किए जाएंगे। (जासं)

तीसरी लहर से निपटने को नौ हजार पीकू बेड तैयार

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए मेडिकल कालेजों से लेकर जिला अस्पतालों तक में पीडियाट्रिक आइसीयू (पीकू) के करीब नौ हजार बेड तैयार किए जा चुके हैं। अब तक 133 आक्सीजन प्लांट शुरू किए जा चुके हैं। (राब्यू)

111 दिन बाद मिले सबसे कम केस

राहत की बात ▶ पिछले 24 घंटे में 34 हजार मामले आए सामने, 553 की मौत

जेएनएन, नई दिल्ली

कोरोना महामारी की दूसरी लहर से तबाह हो चुके देश को अब लगातार राहत मिल रही है। नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है और ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है। 111 दिन बाद 24 घंटे में सबसे कम 34,703 नए केस मिले हैं। 90 दिन बाद सबसे कम 553 लोगों की मौत हुई है और सक्रिय मामले भी 101 दिन में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। बीते 24 घंटे में सक्रिय मामलों में 17,714 कमी आई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना महामारी से हालात लगातार बेहतर हो रहे हैं। उबरने की दर बढ़ रही है और संक्रमण दर कम हो रही है। सक्रिय मामले कुल संक्रमितों का मात्र 1.52 फीसद रह गए हैं। 2.97 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं।



गुजरात के अहमदाबाद में मंगलवार को एक रेलवे स्टेशन पर यात्री का कोरोना टेस्ट के लिए स्वैब सैंपल लेती स्वास्थ्यकर्मी। प्रेट्र

देशभर में कोरोना/वैक्सीन मीटर

भारत

24 घंटे में नए मामले	34,703
कुल सक्रिय मामले	4,64,357
24 घंटे में टीकाकरण	45.82 लाख
अब तक कुल टीकाकरण	35.75 करोड़

मंगलवार सुबह आठ बजे तक कोरोना की स्थिति

नए मामले	34,703
कुल मामले	3,06,19,932
मौतें	553
कुल मौतें	4,03,281
कुल सक्रिय मामले	4,64,357
ठीक होने की दर	97.17 फीसद
पाजिटिविटी दर	2.11 फीसद
मृत्यु दर	1.32 फीसद
जांचें (सोमवार)	16,47,424
कुल जांचें	42,14,24,881

अब 299 रुपये में कराएं आरटी-पीसीआर टेस्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : फ्रांस की कंपनी पाथस्टोर ने मंगलवार को कहा कि उसने भारत में 299 रुपये में कोरोना की आरटी-पीसीआर टेस्ट लांच की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच में यह हो। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि उसकी आरटी-पीसीआर टेस्ट अत्यधिक किफायती होने से पर्यटन, औद्योगिक और रिटेल सेक्टर को बहुत मदद मिलेगी। पाथस्टोर की पैरेंट कंपनी जेनस्टोर के ग्लोबल सीईओ अनुभव अनुषा ने कहा 'हमने पाया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोरोना जांच की राह में आरटी-पीसीआर की ज्यादा कीमत सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए पाथस्टोर ने किफायती कीमत में आरटी-पीसीआर जांच की उपलब्ध कराने का फैसला किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।'

रूसी वैक्सीन स्पुतनिक-वी के उत्पादन की देश में तैयारी पूरी, कच्चे माल का इंतजार

जागरण संवाददाता, सोलन

पैनेशिया बायोटेक कंपनी की बद्दी स्थित इकाई में इस माह के अंत तक रूसी वैक्सीन स्पुतनिक-वी का उत्पादन शुरू हो जाएगा। कंपनी को राज्य दवा नियंत्रक व केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन से इस कोरोना वैक्सीन के उत्पादन का लाइसेंस मिल गया है। अब केवल रूस से स्पुतनिक-वी में इस्तेमाल होने वाले सक्रिय दवा संघटक (एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट, एपीआइ) का इंतजार है। सरल भाषा में कहें तो वैक्सीन के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल का इंतजार है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस सप्ताह के अंत तक एपीआइ पहुंच सकता है।

कुछ दिन पहले पैनेशिया बायोटेक की बद्दी इकाई का राज्य व केंद्र के औषधी नियंत्रक की टीम ने संयुक्त निरीक्षण किया था और सभी सुविधाओं का जायजा लिया। इसके बाद कंपनी को स्पुतनिक-वी के उत्पादन की अनुमति दी गई थी। एपीआइ रूस की ओर से ही मुहैया करवाया जा रहा है। भारत या फिर किसी दूसरे देश में इस वैक्सीन का एपीआइ नहीं मिलता है। पैनेशिया बायोटेक के अधिकारी इसकी आपूर्ति करने के लिए कंपनियों से संपर्क में हैं। एपीआइ यानी कच्चे माल की आपूर्ति होने के बाद ही यह तय होगा कि प्रतिदिन कितनी वैक्सीन का उत्पादन किया जाना है।

उम्मीद

- पैनेशिया बायोटेक कंपनी बद्दी में इसी माह शुरू कर सकती है उत्पादन
- कंपनी को कोरोना वैक्सीन के उत्पादन का मिला है लाइसेंस

इकाई को मिलेगी सुरक्षा

पैनेशिया बायोटेक कंपनी के अधिकारियों की केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों से दिल्ली में बैठक हो चुकी है, जिसमें कंपनी की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई है। बद्दी में भी बीते दिनों हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू आए थे। इस दौरान उन्होंने कंपनी को उचित सुरक्षा मुहैया करवाने का आश्वासन दिया था। पैनेशिया बायोटेक के प्रवक्ता पीडी करन ने बताया कि कंपनी के उच्चस्तर के अधिकारी स्पुतनिक-वी के एपीआइ की आपूर्ति के लिए बात कर रहे हैं।

स्टेरायड के अधिक इस्तेमाल से गल रही हैं हड्डियां

रणविजय सिंह, नई दिल्ली

- एम्स में कोरोना से ठीक हुए चार मरीजों में देखी गई हड्डियों की गंभीर बीमारी
- कोरोना के पहले से स्टेरायड लेने वाले लोगों में देखी जाती रही है कूल्हे की हड्डी गलने की बीमारी

कोरोना से ठीक हुए मरीजों में कई तरह के फंगल संक्रमण होने की बात सामने आ चुकी है। कुछ दिन पहले साइटोमेगालो वायरस का संक्रमण होने की बात भी सामने आई थी। अब कोरोना से ठीक हुए मरीजों में हड्डियां गलने व कमजोर होने की बीमारी देखी जा रही है। एम्स में भी ऐसे चार मरीज देखे जा चुके हैं। एम्स के डाक्टर इसका सबसे बड़ा कारण स्टेरायड का अधिक इस्तेमाल बता रहे हैं। एम्स के आर्थोपेडिक्स विभाग व ट्रामा सेंटर के प्रमुख डा. राजेश मल्होत्रा ने कहा कि कोरोना के पहले से स्टेरायड के अधिक इस्तेमाल के कारण कूल्हे की हड्डी गलने की समस्या से पीड़ित मरीज देखे जाते थे। बुधवार को भी ऐसे तीन मरीजों के कूल्हे बदले जाएंगे, जिन्हें कोरोना नहीं था लेकिन स्टेरायड का इस्तेमाल कर रहे थे।

कई युवा बाडी बिल्डिंग के लिए स्टेरायड युक्त फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। स्टेरायड के अधिक इस्तेमाल से हड्डियों में रक्त संचार प्रभावित होता है। इस वजह से हड्डियों में नया कैल्शियम बनने व पुराने कैल्शियम के हटने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। इस वजह से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इससे पीड़ित को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कोरोना से ठीक होने के बाद एवैस्कुलर नेक्रोसिस से पीड़ित तीन मरीज देखे गए हैं। एक मरीज को बोन मैरो एडिमा की बीमारी थी। बोन मैरो एडिमा की बीमारी में मैरो में सूजन हो जाती है।

इन चारों मरीजों के कूल्हे की हड्डी खराब हो गई थी। उन्होंने कहा कि यह देखा जा रहा है कि कोरोना ठीक होने के बाद भी सीआरपी (सी-रिएक्टिव प्रोटीन) मार्कर देखकर मरीज कई दिनों तक स्टेरायड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि उन्हें सांस लेने या किसी और तरह की शारीरिक परेशानी नहीं होती। इसलिए सिर्फ सीआरपी मार्कर अधिक होने से यह दवा नहीं देनी चाहिए।

कोरोना के बाद फेफड़े गला रहा फंगस, बन रहा है जानलेवा

गंभीर खतरा

ऋषि दीक्षित, कानपुर

अस्पताल में कई दिनों तक भर्ती रहकर कोरोना को मात देने वाले मरीजों की पोस्ट कोविड जटिलताएं लगातार बढ़ रही हैं। पहले जहां आंख, नाक व ब्रेन में ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस के संक्रमण के केस तेजी से बढ़े। वहीं, अब फेफड़े कमजोर होने से उनके टिश्यू एवं सेल्स में एस्परजिलोसिस फंगस के संक्रमण से मवाद (कैविटी) बन रहा है। इससे मरीजों के फेफड़े में बड़ा सा छेद हो जाता है तो कई का आधे से अधिक फेफड़ा ही गल जाता है, जो जानलेवा बन जाता है। ऐसा कम प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी), मधुमेह, लिवर, किडनी और हार्ट के मरीजों में ज्यादा हो रहा है।

कैविटिज निर्माणिया से गंभीर होते हालात : कई बार कैविटी की वजह से बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाता है, जिससे कैविटिज निमोनिया होने लगता है। इससे फेफड़े गलने लगते हैं और स्थिति गंभीर हो जाती है।

केस 01 स्वरूप नगर निवासी 56 वर्षीय व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कई दिनों तक कोविड आइसीयू में भर्ती रहे। ठीक होने के एक माह बाद उन्हें फिर से दिक्कत हुई। उनका शरीर गुब्बारे की तरह फूलने लगा। सर्वोदय नगर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए, जहां कई दिन इलाज चला लेकिन फेफड़े गलने से उन्हें बचाया नहीं जा सका।

केस 02 किदवई नगर निवासी 45 वर्षीय युवक कोरोना पीड़ित होकर कई दिन अस्पताल में वेंटिलेटर पर भी रहे। स्वस्थ होकर घर आने के कुछ दिन बाद ही उनका उठने-बैठने में दम फूलने लगा। दो सप्ताह बाद से खांसी आने लगी। बलगम के साथ खून आने पर डाक्टर को दिखाया। जांच में फेफड़े में छेद का पता चला।

यह हैं लक्षण

कोरोना से उबरने के बाद खांसने में खून आना, सांस फूलना, काला या पीला बलगम आना, शरीर फूलने लगना और अचानक से आक्सीजन सेचुरेशन गिरने लगना।

कोरोना से उबरने के बाद दोबारा भर्ती हुए मरीजों में फेफड़े क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। ऐसे मरीजों के इलाज में सावधानी और लगातार निगरानी जरूरी है। स्टेरायड और वेंटिलेटर पर भी एहतियात से रखा जाए। जरा सी चूक में फेफड़े पूरी तरह फट जाते हैं। ऐसे पीड़ितों की जान बचाना चुनौती से कम नहीं है। इस समस्या के अब तक 12 से अधिक मरीज आ चुके हैं। -डा.एके सिंह, सीनियर पल्मोनोलाजिस्ट एवं क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट।

यह स्थिति और भी घातक

फंगल इंफेक्शन की वजह से फेफड़े में बड़ा छेद बनने पर कई टिश्यू एवं कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने के कारण फेफड़ों में लीकेज होता है, जिससे पूरे शरीर में हवा भर जाती है और शरीर गुब्बारे की तरह फूल जाता है। इस स्थिति को न्यूमो थोरेक्स (फेफड़े में हवा भरना) कहा जाता है। इसमें मरीज की जान बचाना मुश्किल हो जाता है।

भारत में वैक्सीन लांच करने को उत्सुक नहीं दिख रही फाइजर

नई दिल्ली, एएनआइ : अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर भारत में अपनी कोरोना रोधी वैक्सीन लांच करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। भारतीय दवा नियामक की तरफ से फाइजर को इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति के लिए आवेदन करने को दो बार लिखा जा चुका है, लेकिन कंपनी ने अभी तक लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया है।

सूत्रों ने बताया कि सरकार लगातार फाइजर के संपर्क में बनी हुई है, लेकिन विशेष रूप से कानूनी दायित्व के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

गौरतलब है कि फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बौरला ने जून में ही कहा था कि भारत में कोरोना वैक्सीन की मंजूरी के लिए बातचीत अंतिम दौर में है। इस बीच, दूसरी अमेरिकी दवा कंपनी माडर्ना की कोरोना वैक्सीन के इस हफ्ते भारत पहुंच जाने की संभावना है। माडर्ना की यह वैक्सीन मेसेंजर आरएनए (एमआरएनए) आधारित है। पिछले हफ्ते भारत के दवा महानियंत्रक ने सिप्ला को माडर्ना की वैक्सीन का आयात करने की अनुमति दे दी थी।

21 जून से 15 दिन में लगे 7.75 करोड़ टीके

नई दिल्ली, एएनआइ : देश में 21 जून से शुरू हुए कोरोना टीकाकरण महाभियान के 15 दिन में ही 7.75 करोड़ टीके लगाए गए हैं। महाभियान में रोजाना औसतन 50 लाख से अधिक डोज लगाई जा रही हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मंगलवार सुबह सात बजे तक कोरोना रोधी वैक्सीन की कुल 35.75 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। 20 दिन का यानी महाभियान शुरू होने से ठीक पहले तक 28 करोड़ डोज लगाई गई थीं। पिछले 24 घंटे में 45.82 लाख से ज्यादा डोज दी गई हैं। मंत्रालय के मुताबिक लाभार्थियों में सबसे ज्यादा 18-44 आयुवर्ग के 10.28 करोड़ लोगों को टीके की पहली डोज दी गई है, जबकि 29.28 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। 45-60 आयुवर्ग के 9.12 करोड़ लोगों को पहली और 1.99 करोड़ लोगों को दूसरी डोज भी लगाई दी गई है। वहीं, 60 साल से अधिक उम्र के 6.92 करोड़ को पहली और 2.64 करोड़ लोगों को दूसरी डोज लगाई गई है।

राष्ट्रीय फलक

चारधाम यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार

उत्तराखंड : आदेश को चुनौती

राज्य ब्यूरो, देहरादून

उत्तराखंड के तीन जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के स्थानीय निवासियों के लिए, एक जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने के निर्णय पर हाई कोर्ट की रोक के आदेश को प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मंगलवार को इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई। सरकार की ओर से नामित अधिवक्ता वंशजा शुक्ला ने इसकी पुष्टि की।

चारधाम यात्रा का धार्मिक महत्व होने के साथ ही यह प्रदेश की आर्थिकी से भी जुड़ी है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार ने 14 मई से होने वाली चारधाम यात्रा स्थगित कर दी थी। कोरोना संक्रमण के मामले घटने पर पिछली तीरथ कैबिनेट ने चरणबद्ध ढंग से यात्रा शुरू करने का फैसला लिया। इसके तहत प्रथम चरण में एक जुलाई से चारधाम वाले तीन जिलों के स्थानीय निवासियों को कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट के साथ अपने-अपने जिले के धामों में दर्शन की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। इसके बाद 11 जुलाई से सभी जिलों और फिर कोविड की स्थिति की समीक्षा कर अन्य राज्यों के लिए यात्रा खोलने पर सहमति बनी थी। विस्तृत मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) बनाने के निर्देश दिए। इस क्रम में प्रस्तुत की गई एसओपी को कोर्ट ने अस्वीकार करने के साथ ही चारधाम यात्रा शुरू करने के कैबिनेट के फैसले पर रोक लगाने के आदेश पारित किए। सरकार ने कोर्ट के आदेश के मद्देनजर चारधाम यात्रा का निर्णय स्थगित कर दिया था। साथ ही हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला लिया था, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम के कारण इसमें देरी हुई।

याचिका में सरकार ने तर्क दिया है कि कोविड की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए चरणबद्ध ढंग से यात्रा शुरू करने के मद्देनजर सभी पुख्ता व्यवस्था की गई है। चारधामों में यात्रियों के लिए यात्रियों की कम संख्या निर्धारित की गई है तो यात्रा के लिए कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करने का निश्चय किया गया है। यह भी कहा गया है कि चारधाम यात्रा से स्थानीय निवासियों की आजीविका से भी जुड़ी हुई है। जो छह माह खाली रहते हैं और यात्रा के दौरान ही वह वर्षभर के लिए कमाई करते हैं।

कांवड़ यात्रा को लेकर नए सिरे से विचार

राज्य ब्यूरो, देहरादून

कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार नए सिरे से विचार करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश व अन्य पड़ोसी राज्यों से बात कर इस पर अंतिम फैसला किया जाएगा। इधर, कांवड़ यात्रा से जुड़े राज्यों के पुलिस अधिकारियों की साझा बैठक में मौजूदा परिस्थितियों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। पिछली तीरथ सरकार के कांवड़ यात्रा स्थगित रखने के फैसले के क्रम में यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक में फिलहाल कांवड़ यात्रा स्थगित रखने पर सहमति बनी। आगे जो भी स्थितियां बनेंगी, उसी अनुरूप निर्णय किया जाएगा।

प्रदेश में हर साल सावन के दौरान कांवड़ यात्रा होती है। इस पर अभी कोरोना का साया है। पिछले साल भी कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कांवड़ यात्रा स्थगित की गई थी। इस बार परिस्थितियां पिछले साल से ज्यादा खराब हैं। साथ ही कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। इसे देखते हुए इस बार भी कांवड़ यात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया। अब यात्रा को लेकर एक बार फिर नए सिरे से विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते रोज कांवड़ यात्रा के संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की।

अन्नपूर्णा मंदिर के महंत रामेश्वरपुरी की हालत गंभीर, योगी ने जाना हाल

जागरण संवाददाता, वाराणसी

उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को फोन पर अन्नपूर्णा मंदिर के महंत रामेश्वरपुरी के स्वास्थ्य की जानकारी ली। दोपहर 3:45 बजे उपमहंत शंकरपुरी के मोबाइल पर उनकी काल आई। उन्होंने पूरी स्थिति जानने-समझने के बाद कहा, मेदांता अस्पताल के निदेशक से बेहतर इलाज के लिए तत्काल बात करता हूं, आप बिल्कुल चिंता न करें। किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ने पर निस्संकोच फोन करें, तुरंत मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि समय मिलते ही मैं महंत जी से मिलने अस्पताल आऊंगा। इसके करीब एक घंटे बाद धर्मार्थ कार्य मंत्री डा. नीलकंठ तिवारी ने फोन कर महंत का हाल-चाल जाना।

मेदांता अस्पताल के निदेशक दीपक कपूर ने बताया कि महंत रामेश्वरपुरी की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। स्वास्थ्य में कुछ खास सुधार नहीं हो रहा है। मंगलवार को एक बार फिर एमआरआइ करवाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़े और किडनी सिर्फ 20 फीसद ही काम कर रहे हैं। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डा. दिलीप दुबे की टीम बराबर उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। महंत रामेश्वरपुरी गत 11 जून से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। वे 30 जून से वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं।

आज शाम तक काशी आ जाएंगे महंत रामेश्वरपुरी

सूत्रों के मुताबिक महंत रामेश्वरपुरी की इच्छा रही है कि वह अंतिम सांस काशी में ही लें। उनकी इच्छा के मुताबिक मंगलवार को आई एमआरआइ रिपोर्ट के आधार पर बुधवार को दोपहर उनको मेदांता अस्पताल से वेंटीलेटरयुक्त एंबुलेंस से वाराणसी लाया जाएगा। यहां उनको महमूरगंज स्थित एक निजी अस्पताल में वेंटीलेटर पर रखा जाएगा।

मैक्स सर्विसेज के पार्टनर ने वापस ली याचिका

जासं, नैनीताल : हाई कोर्ट ने कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़ा मामले में आरोपित मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज के सर्विस पार्टनर शरद पंत व मल्लिका पंत की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि मामले में कुछ तथ्य नए सामने आए हैं, लिहाजा उन्हें याचिका वापस लेने व दूसरी याचिका को पेश करने की अनुमति दी जाए। इस पर कोर्ट ने अनुमति दे दी है।

मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनएस धानिक की एकलपीठ में मैक्स के पार्टनर शरद पंत व मल्लिका पंत की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया था कि वह मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेस में एक सर्विस प्रोवाइडर है। परीक्षण और डाटा प्रविष्टि के दौरान मैक्स कॉर्पोरेट का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। परीक्षण और डाटा प्रविष्टि का सारा काम स्थानीय स्वास्थ्य विभाग व सरकार के अधिकारियों की प्रत्यक्ष निगरानी में किया गया था। इन अधिकारियों ने परीक्षण स्टालों में जो कुछ भी किया था, उसे मंजूरी दी थी।

राजस्थान की एक महिला के दो गर्भाशय और दो योनि

संवाद सूत्र, अजमेर

राजस्थान में नागौर जिले के थांवला कस्बे में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज कराने आई एक महिला के शरीर में एक नहीं बल्कि दो गर्भाशय और दो योनि की जानकारी सामने आई है। इस जानकारी के बाद चिकित्सक भी हैरान हैं। शरीर की इन जटिलताओं के चलते महिला का दो माह का गर्भपात हो गया। अपने शरीर के अतिरिक्त अंगों की जानकारी महिला को भी चिकित्सकों द्वारा कराई गई सोनोग्राफी के बाद पता चली।

स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. प्रकाश चौधरी से मिली जानकारी के अनुसार कस्बे के समीप रहने वाली 22 वर्षीय एक महिला गर्भकाल के दो माह गुजरने के बाद रविवार को राजकीय अस्पताल में इलाज कराने के लिए आई। रक्तस्राव से पीड़ित महिला को चिकित्सक ने सोनोग्राफी कराने की सलाह दी। सोनोग्राफी से पता चला कि महिला के दो गर्भाशय और दो योनि हैं। इसके बाद डा. प्रकाश चौधरी ने अपने वरिष्ठ चिकित्सकों और अजमेर के स्त्री रोग विशेषज्ञों से संपर्क कर इस मामले की जटिलताओं के बारे में उनसे विमर्श किया। सभी ने सोनोग्राफी दोबारा कराने की बात कही। इसके बाद महिला को अजमेर भेजकर दोबारा से सोनोग्राफी कराई गई। अजमेर में भी उसके शरीर में योनि की संख्या दो ही देखी गई। दो गर्भाशय भी दिखे।

देश में ऐसा पहला मामला : चिकित्सकों के अनुसार देश में ऐसा पहला मामला है, जब किसी महिला के शरीर में दो योनि व दो गर्भाशय पाए गए हों। इससे पहले अमेरिका में अलग-अलग समय में दो ऐसे मामले सामने आए थे। डा. चौधरी ने बताया कि इस प्रकार की शारीरिक जटिलता को यूट्रस डिडेल्फिस के नाम से जाना जाता है।

योग, आयुर्वेद से गंभीर बीमारियों का स्थायी इलाज संभव : स्वामी रामदेव

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

- एलोपैथी पर फिर किया कटाक्ष, कहा-ड्रग्स इंडस्ट्री द्वारा तैयार सिलेबस पढ़ रहे डाक्टर

देश के अलावा विदेश में योग को ऐसे ही नहीं अपनाया गया। लाइलाज बीमारियों का इलाज भी योग और आयुर्वेद से संभव हो सकता है। हरिद्वार में पतंजलि तीन हजार बेड का अस्पताल बना रहा है। जो अब तक का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। पतंजलि का लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को योग का महत्व बताकर उसको योग से जोड़ा जाए। हमारा उद्देश्य रोगी को सही करना ही नहीं, रोग को पूरी तरह खत्म करना भी है। यह बातें स्वामी रामदेव ने मंगलवार को गाजियाबाद के मोदीनगर में पतंजलि योगपीठ के उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कहीं। एलोपैथी पर कटाक्ष करते हुए स्वामी रामदेव ने कहा कि ड्रग्स इंडस्ट्री द्वारा तैयार किया गया सिलेबस डाक्टरों को पढ़ाया जा रहा है। इसी वजह से ड्रग्स को इतना बढ़ावा मिल रहा है। यदि यह उपचार आयुर्वेद से किया जाए तो रोग को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। इससे स्थायी उपचार संभव है।

गिलोय, नीम से नुकसान नहीं

स्वामी रामदेव ने गिलोय व नीम के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के दावे का पूरी तरह खंडन किया। कहा कि गिलोय व नीम बहुत प्रभावी जड़ी बूटी है। इसका शरीर में कोई भी नुकसान नहीं है। इसका दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पतंजलि बनाएगा तीन हजार बेड का सबसे बड़ा अस्पताल

जासं, गाजियाबाद : 'देश-विदेश में योग को ऐसे ही नहीं अपनाया गया। लाइलाज बीमारियों का इलाज भी योग और आयुर्वेद से संभव हो सकता है। एलोपैथी ने जहां अपने हाथ खड़े कर दिए। वहां योग कारगर साबित हुआ। हरिद्वार में पतंजलि तीन हजार बेड का एक विशाल अस्पताल बना रहा है, जो अब तक का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। पतंजलि का लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को योग का महत्व बताकर उसको योग से जोड़ा जाए। हमारा उद्देश्य रोगी को सही करना ही नहीं है बल्कि रोग को पूरी तरह खत्म करना है।' ये बातें स्वामी रामदेव मंगलवार को गाजियाबाद के सीकरी कलां स्थित पतंजलि योगपीठ के उद्घाटन कार्यक्रम में कहीं।

डाक्टर के फेफड़े प्रत्यारोपित कराने को योगी ने जारी किए डेढ़ करोड़

जागरण संवाददाता, लखनऊ

कोरोना संक्रमितों का इलाज करते समय वायरस की चपेट में आने वाली डाक्टर के लिए उप्र के मुख्यमंत्री ने सराहनीय कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोहिया संस्थान (लखनऊ) की महिला रेजिडेंट के फेफड़ों को प्रत्यारोपित कराने के लिए डेढ़ करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है।

लोहिया संस्थान की 31 वर्षीय रेजिडेंट डा.शारदा सुमन कोविड ड्यूटी करने के दौरान संक्रमित हो गई थीं। इसके बाद डाक्टरों ने उन्हें फेफड़ों को प्रत्यारोपित कराने की सलाह दी थी, मगर खर्च अधिक होने से स्वजन की उम्मीदें धूमिल होने लगी थीं, ऐसे समय में मुख्यमंत्री की उदारता ने जीवन की नई उम्मीद जगाई है।

फिलहाल, डा.शारदा सुमन लोहिया संस्थान के कोविड अस्पताल में पिछले 45 दिनों से इक्मो मशीन के सपोर्ट पर जीवन से संघर्ष कर रही हैं। 14 अप्रैल को जब वह संक्रमित हुई थीं तो आठ माह की गर्भवती थीं। 19 अप्रैल को तबीयत गंभीर होने पर अस्पताल में भर्ती कराई गईं। एक मई को आपरेशन कर उनकी डिलीवरी कराई गई। संस्थान के प्रवक्ता डा.श्रीकेश सिंह ने बताया कि डा.शारदा ने एक बच्ची को जन्म दिया है, जो स्वस्थ है।

तीन दिन में जारी हुई धनराशि : मूलरूप से बिहार की आरा जिले की निवासी डा. शारदा सुमन के पति भी बिहार में रेजिडेंट हैं। हाल ही में उनकी शादी हुई थी। इतनी धनराशि खर्च करने में वह सक्षम नहीं थे। चिकित्सा अधीक्षक डा. विक्रम सिंह ने बताया कि निदेशक डा. सोनिया नित्यानंद के साथ सीएम से मुलाकात कर डा. शारदा की जान बचाने के लिए फेफड़े के प्रत्यारोपण का विकल्प बताया। तीन दिन में ही धनराशि जारी हो गई।

पेटीएम के बोर्ड में अब कोई चीनी नागरिक नहीं

नई दिल्ली : डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम के निदेशक बोर्ड से सभी चीनी नागरिक बाहर हो गए हैं। चीन के नागरिकों की जगह पेटीएम के बोर्ड में अमेरिकी और भारतीयों को जगह दी गई है। अलीपे के प्रतिनिधि जिंग शिआनडांग, एंट फाइनेंशियल्स के प्रतिनिधि गुओमिंग चेंग तथा अलीबाबा के प्रतिनिधि माइकल युएन जेन याओ (अमेरिकी नागरिक) व टिंग हांग केनी अब पेटीएम के निदेशक बोर्ड का हिस्सा नहीं हैं। (प्रेट्र)



गेहूं उत्पादों की खपत पद्धति में विविधीकरण की काफी गुंजाइश है। उद्योग जगत इसके निर्यात उत्पादों पर फोकस कर काफी लाभ कमा सकता है।
— रमेश चंद, सदस्य, नीति आयोग

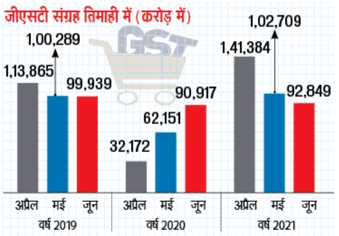
सेंसेक्स	52,861.18	▼ 18.82
निफ्टी	15,818.25	▼ 16.10
सोना प्रति दस ग्राम	₹46,762	▲ ₹389
चांदी प्रति किलोग्राम	₹69,105	▲ ₹397
डॉलर	₹74.55	▲ ₹0.24
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 77.46	

आठ महीने बाद जीएसटी संग्रह की रकम एक लाख करोड़ रुपये से कम

इसके बावजूद पहली तिमाही संग्रह पिछले दो वर्षों की समान अवधि से अधिक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कोरोना की दूसरी लहर की वजह से इस वर्ष जून का जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से कम रहा। यह पिछले आठ महीनों में सबसे कम जीएसटी संग्रह है। जून में जीएसटी का संग्रह 92,849 करोड़ रुपये रहा।

हालांकि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2021) में 3,36,987 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह किया गया, जो कोरोना के पहले के दो वित्त वर्षों की समान अवधि में हासिल रकम के मुकाबले अधिक है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही का जीएसटी संग्रह वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के मुकाबले लगभग सात फीसद ज्यादा है। इस अवधि में 3,14,093 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह हुआ था। पिछले वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से मात्र 1,85,240 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह हो पाया था।



मंगलवार को वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष जून में सीजीएसटी का संग्रह 16,429 करोड़ रुपये रहा। एसजीएसटी 20,397 करोड़ रुपये तो आइजीएसटी के रूप में 49,079 करोड़ रुपये का संग्रह किया गया। सेस के रूप में 6,949 करोड़ रुपये की वसूली की गई। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस वर्ष जून का जीएसटी संग्रह पिछले वर्ष जून के मुकाबले दो फीसद अधिक है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक यह आंकड़ा पांच जून से पांच जुलाई का है क्योंकि कोरोना की वजह से करदाताओं को जीएसटी भुगतान और आइटीआर फाइल करने की समय सीमा में मोहलत दी गई थी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस वर्ष जून का जीएसटी संग्रह मुख्य रूप से मई में किए गए कारोबारी ट्रांजेक्शन का है।

मई में अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन जैसी स्थिति होने का असर जीएसटी संग्रह पर दिखा है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 20 जून के बाद ईवे बिल में अच्छी बढ़ोतरी हुई है और जुलाई के जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी की पूरी संभावना है। आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष मई में 3.99 करोड़ ईवे बिल जारी किए गए थे। जून में यह आंकड़ा बढ़कर 5.5 करोड़ हो गया है। इसका मतलब यह है कि जुलाई के जीएसटी संग्रह आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहने के संकेत हैं।

कोरोना काल में विनिवेश पर सोचने को मजबूर कंपनियां

मुंबई, प्रेट्र: कोरोना महामारी के कारण कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर व्यापक दुष्प्रभाव पड़ा है। कई कंपनियों के सामने अपने नॉन-कोर एसेट्स में विनिवेश की स्थिति भी आ गई है। कंसल्टेंसी फर्म ईवाई के सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है।

वार्षिक सर्वे में ईवाई ने बताया कि वित्तीय संकट के कारण तीन चौथाई कंपनियां अपने नॉन-कोर एसेट बेचने के बारे में सोचने पर मजबूर हुई हैं। महामारी के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था में 7.3 फीसद की गिरावट आई है। दूसरी लहर के कारण चालू वित्त वर्ष में भी अर्थव्यवस्था में दोहरे अंकों में बढ़त की उम्मीद नहीं लग रही है, जैसा पहले अनुमान लगाया जा रहा था। सर्वेक्षण में शामिल 73 फीसद कंपनियों ने बताया कि वे अगले दो साल में कुछ परिसंपत्तियों को बेचने पर विचार कर रही हैं, क्योंकि कारोबारी जरूरतों के लिए उनके पास पूंजी का संकट पैदा हो गया है। समय पर इस विनिवेश से कंपनियों को जरूरी फंड मिल सकेगा, जिससे उन्हें कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

'जेट कर्मचारी साथ दें, हम देंगे नकद, लैपटॉप, आइपैड'

नई दिल्ली, प्रेट्र : बंद पड़ी निजी एयरलाइन जेट एयरवेज की समाधान योजना जीतने वाले जालान-कालरॉक कंसोर्टियम ने कंपनी के पुराने कर्मचारियों को अपने पक्ष में करने के लिए तरह-तरह के ऑफर दिए हैं। कंपनी ने कहा है कि अगर कर्मचारी बोली जीतने वाले कंसोर्टियम का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें मोबाइल फोन, लैपटॉप, आइपैड, मुफ्त टिकट समेत नकद राशि भी दी जाएगी। लेकिन इसके लिए कम से कम 95 फीसद कर्मचारियों को कंसोर्टियम का प्रस्ताव स्वीकार करना होगा। कंसोर्टियम ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के समक्ष पेश समाधान योजना में ही ये पेशकश शामिल किए हैं।

जेट एयरवेज के लिए जालान-कालरॉक कंसोर्टियम की समाधान योजना पर कंपनी के कर्मचारियों और कामगारों की तरफ से वोटिंग की प्रक्रिया पांच जुलाई को शुरू हो गई। यह प्रक्रिया चार अगस्त तक चलेगी। एनसीएलटी ने 22 जून को जेट एयरवेज के लिए यूएई-स्थित कारोबारी मुरारी लाल जालान और ब्रिटेन की कंपनी कालरॉक के कंसोर्टियम द्वारा पेश समाधान योजना को मंजूरी दे दी थी। कंसोर्टियम को यह मंजूरी कुछ शर्तों के साथ दी गई है। समाधान योजना के तहत 20 जून, 2019 की तिथि को जेट एयरवेज के जितने भी कर्मचारी और कामगार थे, कंसोर्टियम उन्हें कुछ विशेष ऑफर करेगा। उस तिथि को इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू हुई थी। कंसोर्टियम ने कहा, उस तिथि से पहले तत्कालीन जेट एयरवेज के जितने भी कर्मचारियों व कामगारों का जो भी बकाया था, उसका भुगतान समाधान योजना के तहत ही होगा। लेकिन उसकी यह पेशकश उससे अलग है।



नए कंसोर्टियम ने कहा – कंपनी के 95 फीसद कर्मचारियों को देनी होगी समाधान योजना को मंजूरी

दो दिनों की बढ़त के बाद बाजारों में सुस्ती

मुंबई, प्रेट्र: पिछले सप्ताह शुक्रवार और इस सप्ताह सोमवार के उछाल के बाद मंगलवार को घरेलू शेयर बाजारों में थोड़ी सुस्ती देखी गई। दिग्गज शेयरों में मुनाफावसूली और प्रमुख सेक्टरों से निवेशकों की बेरुखी के चलते बीएसई का 30-शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स मंगलवार को 18.82 अंक यानी 0.04 फीसद फिसलकर 52,861.18 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50-शेयरों वाला निफ्टी 16.10 अंकों यानी 0.1 फीसद की गिरावट के साथ 15,818.25 पर स्थिर हुआ।

मंगलवार को शेयर बाजारों में कारोबार की शुरुआत सकारात्मक स्तर पर हुई थी। लेकिन वह गति बरकरार नहीं रख पाया। सेंसेक्स पैक में सबसे अधिक 2.30 फीसद की गिरावट टेक महिंद्रा के शेयरों में दर्ज की गई। टीसीएस, मारुति सुजुकी, आरआइएल, सन फार्मा, इन्फोसिस व महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर भी लाल निशान पर बंद हुए। दूसरी तरफ अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, कोटक महिंद्रा बैंक तथा इंडसइंड बैंक के शेयर मजबूत हुए।

असंगठित क्षेत्र के कारोबारियों को सिडबी देगा सस्ता कर्ज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : फिनटेक (फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी) की मदद से असंगठित क्षेत्र के कारोबारियों को सस्ता लोन देने की तैयारी चल रही है। इस दिशा में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने पहल की है। कर्ज की मात्रा के लिए डिजिटल माध्यम व फिनटेक के इस्तेमाल से उन कारोबारियों के टर्नओवर और उनके रोजाना के कारोबार की जानकारी ली जाएगी।

सिडबी के सीएमडी एस. रमन के मुताबिक बैंक बड़ी रिटेल चेन को सप्लाई देने वाले छोटे-छोटे कारोबारियों को लोन देगा। इस दिशा में उन्होंने बिग बास्केट जैसी ऑनलाइन चेन के साथ करार किया है। रमन के मुताबिक बिग बास्केट में विभिन्न चीजों की सप्लाई देने वाले सैकड़ों ऐसे छोटे कारोबारी हैं जिनके लोन का कोई आधार नहीं है। ऐसे कारोबारियों को स्थानीय कर्जदाताओं से ऊंची दरों पर कर्ज लेना पड़ता है। कई बार ऐसे कर्ज की दर 40% तक होती है। सिडबी ऐसे कारोबारियों को 14-18% तक की दर से लोन देने की कोशिश कर रहा है। सिडबी की तरफ से लोन के अप्लाई के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसपर मात्र 25 मिनटों में लोन की प्रोसेसिंग हो सकती है। इस प्लेटफॉर्म पर अन्य बैंक को भी लाया गया है। प्लेटफॉर्म पर लोन आवेदन मिलने के बाद वहां मौजूद अन्य बैंक भी उन्हें लोन की पेशकश कर सकते हैं। रमन के मुताबिक छोटे कारोबारियों को संगठित लोन के दायरे में लाने को फिनटेक की मदद ली जा रही है।

विशेषज्ञों के मुताबिक छोटे-छोटे दुकानदार से लेकर रेहड़ी वाले तक लेनदेन में विभिन्न डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल करते हैं।

एनएमडीसी ने सरकार का भरोसा बढ़ाया

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकारी कंपनी एनएमडीसी के ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) ने विनिवेश प्रक्रिया की सफलता को लेकर सरकार का भरोसा बढ़ा दिया है। एनएमडीसी में सात फीसद शेयर बिक्री को मंगलवार को पहले दिन अच्छी प्रतिक्रिया मिली।

संस्थागत निवेशकों ने 3,700 करोड़ रुपये से अधिक की बोलियां लगाई हैं। निवेशकों के लिए 10.55 करोड़ से अधिक शेयर बिक्री पेशकश के तहत रखे गए हैं। निवेशकों ने मंगलवार को 22.55 करोड़ शेयर के लिए लगाई हैं। एनएसई पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक सांकेतिक मूल्य 166.46 रुपये पर संस्थागत निवेशकों की बोलियां 3,753 करोड़ से अधिक है। खुदरा निवेशकों के लिए बिक्री पेशकश बुधवार को खुलेगी। सरकार 165 रुपये के न्यूनतम मूल्य पर सार्वजनिक क्षेत्र की खनन कंपनी एनएमडीसी में 21.95 करोड़ शेयर या 7.49% हिस्सेदारी बेच रही है।

नया आइटी पोर्टल जल्द होगा दुरुस्त : अनुराग ठाकुर

नई दिल्ली, एएनआइ : वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने आश्वस्त किया है कि सात जून को लांच किए गए नए आइटी पोर्टल की दिक्कतें जल्द ठीक कर ली जाएंगी। वित्त राज्यमंत्री के अनुसार पोर्टल बनाने वाली कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड और आयकर विभाग के अधिकारियों का दल तकनीकी दिक्कतों को दुरुस्त करने में पूरी तरह जुटा हुआ है। उन्होंने इन्फोसिस से भी आग्रह किया कि सभी तकनीकी दिक्कतों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए।

ठाकुर ने मंगलवार को कहा, 'कुछ दिनों पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इन्फोसिस के अधिकारियों की बैठक हुई थी। इस बैठक में उन्होंने कंपनी के अधिकारियों को नए आइटी पोर्टल की सभी दिक्कतों को यथाशीघ्र दूर करने का निर्देश दिया था। आयकर विभाग के अधिकारी तब से इन्फोसिस के दल के साथ लगातार संपर्क में हैं। उनके बीच नए आइटी पोर्टल की सभी दिक्कतें जल्द से जल्द खत्म करने के लिए रोजाना कम से कम दो घंटे विमर्श हो रहा है।'

इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने नए आइटी पोर्टल में आ रही दिक्कतों को लेकर केंद्र पर तीखा प्रहार किया था। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से कहा कि 4,200 करोड़ खर्च करने के बाद भी सरकार को इच्छित परिणाम नहीं मिल सके हैं और आम करदाताओं के लिए यह पोर्टल मुसीबत बन गया है। उल्लेखनीय है कि पुराने आइटी पोर्टल की चुनिंदा दिक्कतें दूर करने तथा उसे करदाताओं के लिए बेहद आसान बनाने के मकसद से केंद्र सरकार ने नया आइटी पोर्टल विकसित कराया है।

डीएचएफएल मामले में कर्जदाताओं और पीरामल को नोटिस

नई दिल्ली, प्रेट्र : नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनक्लैट) ने कर्ज के बोझ तले दबी डीएचएफएल व इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत समाधान योजना जीतने वाली पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस को नोटिस भेजा है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) की समाधान प्रक्रिया पर 63 मून्स टेक्नोलॉजीज ने सवाल उठाए थे। एनक्लैट की दो सदस्यीय पीठ ने डीएचएफएल के कर्जदाताओं और पीरामल कैपिटल को सुनवाई की अगली तारीख 19 जुलाई से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है।

उल्लेखनीय है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनक्लैट) ने डीएचएफएल के लिए पीरामल कैटिपल होल्डिंग्स द्वारा पेश समाधान योजना को सात जून को मंजूरी दे दी थी। इसके खिलाफ 63 मून्स ने याचिका दायर की हुई है।

कच्चे तेल के लिए नए बाजारों पर केंद्र सरकार की नजर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में अभी अस्थिरता को देखते हुए भारत ओपेक से अलग देशों से कच्चा तेल खरीदने पर जोर दे रही है। इस क्रम में अगले कुछ दिनों में भारत गुयाना से पहली बार तेल की खेप आने वाली है। भारत अफ्रीका के कुछ ऐसे देशों पर भी नजर बनाए हुए है जहां हाल ही में तेल उत्पादन शुरू हुआ है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव तरुण कपूर ने दैनिक जागरण को बताया, हम बाजार की स्थिति को देखते आपूर्तिकर्ताओं की संख्या बढ़ा रहे हैं। सरकारी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल की तरफ से गुयाना से खरीदा गया क्रूड कुछ ही दिनों में भारत पहुंच जाएगा। तेल कंपनी एचईएमएल भी वहां से तेल खरीद रही है। निजी क्षेत्र की एक दूसरी तेल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज वेनेजुएला से तेल खरीद रही है।



ओपेक के बाहर अन्य उत्पादकों से ज्यादा तेल खरीदने की योजना • फाइल फोटो

कपूर ने बताया, कई देशों में नए तेल भंडारों की खोज हो रही है जहां से तेल खरीदने को लेकर हम विशेष प्रयास कर रहे हैं। यूरोपीय देश नॉर्वे भी इसमें शामिल है। भारत अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब, इराक, ईरान व अमेरिका से खरीदता रहा है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध के बाद वहां से खरीद अभी नहीं हो रही है। अमेरिका से चार वर्ष पहले भारत ने तेल खरीदना शुरू किया। वह अब भारत को सबसे ज्यादा क्रूड बेचने वालों में पांचवें स्थान पर है।

राष्ट्रीय फलक

न्यूज गैलरी

13 साल से छिप रहा पूर्व आतंकी गिरफ्तार

किश्तवाड़ : जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को एक पूर्व आतंकी को गिरफ्तार किया है। वह पिछले 13 साल से गिरफ्तारी से बच रहा था। पूर्व आतंकी नईम अहमद किश्तवाड़ जिले की पाडर तहसील के गांव टटानी का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार उस पर 13 साल पहले आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। (जासं)

एक लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार

दंतेवाड़ा : जिले कटेकल्याण थाना के पुलिस बल और डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड गार्ड (डीआरजी) की संयुक्त टीम गुड़से गीदम के जंगलों में सर्चिंग पर निकली हुई थी, तभी जवानों को देखकर एक नक्सली भागने लगा। इस दौरान जवानों की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उनकी पहचान पांडु मुचाकी के रूप में हुई। उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था। उस पर कटेकल्याण थाना में सात मामले नामजद है। (नईदुनिया)

देशमुख के सहयोगियों को 20 तक न्यायिक हिरासत में भेजा

मुंबई : विशेष पीएमएलए अदालत ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के दो सहयोगियों को सौ करोड़ रुपये की उगाही से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में 20 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 26 जून को देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को गिरफ्तार किया था। (प्रेट्र)

जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाली याचिका पर समन

अहमदाबाद : गुजरात हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता सुरेश कटारा की तरफ से दाखिल एक याचिका पर भाजपा विधायक निमिषा सुथार व निर्वाचन आयोग को समन जारी किया है। कटारा ने मोरवा हड़प की विधायक सुथार के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती दी है। जस्टिस निखिल एस. करील ने लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत समन जारी करते हुए उन्हें दो अगस्त को अदालत के समक्ष उपस्थित होने को कहा है। (प्रेट्र)

शर्लाक होम्स का जिक्र कर सुप्रीम कोर्ट ने हत्या मामले में फैसला बरकरार रखा

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने शर्लाक होम्स के कथन, आप देखते हैं लेकिन आप ध्यान नहीं देते को उद्धृत करते हुए हत्या के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने और उम्रकैद की सजा के खिलाफ की गई अपील को खारिज कर दिया।

शीर्ष अदालत ने एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) की इस दलील को खारिज कर दिया कि चार चश्मदीद गवाहों के लिए रात में हत्या करने वाले व्यक्ति का चेहरा देखना संभव नहीं था। जस्टिस आरएफ नरीमन, केएम जोसेफ और बीआर गवई की पीठ ने सोमवार को पारित अपने आदेश में कहा कि हमें हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं लगता है। इसके अनुसार विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।

सुनवाई के दौरान मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त किए गए अधिवक्ता पीयूष कांति राय ने कहा, सुनसान जगह और अंधेरी रात थी और मामले के चार चश्मदीद गवाह याचिकाकर्ता का चेहरा नहीं देख सकते थे। इस पर जस्टिस नरीमन ने कहा,यह ऐसा है जैसे शर्लाक होम्स ने डा.वाटसन से कहा, आप देखते हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं देते। राय ने कहा कि उनका एकमात्र प्रयास यह है कि एक निर्दोष को उस अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए जो उसने नहीं किया है। इस पर पीठ ने कहा,आप ऐसी चीज पर चर्चा कर रहे हैं जिस पर पहले ही बहस हो चुकी है। आपने एमिकस क्यूरी से बढ़कर ड्यूटी निभाई है।

शीर्ष अदालत मुकेश द्वारा दाखिल अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की थी। निचली अदालत ने मुकेश को उसके गांव के गोपाल लाल की 18 जुलाई 2012 को हत्या के लिए दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा दी थी। राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर जेल में बंद मुकेश की याचिका खारिज कर दी थी। मुकेश ने अपनी अपील में दलील दी कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 302 के तहत कोई मामला नहीं बनता। अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 जुलाई 2012 को बाबूलाल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका छोटा भाई 18 जुलाई 2012 को रात करीब 10-11 बजे भानपुर से अपने गांव आ रहा था, तभी ग्रामीणों ने उसे सूचना दी कि गोपाल लाल को तीन लोगों ने पीटा था। मौके पर पहुंचा तब तक उनके भाई को मार डाला था।

कौन हैं शर्लाक होम्स

ब्रिटिश उपन्यासकार सर आर्थर कानन डायल के काल्पनिक पात्र शर्लाक होम्स को लंदन के जटिल आपराधिक मामलों को सुलझाने में महारत थी। डा. वाटसन उनके मित्र थे। विक्टोरिया काल की पृष्ठभूमि पर लिखे गए उपन्यासों के इन दोनों काल्पनिक पात्रों की एक दौर में बहुत धूम रही है। शर्लाक के चाहने वालों को उनका काल्पनिक पता 221बी बेकर स्ट्रीट, लंदन आज भी याद होगा।

'यूएई जासूसी' मामले में केरल हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

कोच्चि, प्रेट्र : केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक महिला की तरफ से दाखिल याचिका पर केंद्र से उसका रुख स्पष्ट करने को कहा है। याचिकाकर्ता शाहुबनाथ बीवी का बेटा शिहानी मीरा साहिब जमाल मुहम्मद कथित तौर पर भारत के लिए जासूसी करने के आरोप में संयुक्त अरब अमीरात की जेल में बंद है। शाहुबनाथ ने कोर्ट से जेल में बंद बेटे को आवश्यक मदद दिलाने के लिए केंद्र को निर्देशित करने की मांग की है।

जस्टिस पीबी सुरेश कुमार ने कहा, 'हम इसका परीक्षण करेंगे। याचिका के संबंध में केंद्र सरकार के वकील को निर्देश दिए जाएंगे।' शाहुबनाथ का आरोप है कि जेल में उसके बेटे को यातनाएं दी जा रही हैं। भारतीय दूतावास या केंद्र सरकार की तरफ से उसे मदद नहीं दी जा रही है। विधिक सहायता भी उपलब्ध नहीं कराई गई, ताकि वह अपना पक्ष रख सके।

क्रिप्टो करेंसी के जरिये विदेश भेजे करोड़ों रुपये

नईदुनिया, भोपाल

> मध्य प्रदेश साइबर सेल की जांच में बड़ा राजफाश, गुरुग्राम, दिल्ली और राजकोट से आरोपित गिरफ्तार

मध्य प्रदेश की साइबर सेल ने क्रिप्टो करेंसी (बिटकॉइन) के माध्यम से विदेश में करोड़ों रुपये भेजने के मामले का राजफाश किया है। इसमें प्रमुख भूमिका में पाकिस्तान और चीन के नागरिक भी हैं। इनकी जानकारी जुटाई जा रही है। इस मामले में चार आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। ये गुरुग्राम (हरियाणा), दिल्ली और राजकोट (गुजरात) के निवासी हैं। दो आरोपित फरार हैं। पाकिस्तान के नागरिक का नाम आने से शक है कि राशि पाकिस्तान भी पहुंची है।

राज्य साइबर सेल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक योगेश चौधरी ने बताया कि भोपाल निवासी व्यवसायी ने 16 मई, 2021 को साइबर सेल में शिकायत की थी कि उससे कमोडिटी ट्रेडिंग के नाम पर एक करोड़ से अधिक की ठगी की गई है। साइबर सेल की टीम ने जांच शुरू की तो देश में अपनी तरह के अनूठे मामले का राजफाश हुआ। व्यवसायी की डेटिंग एप्लीकेशन पर एक महिला से पहचान हुई। महिला ने उसे मसालों की ट्रेडिंग के लिए वेबसाइट का नाम सुझाया। व्यवसायी ने उस वेबसाइट पर ट्रेडिंग शुरू की। वहां से हर लेन-देन की जानकारी और बैंक खातों में ट्रांजेक्शन दिखता रहा। जब उसने राशि निकालनी चाही, तब उसे धोखाधड़ी का पता चला। इस मामले में गुरुग्राम निवासी ऐविक केडिया, दिल्ली निवासी डॉली माखीजा व विक्की माखीजा और राजकोट निवासी दिलीप पटेल को गिरफ्तार किया गया है। राजकोट निवासी विजय हरियानी और मुंबई निवासी विजय छुटलानी फरार हैं।

क्रिप्टो करेंसी को इस तरह भेजा जाता था देश के बाहर: चौधरी ने बताया कि इस धोखाधड़ी के लिए आरोपितों ने फर्जी कंपनियां बनाईं। इनमें सभी चालू खाते बैंक में खुलवाए गए ताकि राशि निकालने में दिक्कत न आए। गुरुग्राम, दिल्ली और राजकोट की फर्म के नाम से पांच बैंक खातों में दो माह में तीस करोड़ रुपये का लेन-देन किया गया। इस राशि को क्रिप्टो ट्रेडर्स के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी में बदलकर देश से बाहर भेजा गया। क्रिप्टो ट्रेडर्स ने वजीरएक्स व बिनांस नामक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर टीथर नामक क्रिप्टो करेंसी में इसे बदला गया। इसके संचालन में पाकिस्तानी नागरिक की भूमिका खास है। चीन के एक नागरिक का नाम भी सामने आया है। दोनों अज्ञात हैं। इस राशि के उपयोग के बारे में जानकारी नहीं मिली है। आरोपितों ने धोखाधड़ी के लिए पांच फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया था।

दो मामलों की जांच जारी: इसी तरह के दो अन्य मामलों की जांच भोपाल और इंदौर जोनल कार्यालयों में की जा रही है। इनमें 45 और 25 लाख रुपये की आनलाइन धोखाधड़ी की गई है।

एम्स की काउंसिलिंग में तीन लाख जमा कराने के खिलाफ याचिका खारिज

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में स्नातकोत्तर सीटों के लिए होने वाली खुले दौर की काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए तीन लाख रुपये जमा कराने की शर्त को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने कहा कि वह मौजूदा वर्ष के लिए इस याचिका पर सुनवाई करने में असमर्थ है, क्योंकि दाखिला पाने वाला कोई भी प्रभावित छात्र अदालत के समक्ष नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह याचिका थोड़ी देर से दायर की गई है, क्योंकि काउंसलिंग की समूची प्रक्रिया नौ से 14 जनवरी, 2021 के बीच पूरी हो गई।

पीठ ने कहा, इस परिस्थिति में हम याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि मौजूदा वर्ष में कोई राहत नहीं दी जा सकती। हालांकि, हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि अदालत ने इस मुद्दे के गुणदोष या वैधानिकता को खत्म नहीं किया है, जिन्हें खुले दौर की काउंसलिंग के लिए तीन लाख रुपये मांगे जाने के संदर्भ में यहां उठाया गया है।

'ट्विटर इंडिया की भूमिका की जांच को इच्छुक नहीं गाजियाबाद पुलिस'

> माहेश्वरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने प्रतिवादी की मंशा पर उठाए सवाल

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि ट्विटर पर साझा किए गए विवादित वायरल वीडियो मामले में ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक (एमडी) मनीष माहेश्वरी की भूमिका की जांच के लिए गाजियाबाद पुलिस इच्छुक ही नहीं है। विवादित वीडियो को साझा करने वाले ने दावा किया था कि एक बुजुर्ग को जय श्रीराम व वंदे मातरम कहने के लिए मजबूर किया गया और ऐसा नहीं करने पर उसकी दाढ़ी काट ली गई। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी।

जस्टिस जी. नरेंद्र की एकल पीठ ने टिप्पणी की, 'मामला जांच का है और इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि आपने जांच क्यों नहीं की। समस्या यह है कि आप जांच ही नहीं करना चाहते।' प्रतिवादी गाजियाबाद पुलिस को आड़ेहाथ लेते हुए कोर्ट ने कहा, 'आप मेरे प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल नहीं दे रहे हैं... आप किस आधार पर कह रहे हैं कि ट्विटर इंडिया जिम्मेदार है? यह पूरी तरह स्पष्ट है कि ट्विटर इंडिया व ट्विटर इंक दो निकाय हैं। ऐसे में आपकी जांच कहां है?'

गाजियाबाद पुलिस को दोनों निकायों को एक न करने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने यह जानना चाहा कि क्या पुलिस रजिस्ट्रार आफ कंपनी (आरओसी) तक गई है। कोर्ट ने पुलिस को कहा कि वह आरओसी से एक दिन में कंपनी की गतिविधियों का पता लगा सकती थी और माहेश्वरी के उस दावे की पुष्टि कर सकती थी कि ट्विटर इंडिया अलग इकाई है। कोर्ट ने कहा, 'ऐसा नहीं है कि वह (माहेश्वरी) उदंड हैं। वह बहुत विशिष्ट और स्पष्ट हैं। वह कहते हैं कि उनका वीडियो अपलोड करने पर नियंत्रण नहीं है। कम से कम उन्होंने कोर्ट के सामने वस्तुस्थिति तो रखी है।'

माहेश्वरी का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता सीवी नागेश ने कहा कि ट्विटर तो इंटरमेडियरी भी नहीं है, क्योंकि आरोप ट्विटर इंडिया के खिलाफ हैं, न कि ट्विटर इंक (अमेरिका) के खिलाफ। इस पर कोर्ट ने प्रतिवादी से कहा कि आप इस मामले को कहां ले जा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि गाजियाबाद पुलिस ने माहेश्वरी को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41-ए के तहत 21 जून को नोटिस जारी कर 24 जून को लोनी बार्डर थाने में सुबह साढ़े दस बजे उपस्थित होने को कहा था। इसके खिलाफ माहेश्वरी ने कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील की थी। अदालत ने 24 जून को गाजियाबाद पुलिस को माहेश्वरी के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया था। गाजियाबाद पुलिस ने 15 जून को ट्विटर इंक, ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया व अन्य के खिलाफ पांच जून को हुई कथित घटना का वीडियो साझा कर सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था।

नए आइटी नियमों के खिलाफ दायर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट मंगवाई जाएं

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र ने देश के विभिन्न हाई कोर्ट में नए सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर मंगलवार को शीर्ष अदालत का रुख किया। सरकार की इस याचिका पर इसी हफ्ते सुनवाई होने की संभावना है।

एक वरिष्ठ विधि अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की। सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट सहित विभिन्न हाई कोर्ट में लंबित हैं।

हाई कोर्ट में लंबित याचिकाओं में फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया फर्मों के साथ ही ओटीटी मंचों को विनियमित करने के उद्देश्य से लाए गए नए आइटी नियमों को चुनौती दी गई है। नए आइटी नियमों के तहत भारतीय उपयोगकर्ताओं की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति जरूरी है।

ट्विटर ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर कहा कि वह नए आइटी नियमों के तहत एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक अंतरिम स्थानीय शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के अंतिम चरण में है।

दैनिक जागरण
अनुशासन ही उन्नति की कुंजी है

मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार

केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने से मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार की संभावनाएं और प्रबल हो गई हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार अवश्यंभावी होने के कुछ और भी कारण हैं। एक तो मोदी सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूरे हो चुके हैं और दूसरे, शिवसेना एवं अकाली दल के मंत्री मंत्रिमंडल से बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा रामविलास पासवान के निधन से भी मंत्री पद रिक्त है। यह भी ध्यान रहे कि अगले वर्ष पांच राज्यों में चुनाव हैं और इस दृष्टि से भी कुछ चेहरों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाना स्वाभाविक है। एक अन्य तथ्य यह भी है कि इस मंत्रिमंडल में कई ऐसे मंत्री हैं, जिनके पास एक से अधिक मंत्रालय हैं। कुछ मंत्री तो ऐसे हैं जिनके पास चार-चार मंत्रालय हैं। स्पष्ट है कि यह आदर्श स्थिति नहीं। एक-दो से अधिक मंत्रालयों को संभाल रहे मंत्रियों के काम का बोझ केवल इसलिए कम नहीं किया जाना चाहिए कि वह अपना काम सही तरह से कर सकें, बल्कि इसलिए भी कम किया जाना चाहिए, क्योंकि शेष तीन साल के कार्यकाल में मोदी सरकार के उस एजेंडे को पूरा करने की चुनौती सामने आ खड़ी हुई है, जो कोविड महामारी के कारण बाधित हुआ है। निःसंदेह कम समय में अधिक काम तभी हो सकता है, जब केंद्रीय मंत्री अपने काम पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सकेंगे।

मोदी सरकार के मामले में यह कहना और कठिन है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कौन-कौन लोग मंत्री बनेंगे, लेकिन यह मानकर चला जाना चाहिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सर्बानंद सोनोवाल प्रमुख दावेदार हैं। इसी तरह जनता दल यू और अन्य सहयोगी दलों के नेता भी मंत्रिमंडल में अपना स्थान बना सकते हैं। वैसे तो मंत्रिमंडल में अपने सहयोगियों का चुनाव करना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन उनके लिए क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों की अनदेखी करना मुश्किल है। भारत सरीखे बड़ी आबादी और विविधता वाले देश में प्रधानमंत्री के लिए यह आवश्यक सा हो जाता है कि वह समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों के नेताओं को अपने मंत्रिमंडल में स्थान दे। बावजूद इसके अपेक्षा यही है कि एक ओर जहां बेहतर काम करने वाले मंत्रियों को पदोन्नति मिले, वहीं नए मंत्रियों के चुनाव में योग्यता को सर्वोच्च महत्व प्रदान किया जाए। यदि क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को पूरा करने के फेर में योग्यता की अनदेखी होगी तो फिर उसका असर सरकार के कामकाज पर पड़ेगा। भले ही राजनीति से इतर क्षेत्रों के लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान देना पड़े, कोशिश यही होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दक्ष लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान मिले-ठीक वैसे ही जैसे जयशंकर और हरदीप पुरी को मिला था।

खनन पर रोक

खनन से सिर्फ पर्यावरण को ही नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि यह पेयजल स्रोतों को भी निगल रहा है। हिमाचल प्रदेश में खनन माफिया काफी समय से सक्रिय हैं। सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई भी करती है, लेकिन कुछ दिन बाद माफिया सक्रिय हो जाते हैं। सीमांत क्षेत्रों में पड़ोसी राज्यों के माफिया भी सक्रिय हैं। खनन से नदियां गहरी हो गई हैं और कई जगह इनका बहाव भी बदल गया है। बरसात में काफी जमीन भी बह जाती है। कई जगह पुलों को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। सबसे अधिक प्रभाव पेयजल योजनाओं पर पड़ा है। कई जलस्रोतों में पानी कम हो गया है। सरकार ने इसका कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। पिछले दिनों खनन संबंधी गतिविधियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि नगर निगम क्षेत्र के दो किलोमीटर और नगर पंचायत क्षेत्र के एक किलोमीटर दायरे में किसी को खनन की अनुमति नहीं होगी। खनन के लिए समिति से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लेना जरूरी होगा। इसके साथ ही पेयजल और सिंचाई योजनाओं के 200 मीटर के दायरे और पुलों के नीचे धारा प्रवाह के 500 मीटर दायरे में खनन की अनुमति नहीं होगी। सरकार का देरी से उठाया गया यह सराहनीय फैसला है। कई स्थानों पर बड़ी मशीनों के साथ नदियों में खनन किया जा रहा है, जबकि नदियों में मशीनों से खनन नहीं किया जा सकता है। सड़कों पर रात और अलसुबह खनन सामग्री ले जाते वाहन देखे जा सकते हैं। सरकार ने खनन के दोषी के खिलाफ पांच लाख रुपये तक जुर्माने और दो वर्ष की कैद का प्रविधान किया है। इसके बावजूद अवैध खनन नहीं रुक पा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में तो स्थिति काफी गंभीर है। हर रोज सैकड़ों वाहन खनन सामग्री पड़ोसी राज्यों में ले जा रहे हैं। सरकार को इन क्षेत्रों में जल्द पड़ताल चौकियां स्थापित करनी चाहिए। इन क्षेत्रों में गश्त की भी व्यवस्था की जानी आवश्यक है। संबंधित क्षेत्र के लोगों विशेषकर पंचायत प्रतिनिधियों को भी खनन के खिलाफ सक्रिय होने की आवश्यकता है। जब सभी पक्ष खनन के खिलाफ आवाज उठाएंगे तभी इस पर रोक लगाई जा सकेगी।

खनन पर रोक के लिए सरकारी प्रयास के साथ आम लोगों की सहभागिता भी अहम है

खुद को साबित करने का सुनहरा अवसर



सृजन पाल सिंह

दुनिया कोविड-19 के बाद के युग में एशिया में नए शक्तिशाली कारोबारी साझीदार ढूंढ रही है। हमें इस मौके को किसी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए

डेढ़ साल पहले जब कोविड-19 महामारी दुनिया के लिए संकट बनकर आई, तब किसे पता था कि जिस वायरस को हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, वही एक नई विश्व व्यवस्था के उदय का कारण बन जाएगा। वायरस के लैब-लीक को लेकर चीन पर संदेह बढ़ने के साथ ही इस 'फैक्ट्री-राष्ट्र' चीन को विश्व भर में जीवन और आजीविका को भयंकर हानि पहुंचाने का जिम्मेदार माना जा रहा है। राष्ट्रपति पद से डोनाल्ड ट्रंप की विदाई के पश्चात वैश्विक महाशक्ति अमेरिका अपने समाज में तेजी से बढ़ते सामाजिक संघर्ष से दो-चार है। यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल है। उसके सदस्य देशों के बीच खींचतान जारी है। वर्ष 2020 के आखिर तक विश्व व्यापार में चीन का हिस्सा 15 प्रतिशत, अमेरिका का 11.5 प्रतिशत और भारत का दो प्रतिशत से भी कम था, मगर अब स्थिति तेजी से बदल रही है। दुनिया अब चीन से व्यापार को लेकर सतर्क है। तमाम देश व्यापार और उत्पादन के नए-नए तरीके ढूंढ रहे हैं। पश्चिम के ताकतवर देश चीन को छोड़ दूसरे साझीदारों की गंभीरता से तलाश कर रहे हैं। यही अवसर है जब भारत 'ग्लोबल लीडर' यानी विश्व गुरु के रूप में उभर सकता है। दरअसल इन विकट परिस्थितियों में भी भारत ने कुछ नया करने का दृढ़संकल्प दिखाया है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन के साथ भारत ही ऐसा देश है जिसने एक कारगर कोविड-19 रोधी वैक्सीन बनाई। करीब एक वर्ष पहले हमारे पास अपने लिए पीपीई किट और मास्क बनाने तक की सुविधा नहीं थी। हम कहीं से भी उनके आयात के प्रयास में थे। तब भारत ने अपने आप को बदला। देश ने आज मास्क के आयातक से खुद को सबसे बड़े वैक्सीन निर्यातक के रूप में खड़ा किया है, जिसकी वैक्सीन 85 देशों तक पहुंची।

वर्ष 1991 में भारत ने जब अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, तब भारत और चीन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लिहाज से लगभग एक ही पायदान पर थे। विशुद्ध रूप से कम-लागत वाले उत्पादन की बदौलत चीन हमें तेजी से पछाड़ते हुए आगे निकल गया, जो अक्सर शोषणवादी श्रम कानूनों की कीमत पर होता है। सस्ते उपभोक्ता सामान के नशे में दुनिया ने चीन के इस आक्रामक विकास मॉडल के खतरों को अनदेखा कर दिया। अब कोविड-19 ने एक सबक सिखाया है कि अनैतिकता और अन्याय से कभी स्थायी विकास संभव नहीं है। इस उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्था को लागत की इस स्पर्धा से आगे जाना होगा। इसे विश्वास और मानवता पर आधारित होना चाहिए। इस नए सूर्योदय में भारत के पास एशिया का पावरहाउस बनने का दमदार अवसर है। कई बातें हैं, जो हमारे पक्ष में हैं। पहली, लोक केंद्रित लोकतंत्र की हमारी शैली और खुली आलोचना पारदर्शिता के सूचक हैं। भारतीय कानून और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा कोई भी कर सकता है। हमने जैविक हथियार बनाने के नापाक मंसूबे कभी नहीं पाले। बर्बरता से विपक्ष को कुचलने वाले चीन की एकदलीय व्यवस्था के मुकाबले हमारे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कहीं अधिक विश्वसनीय हैं। दूसरी, हमारे शिक्षित और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवा विश्व की नई अर्थव्यवस्था के निर्माण की रीढ़ हैं। आज जो भी सेक्टर दुनिया में स्वयं को फिर से खड़ा करना चाहता है, वह इसके लिए भारतीय युवाओं की सहायता ले सकता है। तीसरी, उपभोक्ता देश के रूप में भी हम शक्तिशाली हैं। कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी हमारे बड़े बाजार को हाथ से नहीं जाने दे सकती। हमारे पास अवसर है कि हमारे स्थानीय उद्यम बड़ी वैश्विक कंपनियों से सीखें, साझेदारी करें और आगे एक दशक में और भी बड़े बाजार पर व्यापार करें।



अवधेश राजपूत

हालांकि इसके लिए हमें कुछ प्रमुख क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें अपने ग्रामीण विकास के ढांचे पर गौर करना होगा। भारत के छह लाख गांव आर्थिक बोझ नहीं, बल्कि शक्तिपुंज हैं, जिनकी संभावनाओं का पता लगाने की आवश्यकता है। वे अवसरों का भंडार और एक विशाल उपभोक्ता बाजार हैं। उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाले और ऑटोमोबाइल उद्योग लगभग 45 प्रतिशत सामान ग्रामीण भारत में बेचते हैं। अब बिजली और इंटरनेट की पहुंच गांव-गांव तक है। लिहाजा ऐसे ग्रामीण भारत में हमें सिर्फ खेती को ही नहीं, उससे आगे भी देखना होगा। वे उन्नत उद्योग, तकनीकी शोध और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों के गढ़ बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) की शुरुआत की है, ताकि स्थानीय क्षमता के आधार पर प्रत्येक जिले में एक लक्षित उद्योग लगाया जा सके। इस प्रकार की तरकीबों को उद्योग जगत के समर्थन और व्यापक स्तर पर लागू करने की जरूरत है। फिर हमें इन तरकीबों और युवाओं की ऊर्जा पर पूंजी लगाने की आवश्यकता है। युवाओं के पास जबरदस्त आइडिया हैं, लेकिन उन्हें पूर्ण रूप से साकार करने में छोटे से निवेश के लिए भी वे बरसों से भटक रहे हैं। भारत के 80 प्रतिशत स्टार्ट-अप को 30 साल से कम उम्र के युवाओं ने शुरू किया है। यही नहीं, नए जमाने के बड़े से बड़े ब्रांड की शुरुआत भी बेहद कम आयु के संस्थापकों ने की थी। यदि हम चाहते हैं कि ऐसे युवा भारत के नए युग के आर्थिक विकास का नेतृत्व करें तो हमें उनकी मदद के लिए एक मजबूत ढांचे का निर्माण करना चाहिए।

वास्तव में देशभक्ति की भावना ने हमारे राष्ट्रवाद को नई ऊंचाई दी है। आज तकनीकी राष्ट्रवाद आवश्यक है। 21वीं सदी के राष्ट्रवाद में हमें अपने युवाओं को उस सहृदय तकनीक के पथ पर चलने की शिक्षा देनी होगी, जिससे मातृभूमि की सेवा की जा सके। हालांकि कई लोगों को संदेह है कि भारत इतने कम समय में इतना कुछ कैसे प्राप्त कर सकता है? तो शुभ संकेत यह है कि इतिहास ने हमें दिखाया है कि वैश्विक व्यवस्था को राह बदलने में अधिक समय नहीं लगता। 1995 में चीन तीन प्रतिशत विश्व व्यापार के साथ दुनिया में कहीं भी नहीं था। वहां से मात्र दो दशक बाद वह दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी देश बन गया है। भारत के पास आज उससे भी बेहतर अवसर हैं, क्योंकि दुनिया कोविड-19 के बाद के युग में एशिया में नए शक्तिशाली कारोबारी साझीदार ढूंढ रही है। हमें इस मौके को किसी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए।

(पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के सलाहकार रहे लेखक कलाम सेंटर के सीईओ हैं)

response@jagran.com

कोरोना ने बदला शिक्षा देने का तरीका



गिरीश्वर मिश्र

कोरोना तो चला जाएगा, लेकिन उसके बाद शिक्षा का स्वरूप पहले जैसा नहीं रह जाएगा

कोविड महामारी का सबसे गहन प्रभाव देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन को लेकर दिख रहा है, जो मानव संसाधन के निर्माण के साथ ही युवा भारत की सामर्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। महामारी के चलते स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से तात्कालिक कदम के रूप में शैक्षिक संस्थानों को प्रत्यक्ष भौतिक संचालन से मना कर दिया गया, फिर कक्षा की पढ़ाई और परीक्षाएं जहां भी संभव थीं, आभासी (वर्चुअल) माध्यम से शुरू की गईं। करीब डेढ़ साल से यह हलचल जारी है। इसमें संदेह नहीं कि बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए शिक्षा केंद्र में विद्यार्थी की भौतिक उपस्थिति महत्वपूर्ण होती है, पर महामारी के कारण विद्यालय की अवधारणा ही बदल गई। तमाम विद्यार्थी आनलाइन प्रवेश, आनलाइन शिक्षा और आनलाइन परीक्षा को बाध्य हुए। शिक्षा केंद्र विद्यार्थी और शिक्षक से भौतिक रूप से दूर तो हुए ही, उनके विकल्प में मोबाइल या लैपटाप की स्क्रीन पर लगातार घंटों बैठने से परेशानियां भी होने लगीं। सच तो यह है कि शिक्षा पाने का प्रेरणादायी अनुभव उबाऊ होने लगा।

दरअसल आभासी माध्यम पर आनलाइन कक्षा की प्रकृति में अध्यापक-छात्र के बीच होने वाली अंतःक्रिया अस्वाभाविक और असहज होती है। उसमें विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी और शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले फीडबैक कृत्रिम होते हैं। लिहाजा विद्यार्थी की प्रतिभा को प्रदर्शित करने के अवसर कम होते जाते हैं। वहीं वास्तविक परिस्थितियों में शिक्षक के समक्ष विद्यार्थी की उपस्थिति होने में अनुशासन के अभ्यास का भी अवसर मिलता है। इससे एक सामाजिक परिस्थिति बनती है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। इसके उलट आनलाइन कक्षा में कोताही की गुंजाइश अधिक हो गई है। इन सबसे शिक्षा की स्वीकृत परिभाषा, ढांचा और प्रक्रिया ही बदल गई। बहरहाल यह तकनीकी बदलाव सिर्फ डिलीवरी के तरीके से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि दुनिया और खुद से जुड़ने और अनुभव करने के नजरिये से भी जुड़ा हुआ है। सीखने की प्रक्रिया को कंप्यूटर के की-बोर्ड को आपरेट करने तक सीमित करना विद्यार्थियों को सीखने और समझने की शैलियों में विविधता की भी अनदेखी कर रहा है। आज एक बंधा-बंधाया तकनीक-नियंत्रित ढांचा उनके ऊपर थोप दिया गया है। उसी में बंधकर ही उनका सीखना-पढ़ना हो रहा है। ऐसा करने से उनकी कल्पनाशीलता, प्रयोग और सृजन के अवसर पर एक तरह से ग्रहण लग गया है। इन सबके बीच सूचना ही ज्ञान और अनुभव का पर्याय बनती जा रही है। हालांकि ऐसे आशावादी लोग भी हैं, जो अब यह विश्वास करने लगे हैं कि भविष्य में सब कुछ आनलाइन हो जाएगा। वे उसे ही एकमात्र विकल्प मान बैठे हैं। देखा जाए तो यह कल्पना दूर की कौड़ी है। इस तरह की सोच शिक्षा को उसके मुख्य प्रयोजन से दूर ले जाने वाली है। दूसरी ओर कुछ यथास्थितिवादी शिक्षाविद् भी हैं, जो शिक्षा के पारंपरिक ढांचे को ही ठीक समझते हैं। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों में अधिकांश लोग आनलाइन और आफलाइन, दोनों तरीकों के मिले-जुले रूप को ही बेहतर मानते हैं। वे बदलते वैश्विक परिदृश्य में नई तकनीकों का लाभ लेते हुए शिक्षा की संवादमूलक मानवीय प्रक्रिया को स्वाभाविक और मानवता का हितैषी मानते हैं।



कोरोना काल में अपरिहार्य बनी आनलाइन शिक्षा। फाइल

आज की आनलाइन शिक्षा से जुड़े लोगों की बदलती आदतें अब तकनीकी व्यवस्था में उलझ रही हैं। नतीजा यह हो रहा है कि अब ध्यान देने, सोचने और आत्मसात करने की जगह डाउनलोड और अपलोड करने, गूगल सर्च करने, स्क्रीन शेयर करने और पीपीटी तैयार करने जैसे कंप्यूटरी कौशल के अभ्यास और प्रबंधन के रूटीन को स्थापित करने में ज्यादा समय बीत रहा है। इंटरनेट से जुड़ते हुए देश और काल, दोनों का अनुभव बदल जाता है। साइबर स्पेस में भ्रमण अद्भुत होता है। सूचना का प्रवाह जिस वेग से बढ़ रहा है वह चौंकाने वाला है। इसमें जानकारियां तत्काल बासी हो जा रही हैं। बुद्धि और विवेक की जगह तकनीक की बढ़ती प्रतिष्ठा का चरम कृत्रिम बुद्धि में प्रतिफलित हो रहा है। वस्तुतः तकनीक मानव मूल्यों की जगह नहीं ले सकती। सब कुछ मशीन के हाथों सुपुर्द करना दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

यह साफ जाहिर है कि कोविड महामारी की मार समाज के विभिन्न वर्गों पर एक जैसी नहीं पड़ी है। आनलाइन शिक्षा के जरूरी संसाधनों की व्यवस्था के लिए आर्थिक साधन सबके पास न होने से उस तक पहुंच एक ऐसे डिजिटल डिवाइड को जन्म दे रही है, जो संपन्न परिवार से आने वाले विद्यार्थियों और कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के बीच की खाई को और ज्यादा बढ़ाने वाली है। हम यह न भूलें कि वंचित और कमजोर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा समस्या उनकी आर्थिक असुरक्षा से जुड़ी हुई है, जिसका प्रभावी नीतिगत समाधान अभी तक नहीं हो सका है। आनलाइन पढ़ाई की उपलब्धता की स्थिति में पूरे देश में बड़ी विविधता है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

हालांकि नई शिक्षा नीति भी आनलाइन पाठ्यक्रम के उपयोग को बढ़ावा देती है। इससे विद्यार्थी अपनी रुचि के कुछ पाठ्यक्रमों की दूसरी संस्थाओं से भी आनलाइन पढ़ाई कर सकेगा। इस प्रस्तावित लचीली शिक्षा व्यवस्था में छात्र-छात्राओं को अपनी रुचि, प्रतिभा और सृजनात्मकता को निखारने का अवसर मिल सकेगा। इस तरह की पढ़ाई से मिलने वाले क्रेडिट स्वीकार्य होंगे और डिग्री की पात्रता से जुड़ जाएंगे। देखना है कि नई शिक्षा नीति का मसौदा कार्य रूप में किस तरह व्यावहारिक धरातल पर उतरता है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि शिक्षा की आधार संरचना में निवेश किया जाए। कोरोना जाएगा, पर उसके बाद शिक्षा का स्वरूप पहले जैसा नहीं रह जाएगा और उस स्थिति के लिए तैयारी जरूरी है।

(लेखक पूर्व कुलपति एवं पूर्व प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सत्य से साक्षात्कार

संप्रति शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि होने के बावजूद मानवीय विचारों में संकीर्णता बढ़ती ही जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति वास्तविक सत्य से दूर होता जा रहा है। आज जो स्वयं को सत्यवादी कहते हैं, वे भी सत्य के वास्तविक अर्थ का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। सत्य बोलना ही सत्यता की संपूर्ण परिधि नही है। यह तो सत्यता का केवल एक क्षुद्र अंश है। यदि सत्यता को धारण करना है तो इसे आचरण और विचारों में उतारना होगा। यह तभी संभव है जब सत्यता हृदय की गहराइयों में समाई होगी। जब ऐसी स्थिति विकसित हो जाती है तब आचरण और विचार अपने आप ही बदल जाते हैं। सत्यता से सराबोर व्यक्ति के अंतर्मन में ऐसा प्रचंड बल प्रवेश कर जाता है जिसके समक्ष सृष्टि के सभी बल निर्बल पड़ने लगते हैं। सत्य की सामर्थ्य की तुलना इस भौतिक जगत में उपलब्ध किसी भी बल से नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति आत्मा से सच्चा है वही बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि आत्मा से सच्चा व्यक्ति ही आत्मा की आवाज के अनुसार आचरण करता है। परिणामस्वरूप वह एक शक्तिपुंज के समान हो जाता है।

आज के युग का पढ़ा-लिखा व्यक्ति सत्य की भाषा न बोलकर कानून, नियम और अधिकार की भाषा ज्यादा बोलता है। संभवतः इसी कारण वह तनाव में रहता है। हमें आज के तनाव भरे युग में अध्यात्म की भाषा में सोचना और चिंतन करना सीखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की चेतना केवल इसी तरह से जागृत होती है। जब तक चेतना जागृत नहीं होगी तब तक न्याय और अन्याय में वास्तविक भेद कर पाना कठिन होगा। अध्यात्म की ओर अग्रसर होने में सत्य की निर्णायक भूमिका होती है, क्योंकि सत्य ही हृदय के अंधकार को दूर करता है। प्रत्येक व्यक्ति को इस पर चिंतन अवश्य करना चाहिए कि वह कितनी सच्चाई से भरा जीवन जी रहा है। भ्रांतियों को तोड़कर हमें सत्य से साक्षात्कार करना चाहिए तभी जीवन की नैया पार लगेगी।

वीके जायसवाल

आसमान में रहना होगा और चौकन्ना

रंजना मिश्रा

ड्रोन संवेदनशील जानकारियां चुराने के साथ ही आतंकी हमले करने में भी सक्षम है। उसकी काट के उपाय तलाशने ही होंगे

हाल में जम्मू एयरबेस पर ड्रोन यानी यूएवी से हुए आतंकी हमले ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष खतरे की एक नई घंटी बजा दी है। यह अपनी किस्म की पहली ऐसी घटना है जिसमें ड्रोन के जरिये किसी भारतीय सामरिक प्रतिष्ठान को निशाना बनाया गया। आतंकियों ने ड्रोन का इस्तेमाल इसलिए किया, क्योंकि इसे रडार की मदद से पकड़ना बेहद मुश्किल है। ड्रोन अपने कैमरे से संवेदनशील गतिविधियों की सूचना भेज सकता है, डाटा चुरा सकता है और जानमाल का नुकसान तक कर सकता है। इसलिए ये ड्रोन अटैक बहुत ही खतरनाक है। इसी खतरे को भांपते हुए अब एंटी ड्रोन सिस्टम की मांग और बढ़ गई है। उसे जल्द से जल्द भारत लाने की बात कही जा रही है। इससे जुड़े सौदे के तहत भारत को जल्द ही इजरायली एंटी ड्रोन सिस्टम मिल सकता है। नौसेना इसकी खरीद की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर चुकी है। सेना और वायुसेना भी जल्द इस दिशा में कदम बढ़ा सकती हैं।

इस बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने ऐसी एंटी ड्रोन तकनीक विकसित की है, जिससे दुश्मन का ड्रोन पलक झपकते ही ढेर हो जाएगा। इस सिस्टम को इंद्रजाल नाम दिया गया है। डीआरडीओ की यह ऐसी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जो लेजर के माध्यम से हवाई ऑब्जेक्ट को चूर-चूर करने में सक्षम है। इसे डीआरडीओ ने करीब डेढ़ साल पहले विकसित किया है। इस तकनीक का नाम चैस है। ये दुश्मन के ड्रोन को तहस-नहस कर सकती है। इसे जमीन के साथ-साथ गाड़ियों पर भी लगाया जा सकता है। इस डिवाइस में 360 डिग्री तक रोटेट करने वाला एक रडार है, जो चार किलोमीटर की रेंज तक छोटे-छोटे ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर भी मौजूद है। ड्रोन को हवा में ही जाम करने के लिए जैमर भी इसमें लगे हैं। ये सारी चीजें सॉफ्ट किल का हिस्सा हैं। जहां तक हार्ड किल यानी आतंकी ड्रोन को खत्म करने की बात है तो इसमें खास लेजर सिस्टम लगा है।

यह पूरा सिस्टम कमांड पोस्ट के जरिये एकीकृत होता है। ये तीन किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के ड्रोन को लॉक कर सकता है और ढाई किलोमीटर की रेंज में हार्ड किल व सॉफ्ट किल के जरिये उन्हें पूरी तरह ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है। दरअसल यह तीन अलग-अलग तरीके से काम करता है। लेजर के जरिये दुश्मन के यूएवी को लॉक करके तुरंत उसे गिराने की क्षमता इस एंटी ड्रोन तकनीक में है। दूसरा ये उसके सेंसर्स और सिग्नल्स को जाम कर देता है। तीसरा सभी सिग्नल्स को ब्लॉक करके ये यूएवी को दुश्मन से डिस्कनेक्ट कर सकता है, जिससे यूएवी को ऑपरेट करने वाले हैंडलर तक कोई जानकारी या कोई तस्वीर नहीं पहुंच पाएगी। डीआरडीओ के इस एंटी ड्रोन सिस्टम का कई मौकों पर सफल परीक्षण हो चुका है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

पूर्वाग्रह से ग्रस्त पश्चिमी मीडिया

'भारत विरोध पर आमादा पश्चिमी मीडिया' शीर्षक से लिखे अपने आलेख में श्रीराम चौलिया ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया के पूर्वाग्रह को पूरी तरह उजागर करके रख दिया। लेखक ने जिन पश्चिमी मीडिया संस्थानों का उल्लेख किया है, उनके विषय में एक तथ्य यह भी है कि अमूमन समूचे दक्षिण एशिया के लिए ही उनका एक संवाददाता नियुक्त होता है या फिर एक बहुत ही छोटी सी टीम होती है। आखिर इतने बड़े दक्षिण एशिया और विशेषकर भारत जैसे महादेश, जिसे भौगोलिक-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, के लिए चुनिंदा लोग कैसे वस्तुनिष्ठ तस्वीर पेश कर सकते हैं। इतना ही नहीं उन लोगों को जमीनी मुद्दों और स्थानीय समुदाय को लेकर भी कोई पुख्ता जानकारी या समझ नहीं होती। ऐसी बुनियादी समझ के अभाव में वे कैसे तथ्यों को निष्पक्षता की कसौटी पर कसकर वास्तविक रपट बना सकते हैं। यही कारण है कि वे भारत या दक्षिण एशियाई देशों की जो तस्वीर दिखाना चाहते हैं, उसका खाका उनके दिमाग में पहले से ही बना होता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के विज्ञापन से उसके ऐसे पूर्वाग्रह की ही पुष्टि होती है। भारतीयों को ऐसी एकतरफा रिपोर्टिंग पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, जो संस्थान उनके मूल्यों, संस्कृति और मुद्दों की समझ न रखते हों।

केशव तिवारी, इंदिरापुरम (गाजियाबाद)

फायदा उठाने वाला देश

भारत हमेशा से रास्ता सिखाता है और संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए क्रेडिट लाइन का विस्तार करता है। इसके विपरीत चीन सिर्फ अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हुए मुश्किल में फंसे देशों की समस्याओं का फायदा उठाता है। पाकिस्तान, चीन का आधुनिक उपनिवेश बन गया है। यही कारण है कि इमरान खान अपना चेहरा छुपाते हैं, जब उनसे उइगर मुस्लिमों के बारे में पूछा जाता है। यहां तक कि श्रीलंका को भी अच्छा सबक मिला है, जब चीन ने कर्ज न चुकाने पर हंबनटोटा बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। आज, भारत की अन्य देशों में लगभग 500 परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें से 300 पूरी हो चुकी हैं। चीन के रवैये को पूरी दुनिया देख रही है। फिर भी 150 देशों में वितरित 1.5 ट्रिलियन डॉलर ऋण के साथ दुनिया का सबसे बड़ा देनदार और मृत जालसाज है। ड्रैगन अपनी सीपीईसी परियोजना को इस्लामाबाद से जोड़ने के लिए काबुल में अपने पैर पसार रहा है। काबुल को अपने जाल में फंसाने के लिए ड्रैगन हरसंभव तरीका अपना रहा है। वहीं भारत अच्छी तरह से जानता है कि शिक्षा से लेकर बिजली आपूर्ति और सड़क तक वहीं उसकी तमाम सफल परियोजनाएं चल रही हैं। निश्चित रूप से ये परियोजनाएं काबुल के साथ द्विपक्षीय संबंध बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

अमन जायसवाल, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

मेलबाक्स

कांग्रेस में बिखराव के संकेत

कांग्रेस के अंदरूनी हालात कुप्रबंधन का शिकार हो गए हैं। गुजरते समय के साथ उसमें आए दिन आपसी खींचतान और विद्रोह के स्वर सुनाई दे रहे हैं। एकजुटता का अभाव और वरिष्ठ नेताओं के प्रभाव को नकारने के कारण समन्वय नहीं बन पा रहा है। आज अहम और सत्ता की ताकत में तनातनी सामने दिख रही है। यह मान लेना बेहद प्रासंगिक है कि यही चंद नेता जो आज सत्ता पर काबिज होने के चलते आपसी द्वंद्व में उलझे हैं वही शायद भविष्य में अगर बहुमत या अल्प वाला बहुमत मिलने पर प्रधानमंत्री और अन्य महत्वपूर्ण पदों के लिए बंदरबांट में न लग जाएं। कांग्रेस यह न भूले कि आजादी के समय अन्य कारणों के अलावा सत्ता के एकाधिकार की लड़ाई भी एक वजह थी, जिसके चलते आम जनता ने देश के बंटवारे को झेला। राजनीतिक दांवपेच खेलने के बजाय अगर आज जिस दौर से आम जनता गुजर रही है, उनके मद्देनजर एकमत होकर गंभीर मुद्दों और समस्याओं के प्रति लामबंद होकर काम करेंगे तब शायद जनता में अपनी साख बना पाएं। विपक्ष में बैठकर मोदी सरकार का प्रतिकार उसी स्थिति में संभव है जब खुद के अंदरूनी हालात बेहतर अवस्था में हों।

मृदुल कुमार शर्मा, गाजियाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) - विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

09 नवंबर, 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड। आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड के 3,946 गांवों से 1,18,981 लोगों ने स्थायी रूप से पलायन कर लिया है।



कुशल कोठियाल
राज्य संपादक, उत्तराखंड

उत्तराखंड

युवा मुख्यमंत्री और उम्मीदों का पहाड़

करीब चार माह पहले जब तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब राज्य की सियासी हवा में क्यों हुआ, कैसे हुआ जैसे प्रश्न तैर रहे थे। इससे पहले कि इन सवालों के जवाब उत्तराखंडियों को मिलते, फिर भाजपा हाईकमान ने पुष्कर सिंह धामी पर दांव लगा दिया। संवैधानिक विवशता का हवाला देते हुए किया गया यह परिवर्तन भी चर्चा का विषय बना हुआ है। बहरहाल अब एक युवा नेता के हाथों में राज्य की कमान जाने से प्रदेशवासियों की उम्मीदें जवान जरूर हो गई हैं



नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास सात माह ही बचे हैं काम के लिए। फाइल

पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें और भाजपा के इस कार्यकाल के तीसरे मुख्यमंत्री बन गए हैं। युवा नेता के प्रदेश की कमान संभालने के साथ ही प्रदेशवासियों की उम्मीदों का जवान होना लाजिमी है। कोरोना से बेपटरी हुए विकास कार्य, शिक्षा, उद्योग और पर्यटन को चुनाव के लिए बचे सात महीनों में गति देना आसान नहीं। उत्तराखंड जैसे भौगोलिक विषमता वाले राज्य में नेता का युवा होना सकारात्मक बिंदु है, लेकिन यहां प्रशासनिक अनुभव के महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता है। धामी पहली बार सरकार में कोई जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और वह भी सीधे मुख्यमंत्री की। उन्हें कैबिनेट में अच्छे तजुर्बेकार सहयोगी मिले हैं, वह इनका कितना सहयोग ले पाएंगे, इस बारे में किंतु-परंतु के बीच शुभकामना ही दी जा सकती है। हालांकि प्रशासनिक अनुभव न होने के बावजूद बड़ी जिम्मेदारी बखूबी निभाने वालों के कई उदाहरण देश-प्रदेश में मौजूद हैं।

सियासी हवा में तैरते सवाल : करीब चार माह पहले जब तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली थी, तब राज्य की सियासी हवा में क्यों हुआ, कैसे हुआ जैसे प्रश्न तैर रहे थे। इससे पहले कि इन सवालों के जवाब उत्तराखंडियों को मिलते, फिर भाजपा हाईकमान ने युवा नेता पर दांव लगा दिया। संवैधानिक विवशता का हवाला देते हुए किया गया यह परिवर्तन भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आम जन के गले यह बात नहीं उतर रही कि इस तरह के पेच का पता भाजपा जैसी संगठित और सुनियोजित पार्टी को तब क्यों नहीं चला जब गैर विधायक तीरथ को ताज सौंपा गया। कांग्रेसी तो अभी से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इसी कानूनी पेच से फंसाने की आशंका जताने लगे हैं। प्रदेश में भाजपा का ट्रैक रिकार्ड देखें तो मुख्यमंत्रियों को बदलना कोई नहीं बात नहीं है। राज्य की स्थापना के समय गठित अंतरिम विधानसभा में पार्टी ने नित्यानंद स्वामी को मुख्यमंत्री बनाया। तब भी संगठन में खुल के असंतोष सामने आया था। तब पार्टी विधायकों ने भगत सिंह कोश्यारी को स्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में जाने से रोक दिया था। ढाई साल के कार्यकाल वाली अंतरिम विधानसभा में भी हाईकमान ने स्वामी को हटा कर अंतिम चार माह के लिए भगत सिंह कोश्यारी को मुख्यमंत्री बना दिया था। 2007 के विधानसभा चुनाव में जब बहुमत मिला, तब भी तीन बार मुख्यमंत्री बदले गए। पहले मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चंद्र खंडूरी, फिर डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक और फिर भुवन चंद्र खंडूरी। 2017 के चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत मिला तो फिर तीन मुख्यमंत्री। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और अब पुष्कर सिंह धामी। भाजपा जैसी पार्टी के सामने बार-बार मुख्यमंत्री बदलने की मजबूरी क्यों आती है, यह प्रश्न तो लोग पूछ ही रहे हैं। प्रदेश में भाजपा ही एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी रही, जिसका प्रांतीय संगठन राज्य के गठन से पहले ही काम कर रहा था। राज्य गठन का श्रेय भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को जाता है। फिर भी अभी तक राज्यस्तरीय व्यक्तित्व और नेतृत्व खोजने के लिए प्रयोग पर प्रयोग जारी हैं। राज्य के हित में है कि यह सिलसिला थमे।

कांग्रेस का अतीत भी इतर नहीं : बार-बार मुख्यमंत्री बदलने को लेकर भाजपा का मखौल उड़ा रही कांग्रेस भी अपने अतीत पर इतरा नहीं सकती है। प्रदेश में कांग्रेस को भी जब सत्ता में आने का मौका मिला तो नेतृत्व को लेकर अस्थिरता कायम रही। अलबत्ता वर्ष 2002 से 2007 तक का कांग्रेस कार्यकाल इसका अपवाद माना जा सकता है। एनडी तिवारी पांच साल तक जमे रहे। यह कार्यकाल अस्थिरता भरा न रहा हो, यह नहीं कहा जा सकता। हरीश रावत समर्थक विधायकों ने तिवारी सरकार आज गई, अब गई का माहौल बनाए रखा। यह तिवारी का व्यक्तित्व था कि उन्हें कोई हिला नहीं पाया। वर्ष 2012 में कांग्रेस को फिर सरकार बनाने का मौका जनता ने दिया। पहले विजय बहुगुणा और फिर हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया।

जमीनी हकीकत से दूरी : भाजपा-कांग्रेस के कई नेता तो मुख्यमंत्री के बदलने को सरकार का बदलना तक नहीं मानते हैं। अस्थिरता से इसे जोड़ा जाना उन्हें राजनीतिक पूर्वाग्रह लगता है। तर्क है कि अगर पांच साल तक सरकार भाजपा की ही है और मुख्यमंत्री तीन बदल गए तो अस्थिरता कहां है। वास्तव में नेताओं की यह जमात जमीनी हकीकत से जाने-अनजाने दूरी बनाए हुए है। उत्तराखंड जैसा सीमांत राज्य जो हमेशा राष्ट्रीय राजनीति की मुख्यधारा में रहा है, अपने राज्य और राज्य की सरकार से भावनात्मक रूप से भी जुड़ा रहता है। मुख्यमंत्री किस पार्टी से है बेशक इसका महत्व है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन है और कब तक है यह भी राज्यवासियों के लिए कम अहम सवाल नहीं है। राज्य में दम-खम रखने वाली दोनों पार्टियां दूसरे सवाल को कम महत्व देती रही हैं।

मुख्यमंत्री को विधानमंडल दल की बैठक में विधायक चुनते हैं, यह संवैधानिक व्यवस्था दोनों दलों के लिए महज औपचारिकता भर रह गई है। विधायकों की बैठक में हाईकमान की पर्ची पर लिखा नाम ही सबको स्वीकार करना होता है। जब नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री बने, तब विधायकों का समर्थन तो भगत सिंह कोश्यारी के पास था। जब एनडी तिवारी और विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने, तब भी अधिकतर विधायकों का समर्थन हरीश रावत के साथ था। विधायक मुख्यमंत्री चुनते हैं, यह प्रविधान कितना धरातलीय है, सब जानते हैं। यह भी अनुभव में आया है कि राज्य भर में अच्छे नेटवर्क वाले दोनों दल राज्य का मुखिया चुनते समय जनता की राय को भी हाशिये पर रखते रहे हैं। कई बार तो योग्यता, नेतृत्व क्षमता, चरित्र, लोकप्रियता, चुनावी कौशल, दलीय निष्ठा पर पार्टी हाईकमान के अपने समीकरण भारी पड़ जाते हैं। जब प्रयोग विफल होते दिखने लगता है, तब मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है। यह भी देखा गया कि कार्यकाल के पहले दौर में वफादार चुना जाता है, लेकिन चुनाव करीब आते ही जिता सकने वाले की तलाश होती है। बाद वाले के लिए यह कांटो भरा ताज जैसा होता है। उत्तराखंड की पहली सरकार में भगत सिंह कोश्यारी को सरकार चलाने को अंतिम पांच माह मिले। तीसरी विधानसभा के कार्यकाल में भुवन चंद्र खंडूरी को अंतिम सात माह मिले। वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी के पास भी काम के लिए सात माह ही बचे हैं।

असंतोष का तूफान फिलहाल शांत : धामी के नाम की घोषणा होते ही पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता अपनी नाराजगी और निराशा सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने से नहीं चूके। सतपाल महाराज, डॉ. हरक सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल जैसे वरिष्ठ नेताओं को मनाने के लिए प्रदेश के बड़े नेताओं को ही नहीं, पार्टी हाईकमान को भी सक्रिय होना पड़ा और साझा प्रयास कामयाब हुए। अब माहौल शांत है। युवा मुख्यमंत्री सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हुए दिख भी रहे हैं। यह आगे समय ही बताएगा कि यह फौरी विराम है या स्थायी समन्वय। जो असंतोष दिखाई दिया और जहां से दिखाई दिया, उसके मंतव्य भी भिन्न-भिन्न थे। एक तो उन दिग्गजों ने निराशा दिखाई, जो इस बार मुखिया की कुर्सी के लिए खुद का नंबर देख रहे थे। दूसरे उन्होंने असंतोष जताया जिन्हें कैबिनेट में फिर जगह मिलने पर संशय था या कम महत्व मिलने की आशंका थी, क्योंकि प्रदेश भाजपा की गुटीय राजनीति में धामी उतने तटस्थ नहीं रहे, जितने तीरथ। विरोध दिखा कर वे अपनी जगह और महत्व को भाजपा में उच्चस्तरीय मान्यता दिलाने में कामयाब रहे। तीसरा फैक्टर उस आधी भाजपा का भी है, जो पिछले कुछ वर्षों के दौरान कांग्रेस छोड़ पार्टी में आई है। 12 सदस्यीय इस कैबिनेट में पांच सदस्य वही हैं। भविष्य में कहीं भी वे उपेक्षित और बाहरी न समझे जाएं, इसलिए ताकत का अहसास कराने का इससे बेहतर क्या मौका हो सकता था। खैर, अब सबने मिल कर पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य के विकास के लिए काम करने का संकल्प लिया है, लिहाजा किसी आशंका को उठाना विपक्ष का काम या नकारात्मक दिमाग की उपज ही कही जाएगी। चुनाव की दहलीज पर खड़े नेताओं के हित में भी यह नहीं है, यह वे भी भलीभांति समझते हैं।

पलायन है बड़ी समस्या

उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और पुष्कर सिंह धामी के नए मुख्यमंत्री बनने की बात प्रदेश की जनता के लिए कोई नई नहीं है। इस्तीफों की यह परंपरा उसी दिन से चली आ रही है जब प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी ने त्यागपत्र दिया था। इसमें कोई दो मत नहीं कि नौ नवंबर, 2000 को उत्तर प्रदेश से पृथक हुए उत्तराखंड को विकसित और सुविधाओं से परिपूर्ण देखने की चाह प्रदेश के लोगों में अब भी शेष है। पलायन आज इस पहाड़ी राज्य की बड़ी समस्या बन गई है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में लाखों पहाड़ी लोग बसे हुए हैं। बुराड़ी और संतनगर तो दूसरे उत्तराखंड जैसे हो गए हैं। जहां पलायन से एक राज्य की संस्कृति और रीति-रिवाजों पर संकट मंडरा रहा है वहीं दूसरे राज्य भी बढ़ती जनसंख्या का बोझ झेल रहे हैं। इससे कई परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं-संसाधनों की आपूर्ति से लेकर पर्यावरण प्रदूषण तक।

आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड के 3,946 गांवों से करीब 1,18,981 लोगों ने स्थायी रूप से पलायन कर लिया है। घरों पर लटके ताले और मकड़ियों के जाले एक अलग व्यथा व्यक्त कर रहे हैं। इस पलायन पर रोक तभी लग सकती है जब वहां विकास होगा और लोगों तक उन मूलभूत सुविधाओं-स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की पहुंच होगी, जिनकी चाह में वे विवश होकर अपनी जन्मभूमि को छोड़ बड़े शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। और ये सुविधाएं उन तक तभी पहुंच पाएंगी, जब प्रदेश में एक स्थिर सरकार होगी, पर यहां तो स्थिति ही डगमग है। पिछले चार विधानसभा चुनावों में 11 मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति बेहद दुखद है। आज जनता को भी नहीं पता है कि आगे उनके प्रदेश की कमान किसके हाथों में रहेगी।

उत्तराखंड हर प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है। इनका इस्तेमाल कर इस पहाड़ी राज्य के विकास की गाथा लिखी जानी चाहिए। अब नए मुख्यमंत्री को अपना ध्यान प्रदेश की जनता की बुनियादी समस्याओं पर केंद्रित करना चाहिए।

खरी-खरी

कितने अजीब रिश्ते हैं यहां पर

शशांक दुबे

कितना अंतर है इन फिल्मी सितारों और हम मिडिल क्लास वालों में। अब देखिए ना, लाकडाउन में एक फिल्मी सितारे को कुछ दिन अपनी पत्नी के साथ रहने का मौका मिला, साथ रहे तो एक-दूसरे को समझने लगे और फिर समझते-समझते यही समझ आया कि अपन तो साथ रहने लायक हैं ही नहीं। बड़े लोगों के बड़े-बड़े चोचले! अपने यहां तो शादी होते ही पति-पत्नी को बजट के हिसाब से हनीमून पैकेज पर सिर्फ इसीलिए भेजा जाता है, ताकि वे शुरू में ही एक-दूसरे को ढंग से समझ लें। हालांकि यह बात दीगर है कि वे सारा समय एक-दूजे को समझने के बजाय फोटो खिंचवाने और उसे इंटरनेट मीडिया पर चिपकाने में जाया कर देते हैं। समझने का मौका तो उन्हें हनीमून से लौटकर घर-गृहस्थी की चक्की में उलझने के बाद मिलता है।

शादी से पहले वाट्सएप पर हुई चैटिंग से पति को सच्ची का समझदार होने की खुशफहमी पाल बैठी पत्नी गृहस्थी में आते ही पति की आदतें और हरकतें 'सुधारने' के काम पर लग जाती है। कुछ दिन तो वह पति को समझाने की कोशिश करती है, फिर गृहस्थी की चक्की में पिसते-पिसते कब इन आदतों को उसकी 'क्वालिटी' मान बैठती है, पता ही नहीं चलता। दूसरी ओर पति भी फिर वही तुअर की दाल बनने या पत्नी द्वारा पार्टी के लिए सख्ती से मना कर दिए जाने जैसे हादसों पर कुछ दिन तक तो टेस्ट में शून्य पर आउट होने वाले खिलाड़ी की तरह मुंडी लटकाता है, फिर 'समझौता गमों से कर लो' गाना गाने लगता है। पर तलाक! तौबा, तौबा! भई एक-दूजे को समझने का मतलब यह थोड़े ही है कि हम इतने समझदार हो जाएं कि सिर्फ मीठा-मीठा गप करें और कड़वा-कड़वा थू करते हुए किनारा कर लें। रिश्ते हैं, कोई किराये की साइकिल नहीं।

शुक्र है कि फिल्मी कलाकारों के गीत गुनगुनाने और उन्हीं की तरह कपड़े बदलने वाला हमारा मध्यवर्ग उनकी तरह पत्नियां बदलने जैसी निर्लज्जता पर उतारू नहीं हुआ है, वरना कोरोना के इस कहर के बीच लाख संकटों के बावजूद मजबूती से खड़ा हमारा पारिवारिक ताना-बाना कभी का चूर-चूर हो चुका होता।

ट्वीट-ट्वीट

मोहन भागवत जी के एक बयान ने कितनों को एक्सपोज कर दिया। मुस्लिम वोट के चक्कर में जिन पार्टियों ने हिंदू मुस्लिम के साथ रहने की बात में भी मीनमेख निकाल दी उनमें से किसी को भी ओवैसी के हिंदुत्व को कोसने से कोई दिक्कत नहीं हुई। ये है इन पार्टियों का सेक्युलर चेहरा।
सुशांत सिन्हा@SushantBSinha

मंत्रिपरिषद में फेरबदल और विस्तार के बीच मेरे कुछ सुझाव हैं। ज्योतिरादित्य और जय पांडा को महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपे जाने चाहिए। जावडेकर से सूचना प्रसारण लेकर वह स्मृति ईरानी को दिया जाए। रविशंकर प्रसाद पर विधि या आइटी में से किसी एक विभाग का बोझ हल्का किया जाए। जयशंकर जैसी बाहरी प्रतिभाओं को शामिल करना चाहिए। पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय में लाकर, सीतारमण को वाणिज्य मंत्रालय की कमान सौंपनी चाहिए।
मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant



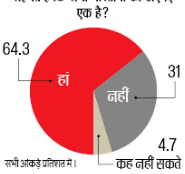
अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने सबसे बड़े एयरबेस बगराम को रातोंरात घुप्प अंधेरे में चोरी-छिपे ही छोड़ दिया। अब अफगानिस्तान को एक बार फिर गृह युद्ध, उथल-पुथल और युद्ध पिपासु आतंकियों की उर्वर भूमि बनने के लिए छोड़ दिया गया है।
शेखर गुप्ता@ShekharGupta

अपना मूल काम ठीक से करते रहिए, श्रेष्ठता प्राप्त कीजिए, किसी एक काम के लिए लोग आपको तलाशें, इतना भर कर लीजिए। पर्याप्त है। हर्ष वर्धन त्रिपाठी@MediaHarshVT

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या आप मोहन भागवत के इस बयान से सहमत हैं कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है?



सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद ही विधानसभा चुनाव होने चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

हो जाती पैदा तभी 'डीएनए' में खोट,
आ जाता है बीच में जब चुनाव का वोट।
जब चुनाव का वोट खड़ा हो जाता हौवा,
कह देते कुछ लोग कान ले भागा कौवा!
यह बेचारी आंख कान को देख न पाती,
बस कौवे को ढूंढ-ढूंढ पागल हो जाती!!
- ओमप्रकाश तिवारी



जगदीश त्रिपाठी
स्टेट डेस्क प्रभारी, हरियाणा

हरियाणा डायरी

भाजपा को भी अजय की रिहाई का इंतजार

प्रदेश के पांच बार मुख्यमंत्री रह चुके चौधरी ओमप्रकाश चौटाला शिक्षक भर्ती प्रकरण में सजा पूरी कर आ चुके हैं। अब वह राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। चौटाला के राजनीति में सक्रिय होने से उनके छोटे पुत्र अभय चौटाला और उनका दल इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) मजबूत होंगे। चौटाला सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पहुंचाएंगे। यह भाजपा के लिए फायदेमंद होगा, पर चौटाला की सक्रियता से सबसे अधिक नुकसान उनके अपने ही पौत्र दुष्यंत चौटाला और उनके दल जननायक जनता पार्टी (जजपा) को होगा, ऐसा लोगों का अनुमान है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि दुष्यंत और उनकी पार्टी का जनाधार एकदम दरक जाएगा, क्योंकि छह-सात महीने बाद दुष्यंत के पिता अजय चौटाला भी सजा पूरी कर आ जाएंगे और अपने पुत्र को मजबूत करने का हरसंभव प्रयास करेंगे। सो, दुष्यंत को तो उनके आने का इंतजार है ही, भाजपा को भी है, क्योंकि दुष्यंत जितना मजबूत होंगे, चौटाला और हुड्डा उतने ही कमजोर होंगे। निश्चित रूप से ओमप्रकाश चौटाला जाट मतदाताओं पर प्रभावी पकड़ रखते हैं, पर अजय चौटाला के भी संबंध-संपर्क जाट समुदाय में कम नहीं हैं। अजय के समर्थक गैर जाट समुदाय में भी हैं।

वास्तव में जब तक ओमप्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे। इनेलो का नेतृत्व उनके हाथों में रहा, तब तक संगठन का सारा काम अजय ही करते रहे। उनमें लोगों को जोड़ने की जबरदस्त कला है। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवतदयाल शर्मा के पुत्र राजेश शर्मा उनके आत्मीय व्यवहार के कारण इनेलो से जुड़े। दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया। उन्होंने मृत्यु से पहले अजय चौटाला को मैसेज किया था-आप जैसे प्यारे इंसान दुनिया में बहुत कम हैं। इस घटना का उल्लेख केवल इसलिए कि ओमप्रकाश चौटाला की वापसी से भले ही दो-चार पुराने लोग जो अन्य दलों में चले गए हैं, वापस आ जाएं, लेकिन अजय जब सक्रिय राजनीति में फिर से एंट्री करेंगे तो बहुत से मजबूत नेता जजपा का दामन थाम सकते हैं। फिर अजय की जो मोहक भाषण कला है, उसका लाभ भी जजपा को मिलेगा। यद्यपि भाजपा को समर्थन देकर उसकी सरकार बनवाने के बाद दुष्यंत और उनके छोटे भाई दिग्विजय से उनके अपने जाट समुदाय के बहुत से युवा खफा हैं, इससे उनकी लोकप्रियता कम जरूर हुई है, पर खत्म नहीं हुई है।

हिसार से सांसद चुने जाने के बाद 26 वर्षीय दुष्यंत ने जबरदस्त सक्रियता दिखाई और उन्हें युवा रोल माडल मानने लगे। इसमें दुष्यंत की अपनी छवि और श्रम तो था ही, उनके छोटे भाई दिग्विजय की रणनीति भी थी, जो छात्रों के बीच काम कर रहे थे। और छात्रों में जितनी उनकी लोकप्रियता थी, उतनी लोकप्रियता हरियाणा में कभी भी किसी छात्र नेता की नहीं रही।



छह-सात महीने बाद दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला भी सजा पूरी कर रिहा हो जाएंगे। फाइल

पारिवारिक कलह के बाद जब दोनों भाई अपने चाचा अभय चौटाला से अलग हुए और चौधरी ओमप्रकाश चौटाला ने अभय का पक्ष लिया तो अजय ने अपने बेटों को अलग कर नई पार्टी जननायक जनता पार्टी बनाई। दोनों भाइयों ने अपने बल पर जजपा को खड़ा किया। विधानसभा चुनावों में जजपा को दस सीटें भी मिल गईं, जबकि इनेलो से एकमात्र सीट अभय चौटाला ही निकाल पाए, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद दुष्यंत के सामने धर्मसंकट हो गया। वह कांग्रेस का सपोर्ट कर हुड्डा की सरकार बनवा दें। विपक्ष में बैठें या भाजपा को समर्थन देकर सरकार में शामिल हों। दुष्यंत को पता था कि अपने समुदाय का मुख्यमंत्री बनाने का सपना संजोने वाले उनके समुदाय के अधिकतर लोग उनके भाजपा से गठबंधन करने से नाराज हो जाएंगे, पर उन्होंने अपने पिता की सलाह पर भाजपा से गठबंधन करने का फैसला लिया। और दुष्यंत के भविष्य के लिए यही फैसला सर्वाधिक सुरक्षित था। दुष्यंत यदि हुड्डा को सपोर्ट कर उनकी सरकार बनवा भी देते तो हुड्डा उनका भविष्य चौपट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा की राजनीति में स्थापित करना है। इसके लिए वे 2005 से ही प्रयास कर रहे हैं।

दूसरी तरफ दुष्यंत ने पहली बार में ही कुलदीप बिश्नोई जैसे दिग्गज को पराजित करते हुए लोकसभा में प्रवेश किया और अपने व्यक्तित्व के बल पर सदन में विशेष छवि बनाने में सफल रहे। यदि दुष्यंत विपक्ष में बैठने का फैसला करते तो भाजपा के रणनीतिकार निर्दलियों के बल पर सरकार तो बना ही लेते, जजपा में भी तोड़फोड़ करने से बाज नहीं आते। सो, दुष्यंत उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन इससे उनके जनाधार को जो क्षति पहुंची अब उसकी क्षतिपूर्ति कैसे हो, यह उनके लिए चिंता का विषय है। जैसे हर पिता अपने पुत्र की चिंता को दूर करता है, वैसे ही उनके पिता भी उन्हें इस चिंता से मुक्त करेंगे और अपने करिश्माई व्यक्तित्व से जजपा का जनाधार वापस लाने में ही नहीं, उसे बढ़ाने और मजबूत करने में भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे, इसका दुष्यंत और दिग्विजय को विश्वास है। बस इंतजार उनके बाहर आने का है।

मंथन



रिजवान अंसारी
शोध अध्येता

एक देश, एक राशन कार्ड से बढ़ेगा समावेशन

यदि एक देश, एक राशन कार्ड योजना पूरे देश में सफलतापूर्वक लागू हो जाती है तो यह देश में भुखमरी और कुपोषण जैसे कई सवालों के जवाब भी तलाश लेगी

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक एक देश, एक राशन कार्ड योजना को लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के मुताबिक ऐसे हर परिवार के लिए और परिवार के हर सदस्य के लिए राशन-पानी का इंतजाम उसी स्थान पर होना चाहिए, जहां वे रह रहे हों। गौरतलब है कि पिछले साल जब पूरी दुनिया पहली बार कोरोना संकट की मार झेल रही थी, समस्याओं के समाधान के लिए नए-नए उपायों पर बल दिया जा रहा था, तब प्रवासी मजदूरों के भरण-पोषण की समस्या ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। जिन राज्यों में मजदूर काम करने गए थे, उन राज्यों के राशन कार्ड नहीं होने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ वे नहीं उठा पा रहे थे। तब इस योजना की जरूरत बड़ी शिद्दत से महसूस की जा रही थी। तब मोदी सरकार ने भी 'एक देश, एक राशन कार्ड' योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का एलान किया था। हालांकि इसकी शुरुआत अप्रैल, 2018 में ही हो गई थी, लेकिन कई सारी समस्याओं के कारण इसका दायरा तय समय में नहीं बढ़ाया जा सका।

यह भी एक तथ्य है कि मार्च, 2021 से पहले 100 फीसद नेशनल पोर्टेबिलिटी हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। इससे जो मजदूर जिस राज्य में हैं, उन्हें उसी राज्य में उनके मूल राज्य के राशन कार्ड पर अनाज मिल जाता, लेकिन जून गुजर जाने तक भी इस लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका। अब अदालत ने राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को इस बाबत सख्त निर्देश दिए हैं। इसके मद्देनजर असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल डेवलप करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। इस योजना के तहत लाभार्थी किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के सरकारी दुकानों से राशन खरीदने में सक्षम हो पाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश का एक मजदूर अगर हैदराबाद में काम करने गया है तो वह उत्तर प्रदेश वाले राशन कार्ड पर हैदराबाद में भी सब्सिडी वाला अनाज प्राप्त कर सकता है। साथ ही अगर कोई मजदूर अपने राज्य के अंदर ही एक जिले से दूसरे जिले में काम करने जाता है तो वहां भी वह राशन कार्ड की सुविधा हासिल कर सकता है। हालांकि इसके लिए मोबाइल सिम कार्ड की तरह ही राशन कार्ड को भी पोर्टेबल कराना जरूरी होगा। पहले तो राशन कार्ड को आधार से लिंक करना होगा। इसके बाद सिम कार्ड पोर्टेबिलिटी में हम जिस तरह नेटवर्क कंपनी बदलते हैं उसी तरह इस योजना में हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान बदलनी होगी।

हालांकि अगर कोई उपभोक्ता एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो उसे केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का ही लाभ मिल सकेगा। यदि कोई राज्य अपने स्तर पर किसी प्रकार की खाद्य सुरक्षा योजना चला रहा है तो उस राज्य के प्रवासी किसी दूसरे राज्य में यह सुविधा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। दरअसल सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राज्यों के नियमों में अंतर है। कहीं केंद्र सरकार से भी कम मूल्यों पर अनाज दिए जाते हैं तो कहीं मिलने वाले सामानों की संख्या ज्यादा होती है। ऐसे में राज्य के भीतर ही राज्य की योजनाओं का लाभ उठाने में तो कोई परेशानी नहीं होगी, पर दूसरे राज्यों में जाने पर वे विशेष लाभ से वंचित रहेंगे। यह योजना उन राशन की दुकानों में ही लागू की जा सकती है, जहां प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनें उपलब्ध हैं। दरअसल इस स्कीम को लागू करने का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर सब्सिडी आधारित अनाजों से वंचित न रहे।

इससे फर्जी राशन कार्ड की समस्या भी खत्म होगी। सभी राशन कार्ड को अनिवार्य रूप से आधार से लिंक करने और सभी उपभोक्ताओं का विवरण प्वाइंट ऑफ सेल मशीन पर आ जाने से कोई भी व्यक्ति फर्जी राशन कार्ड नहीं रख सकेगा, क्योंकि सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों की मशीनें एक-दूसरे से लिंक होंगी। इस योजना की जरूरत इस तरह समझिए कि भारत में काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना एक सामान्य बात हो चुकी है। कभी-कभी लोग पांच-छह महीने के लिए ही कहीं जाते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। यह भी देखा गया है कि परिवार का एक ही सदस्य काम के लिए पलायन करता है, जबकि बाकी लोग घर पर ही रहते हैं। ऐसे में किसी एक जगह ही राशन लेना संभव हो पाता है, लेकिन एक देश, एक राशन कार्ड योजना से हर सदस्य के हिस्से का राशन किसी भी स्थान से प्राप्त किया जा सकता है। यह योजना लाभार्थियों को अपने पसंद के राशन वितरक (डीलर) को चुनने का मौका भी देगी। अगर कोई डीलर राशन के आवंटन में गड़बड़ी करता है तो लाभार्थी तुरंत किसी अन्य दुकान की सेवा ले सकता है। कहने की जरूरत नहीं कि पूरे देश में सफलतापूर्वक लागू हो जाने पर यह योजना भुखमरी और पोषण जैसे कई सवालों के जवाब तलाश लेगी।



अब गरीब देश में कहीं से भी सस्ता राशन प्राप्त कर सकेंगे। फाइल

23 हजार छात्र प्रोन्नत किए गए बगैर परीक्षा के उप्र के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार पूरे देश भर में है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 7 जुलाई, 2021

उत्तराखंड

अभी हारा नहीं है कोरोना

कोरोना संक्रमण की दर कम होने के साथ ही उत्तराखंड के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार होने लगे हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से लोग गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। खासकर मसूरी, नैनीताल, चोपता, औली में वीकेंड पर चहल-पहल दिख रही है। मसूरी और नैनीताल पर्यटकों के फेवरेट स्पॉट बने हुए हैं। स्थिति यह कि पर्यटकों की संख्या बढ़ने के चलते यहां एंट्री बंद भी करनी पड़ रही हैं। निःसंदेह राज्य के लिए यह शुभ संकेत है। गुजरे डेढ़ साल से यहां पर्यटन गतिविधियां पूरी तरह ठप हैं। होटल व्यवसायी लगातार पर्यटन गतिविधियां संचालित करने की मांग करते आ रहे हैं। ऐसे में पर्यटकों की चहलकदमी कारोबारियों के चेहरे पर चमक लाती दिख रही है।

प्रदेश सरकार भी पर्यटन और अन्य व्यापारिक गतिविधियां शुरू करने की पक्षधर है, इसीलिए कोविड कर्फ्यू में चरणबद्ध ढंग से ढील दी जा रही है। वीकेंड पर भीड़-भाड़ को देखते हुए मसूरी और नैनीताल में रविवार का दिन कोविड कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है। प्रदेश के अन्य हिस्सों में यह बंदी का दिन है। इतने तक तो ठीक है, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तय गाइडलाइन के अनुपालन में जो लापरवाही सामने आ रही है, वह चिंता का कारण बनी हुई है। बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण के साथ ही कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता रखी गई है, पर इसका सरसरी तौर पर भी अनुपालन नहीं हो रहा है। मास्क और दो गज की दूरी जैसे मानकों का खुल्लमखुल्ला मखौल उड़ाया जा रहा है। जांच की समुचित व्यवस्था नहीं नजर आ रही है। सीमावर्ती बैरियरों पर बेरोकटोक आवागमन हो रहा है।

> उत्तराखंड में कोरोना के मामले घटे जरूर हैं, लेकिन चिंता बरकरार है। कोविड कर्फ्यू में ढील के दौर में स्वास्थ्य महकमे की सक्रियता कम होना इस चिंता को बढ़ा रहा है

यही वजह है कि उत्तराखंड में अब भी रोजाना दिल्ली और दूसरे राज्यों की तुलना में कोरोना संक्रमण के अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके स्वास्थ्य महकमा उतना सक्रिय नहीं आ रहा है, जितना उसे होना चाहिए। यही नहीं, कोरोना जांच का ग्राफ भी तेजी से गिरा है। जबकि कोविड कर्फ्यू में ढील के साथ ही विभाग को सैंपलिंग बढ़ा देनी चाहिए थी। लेकिन हो इसके उलट रहा है। विभाग की इस उदासीनता से माथे पर चिंता की लकीरें खिंची आ रही हैं। स्वाभाविक भी है, जिस बुरे दौर से राज्यवासी डेढ़ साल से गुजर रहे हैं, वह स्थिति फिर न आए, यह सभी की जिम्मेदारी है। केवल सरकारी तंत्र के बूते रहकर कोरोना को हराने की मुहिम अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पाएगी। आमजन को भी अपना दायित्व समझना होगा।

उत्तर प्रदेश

संरक्षण भी हो सुनिश्चित

उत्तर प्रदेश में एक जुलाई से शुरू हुआ पौधारोपण फिर नया कीर्तिमान गढ़ने में सफल रहा है। इनमें सर्वाधिक 25.51 करोड़ पौधे रविवार को रोपे गए। प्रदेश की आबादी को केंद्र में रखकर 'एक व्यक्ति-एक पौधा' का लक्ष्य अंततः पूरा हुआ। वन विभाग ने 1.30 करोड़ पौधे गंगा और उनकी सहायक 80 नदियों के किनारे रोपे जाने का दावा किया है। कोविड महामारी में दिवंगत हुए प्रियजन की याद में बनाई गईं करीब 19 हजार स्मृति वाटिकाओं में भी पौधे रोपे गए। लोक निर्माण विभाग ने 175 मार्गों की करीब 875 किलोमीटर सड़कें हर्बल मार्ग के लिए चयनित की हैं। यह हरित सिलसिला पूरे माह चलना है, क्योंकि इस वर्ष 30 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य है। योगी सरकार के कार्यकाल में कुल 100 करोड़ पौधे रोपे जा चुके हैं। बीते वर्ष भी रिकार्ड 25.87 करोड़ पौधारोपण हुआ था। पौधारोपण अभियान दशकों से सालाना जलसा जैसा मनता आया है, लेकिन न तो हरियाली बढ़ी और न ही वन क्षेत्र ही बढ़ा नजर आया। असल में पौधे लगाना आसान है, बचाना कठिन। सरकारें रोपने में जोर देती रहीं, देखभाल भूल गईं, जबकि पौधे तो बच्चों सरीखी देखरेख मांगते हैं। हरियाली नहीं बढ़ने से ऐसी धारणा भी बनी कि सरकारी पौधे बस फाइलों में ही लगते और बढ़ते हैं। वर्ष 2018-19 में बलिया में पौधारोपण के नाम पर पांच लाख रुपये का घोटाला इसी धारणा को बल देता है। यहां जिन खेतों में पौधे रोपना दर्शाया गया था, वहां जांच करने गई सोशल आडिट टीम को फसलें उगी हुई मिली थीं। हालांकि 2019 की फारेस्ट सर्वे आफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि दो वर्ष में उप्र का वन क्षेत्र 127 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। वृक्षावरण में भी प्रदेश (3.05 प्रतिशत), राष्ट्रीय औसत (2.89 प्रतिशत) से आगे निकल चुका है। यह रफ्तार न सिर्फ बरकरार रखनी चाहिए, बल्कि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्न भी करते रहने चाहिए। यद्यपि क्विक कैप्चर एप के जरिये वन विभाग ने पौधारोपण स्थलों की जियो टैगिंग की है, लेकिन तकनीक तभी कारगर सिद्ध होगी, जब भौतिक रूप से भी निगरानी ठीक से की जाएगी।



पौधों को रोपने के साथ उनकी देखरेख भी जरूरी है। फाइल

> वन विभाग ने पौधारोपण स्थलों की जियो टैगिंग की है, लेकिन तकनीक तभी कारगर सिद्ध होगी, जब भौतिक रूप से भी निगरानी ठीक से की जाएगी

झारखंड

बाल कैदियों की चिंता

झारखंड के बाल सुधार गृहों का हाल बुरा है। राजधानी रांची समेत विभिन्न जिलों में स्थित दो दर्जन से अधिक बाल सुधार गृहों में कहीं न कहीं से अक्सर बाल कैदियों के भाग जाने की खबरें आती रहती हैं। पिछले महीने ही रांची और कोडरमा से पांच बाल कैदी फरार हो चुके हैं। हालांकि इनमें रांची से भागे दो बाल कैदी बाद में पकड़े गए। अभी एक महीने पहले ही रांची के डुमरदगा में स्थित बाल संरक्षण गृह में शराब, सिगरेट, गांजा पीते हुए और पार्टी मनाते हुए बाल कैदियों का वीडियो वायरल हुआ था। इनके पास मोबाइल भी था। बाल संरक्षण गृहों की यह हालत बता रही है कि बच्चों और किशोरों के सुधार के लिए बनाए गए संरक्षण गृहों में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है।

18 वर्ष से कम उम्र के अपराधियों के लिए इन केंद्रों के निर्माण की परिकल्पना ही यही रही है कि अपराध में आरोपित बच्चे और किशोर जब यहां से निकलें तो अच्छे नागरिक बनकर निकलें। उन्हें बड़ी उम्र के कैदियों के साथ नहीं रखने का मकसद भी यही रहा है कि वह सोच-समझ कर अपराध करने वाले अपराधियों से दूर रहें। उनके मन-मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव नहीं पड़े। अपराध में आरोपित होने के बाद भी इनके आश्रय स्थल को जेल के बजाय संरक्षण गृह या सुधार गृह कहा जाता है। यह सब इसलिए ताकि अच्छी राह से भटके बच्चों को अच्छी राह पर लाने की गुंजाइश बनी रहे। ये पढ़े-लिखे और अपराध की विचारधारा को छोड़कर कर अच्छे इंसान बनें। इस उद्देश्य में हम तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक इन्हें सुधारने के गंभीर और इमानदार प्रयास न हों। गलत माहौल में रहकर, कुसंगति में पड़कर, शातिर अपराधियों के हाथ के खिलौने बनकर या अच्छे मार्गदर्शन के अभाव में ये बच्चे गलत रास्ते पर चल पड़े हैं।

> बाल संरक्षण गृहों की व्यवस्था सुधार कर हम बाल अपराधियों को अच्छा इंसान बनाने का उदाहरण पेश कर सकते हैं



अच्छी नहीं है बाल सुधार गृहों की हालत। फाइल

संरक्षण गृहों पर इनमें लोकतंत्र की मुख्यधारा के प्रति भरोसा पैदा करने की जिम्मेदारी भी है। इन्हें आश्रय गृहों में भगवान भरोसे छोड़ देने भर से इनके जीवन में सुधार नहीं हो सकता। जर्जर और सुविधाविहीन भवनों में चल रहे ज्यादातर संरक्षण गृहों की न तो देखरेख हो रही है ना ही निगरानी। गंभीर प्रयास किए जाएं तो ये आश्रय गृह अपराधियों को अच्छा इंसान बनाने की नर्सरी साबित हो सकते हैं।

बंगाल

पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल

विधानसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद से बंगाल में हुई हिंसा की जांच के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को एक जांच समिति बनाने का निर्देश दिया था। उसी अनुसार एनएचआरसी समिति गठित कर जांच कर रही है। प्राथमिक रिपोर्ट मिलने के बाद हाई कोर्ट ने जो कहा वह सर्वविदित है। बावजूद इसके बंगाल में हिंसक घटनाएं नहीं थम रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को दावा किया कि बांकुड़ा जिले के सोनामुखी से उनके पार्टी विधायक दिबाकर घरामी पर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमला किया। हालांकि पुलिस ने इसकी जानकारी होने से ही इन्कार कर दिया।

बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने देर रात एक ट्वीट कर आरोप लगाया कि घरामी पर मानिक बाजार पंचायत क्षेत्र में 'तृणमूल कांग्रेस के गुंडों' ने हमला किया। हमले में भारतीय जनता पार्टी के सात कार्यकर्ता घायल हो गए और उन्हें बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेजा गया है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि ऐसे हमले क्यों हो रहे हैं? वह भी उस समय जब हाई कोर्ट के निर्देश पर चुनाव बाद हिंसा की जांच के लिए एनएचआरसी की टीम बंगाल में मौजूद है। अभी कुछ दिन पहले ही कोलकाता के जादवपुर इलाके में एनएचआरसी की जांच टीम के साथ बदसलूकी की गई। आखिर ऐसे हमले और बदसलूकी करने वाले लोग कौन हैं? इनमें इतने दुस्साहस कहां से आया?

> भाजपा ने रविवार को दावा किया कि बांकुड़ा जिले के सोनामुखी से उनके पार्टी विधायक दिबाकर घरामी पर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमला किया। हालांकि पुलिस ने इसकी जानकारी होने से ही इन्कार कर दिया

यदि पुलिस प्रशासन का प्रश्रय न हो तो इस तरह के हमले एवं बदसलूकी करना तो दूर किसी से ऊंची आवाज में बिना किसी दोष के कोई बात भी नहीं कर सकता। यही वजह है कि हाई कोर्ट को निर्देश देना पड़ा है कि अब तक जितनी भी हिंसा की घटनाएं हुई हैं सबकी एफआइआर दर्ज की जाए। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट ने पहली बार ऐसा निर्देश दिया है। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें राज्य पुलिस-प्रशासन की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठे थे और कोर्ट में उनकी फजीहत हुई थी। यहां यदि कोई मामला विपक्षी दलों से जुड़ा है तो पुलिस अति सक्रियता के साथ कार्य करती है, लेकिन सत्तारूढ़ दल से जुड़ा हो तो प्राथमिकी दर्ज करना तो दूर शिकायत भी स्वीकार नहीं करती। ऐसे में हिंसा और अपराध कैसे थमेगा? जब बिना झंडा और राजनीति का रंग देखे कार्रवाई होगी तभी हिंसा थमेगी। यदि प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना है तो पुलिस को हिंसा पर रोक लगानी होगी।

रामनगरी को मिलेगी सीता अशोक की हरियाली

रघुवरशरण, अयोध्या

युगों पूर्व रावण ने मां सीता का हरण कर लंका की जिस अशोक वाटिका में रखा था, उस वाटिका के अशोक अब हर तरफ नजर आने वाले अशोक के यह वृक्ष नहीं थे। वह अशोक अलग प्रकार का था और साधारण अशोक की तरह पुष्प विहीन नहीं था। इसमें पीले और केसरिया रंग के फूल खिलते थे।

गुड़गांव की पर्यावरण प्रेमी प्रतिभा साहनी अयोध्या जिला के ही ग्राम बहराएं निवासी प्रगतिशील किसान के साथ मां सीता की गहन साधना के साक्षी इन वृक्षों से रामनगरी को आच्छादित करने की तैयारी में हैं। इस मुहिम की शुरुआत वह इसी महीने की 24 तारीख को गुरु पूर्णिमा की दिव्य बेला में करना चाहती हैं। वह लोगों को सीता अशोक के पौधे उपलब्ध कराएंगी और इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ रोपने और संरक्षित करने का आह्वान करेंगी। उनकी प्राथमिकता धार्मिक-पौराणिक महत्व के मंदिरों व कुंडों सहित विद्यालयों एवं चिकित्सालयों में इस पौधे का रोपण कराने की है। प्रतिभा के अनुसार सीता अशोक के वृक्ष में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करने तथा समृद्धि का वातावरण तैयार करने की अपूर्व सामर्थ्य है।

कम से कम एक पौधा राम मंदिर परिसर में रोपित हो: प्रतिभा कहती हैं, अधिक न भी सही तो सीता अशोक का कम से कम एक पौधा रामजन्मभूमि परिसर में रोपित होना चाहिए।

मुंबई की नर्सरी से लाये जाएंगे पौधे: मुहिम से जुड़े रामनगरी के ही प्रगतिशील किसान राकेश दुबे बताते हैं कि प्रख्यात वन्य प्रेमी वीना राव के निर्देशन में सीता अशोक के पौधों की नर्सरी मुंबई में विकसित की गई है और वीना राव के ही सहयोग से रामनगरी में रोपण के लिए मुंबई की नर्सरी से एक हजार पौधे लाए जाएंगे। राकेश के अनुसार युगों पूर्व की विरासत के वाहक सीता अशोक के वृक्ष रामनगरी सहित उत्तर भारत में भले ही लुप्तप्राय हो गए, लेकिन तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे दक्षिण के राज्यों में इनका वजूद है।

मां सीता ने की थी इन वृक्षों से प्रार्थना: रामकथा मर्मज्ञ जगद्गुरु रत्नेश प्रपन्नाचार्य के अनुसार मां सीता 11 महीने 14 दिन तक अशोक वाटिका में रह कर श्रीराम से पुनर्मिलन की साधना के दौरान वे वाटिका के वृक्षों से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे अशोक अपना नाम सार्थक करते हुए हमारा शोक दूर करो।



विरासत की वाहक सीता अशोक। फाइल फोटो

हर घर का होगा विशिष्ट नंबर

रविप्रकाश श्रीवास्तव, अयोध्या

रामनगरी स्मार्ट सिटी की ओर तेजी से बढ़ रही है। नगर को व्यवस्थित बनाने में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र के सभी भवनों का नए सिरे से डिजिटल डाटाबेस तैयार कराया जा रहा है। इसके लिए पहली बार जियोग्राफिकल इन्फार्मेशन सिस्टम (जीआइएस) का उपयोग हो रहा है। सेटेलाइट से प्राप्त नगर निगम क्षेत्र के मानचित्र की मदद से भवनों का डोर-टू-डोर जीआइएस सर्वे आरंभ हो चुका है। सर्वे के बाद भवनों का डिजिटल डाटा नगर निगम के पास उपलब्ध होगा। इस योजना के तहत प्रत्येक घर को विशिष्ट (यूनीक) नंबर भी आवंटित होगा, जो पुराने मकान नंबर के अतिरिक्त होगा।

तैयारी	
वार्डों की संख्या	60
कुल भवनों की संख्या	42,119
आवासीय भवन	38,263
व्यावसायिक भवन	3856

जीआइएस सर्वे के बाद मिले यूनीक नंबर के जरिये हाउस टैक्स व नगर निगम से जुड़ी भवन संबंधित अन्य जानकारी आनलाइन प्राप्त हो सकेगी। इससे उन भवनों का डाटा भी नगर निगम को मिल जाएगा, जो अभी तक रिकार्ड में नहीं है। इससे भवन की लोकेशन पता करने में भी आसानी होगी। जीआइएस सर्वे के बाद नगर निगम सीमा के प्रत्येक भवन स्वामी को हाउस टैक्स अदा करना पड़ेगा।

उप्र में हुतात्मा कारसेवकों के नाम पर बनेंगे मार्ग : केशव

जासं, अयोध्या : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को रामनगरी में बड़ा एलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब राम मंदिर आंदोलन में प्राणोत्सर्ग करने वाले हुतात्मा कारसेवकों के नाम पर मार्गों का निर्माण होगा।

करीब 15 अरब रुपये की 996 परियोजनाओं का लोकार्पण करने अयोध्या पहुंचे उपमुख्यमंत्री ने डा. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में कहा कि रामजन्मभूमि आंदोलन के बलिदानी कारसेवकों के घर तक मार्ग का निर्माण किया जाएगा। 'राम भक्त कारसेवक' के नाम से सड़क का निर्माण होगा। उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने राममंदिर के लिए एक करोड़ रुपये की धनराशि समर्पित की है। उप मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सेना के वीर जवानों व आंतरिक सुरक्षा में शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों के घर तक भी 'जय हिंद वीर पथ' का सरकार निर्माण कराएगी।

परमवीर अलबर्ट एक्का का निवास स्थल बनेगा संग्रहालय

जागरण संवाददाता, गुमला : शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशां होगा। 1971 की लड़ाई में दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले परमवीर अलबर्ट एक्का के निवास स्थल को राज्य सरकार संग्रहालय के रूप में विकसित करेगी। देर से ही सही, लेकिन सरकार की इस पहल से बलिदानियों को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी और उनके स्वजनों का सम्मान बढ़ेगा। इसी सम्मान की बाट जोहते-जोहते शहीद अलबर्ट एक्का की विधवा बलमदीना एक्का इस वर्ष 16 मार्च को दुनिया छोड़कर चली गईं। सरकार द्वारा उनके निवास स्थल को संग्रहालय बनाने से यह क्षेत्र पर्यटन के दृष्टिकोण से भी विकसित होगा। शहीद अलबर्ट एक्का से जुड़ाव के कारण ही जारी प्रखंड बना। लेकिन यहां विकास के पांव नहीं जम पाए हैं।

पर्यटन निदेशक ने मांगा है प्रतिवेदन : पर्यटन निदेशालय के निदेशक ने पत्र जारी कर परमवीर शहीद अलबर्ट एक्का के निवास स्थल को संग्रहालय के रूप में विकसित करने एवं वहीं पर उनकी एक प्रतिमा स्थापित करने संबंधी योजना पर विभाग के निर्णय से उपायुक्त को अवगत कराया है। साथ ही उपायुक्त से शीघ्र ही पूरा प्रस्ताव मांगा गया है। उपायुक्त ने पहले करते हुए मंगलवार को स्थल निरीक्षण के लिए प्रशासनिक टीम भेजी।

शहीद के परिजनों को मिलेगा सम्मान : परमवीर अलबर्ट एक्का के पुत्र विनसेंट एक्का प्रखंड कार्यालय जारी में तृतीय वर्ग में कार्यरत हैं। उनका मानना है कि सरकार की यह पहल शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

अब घर बैठे करें श्री अमरनाथ की वर्चुअल पूजा, प्रसाद भी मिलेगा

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने श्राइन बोर्ड की आनलाइन सेवा लांच की
- डाक विभाग के सहयोग से 48 घंटे में घर पहुंचेगा प्रसाद

कोरोना संक्रमण के कारण इस बार श्री अमरनाथ यात्रा रद होने के बावजूद शिवभक्तों को मायूस होने की कतई जरूरी नहीं। देशभर में बाबा बर्फानी के भक्त अब घर बैठे वर्चुअल पूजा, हवन और प्रसाद की आनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। पवित्र गुफा में पुजारी श्रद्धालुओं के नाम की पूजा करेंगे और श्राइन बोर्ड की ओर से 48 घंटे के भीतर प्रसाद श्रद्धालुओं को उनके घर पर पहुंचाने के प्रबंध किए जाएंगे। श्रद्धालु हवन और पूजन में लाइव भी जुड़ सकते हैं।

श्री अमरनाथ के श्रद्धालुओं को दर्शन के निजी अनुभव करवाने के उद्देश्य से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की विभिन्न आनलाइन सेवाओं को लांच किया। इस दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि देश विदेश में बैठे शिव भगत इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतिश्वर कुमार ने बताया कि श्रद्धालुओं के नाम पर वर्चुअल पूजा और दर्शन के साथ हवन, आनलाइन प्रसाद बुकिंग की सेवा शुरू कर दी गई हैं। श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट श्रीअमरनाथजीश्राइन.काम पर आनलाइन सेवा को बुक करवाया जा सकता है, जिसमें श्रद्धालुओं को वहां दिए लिंक को क्लिक करना होगा। श्रद्धालु बोर्ड एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। **प्रसाद के लिए 1100 रुपये, चांदी का सिक्का भी मिलेगा :** वर्चुअल पूजा के लिए 1100 रुपये देने होंगे। प्रसाद बुकिंग के लिए 1100 रुपये। प्रसाद के साथ श्रद्धालुओं को पांच ग्राम का श्री अमरनाथ जी का चांदी का सिक्का भी मिलेगा। 2100 रुपये के प्रसाद बुकिंग के साथ 10 ग्राम का चांदी का सिक्का मिलेगा और विशेष हवन 5100 से होगा। वर्चुअल पूजा या हवन पवित्र गुफा में पुजारी श्रद्धालुओं के नाम से करेंगे और मंत्र श्लोक उच्चारण करेंगे। विशेष वर्चुअल पूजा के लिए श्रद्धालु जियो मीट एप्लीकेशन के जरिए आनलाइन जुड़ सकते हैं। इससे श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के पवित्र शिवलिंग के दर्शन भी कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि डाक विभाग के सहयोग से 48 घंटों के भीतर श्रद्धालुओं को प्रसाद उनके घर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। जब बुकिंग हो जाएगी तो श्राइन बोर्ड लिंक शेयर करेगा इसमें समय और तिथि पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पर श्रद्धालुओं को मिल जाएगा। वर्चुअल पूजा और हवन की व्यवस्था स्लाट के जरिए होगी।

श्रद्धालु दिन में किसी भी समय कर सकते हैं दर्शन : नीतिश्वर कुमार ने बताया कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड माई जियो टीवी एप्लीकेशन पर अपना चैनल लांच करने जा रहा है। इसमें श्रद्धालु दिन में किसी भी समय दर्शन कर सकते हैं। ये सारे प्रबंध इस साल रद हुई यात्रा को देखते हुए उठाए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने नेशनल इनफार्मेटिक्स सेंटर के सहयोग से पोर्टल विकसित किया है। श्राइन बोर्ड आरती का सीधा प्रसारण भी कर रहा है।

जागरण विशेष

वैदिक ज्ञान से निकाली नाले की सफाई की तकनीक

'नाला से नदी' : नाले के प्रदूषित पानी में मिलाया जाता है जड़ी-बूटियों का घोल, कुछ ही दिनों में आए बेहतर नतीजे

गौरव सूद • पटियाला

पर्यावरण संरक्षण

नालों की सफाई के लिए बड़ी मशीनों का इस्तेमाल तो आम बात है, लेकिन जड़ी-बूटियों के घोल से गंदे पानी की सफाई नया प्रयोग है। वैदिक विज्ञान पर आधारित इस तकनीक में पानी को एक जीवित प्रणाली माना गया है, जिसका अपना उपचार व सफाई तंत्र है। इससे पानी में रहने वाली जलीय वनस्पतियों को पुनर्जीवित किया जाता है। प्रयोग के प्रारंभिक नतीजे उत्साहवर्धक हैं।

इन दिनों पंजाब में खत्म हो रहे जलस्रोतों व जलसंकट के समाधान के लिए पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) 'नाला से नदी' परियोजना चला रहा है। कुछ माह पहले पीपीसीबी ने नालों की सफाई के लिए चंडीगढ़ की इंपीरियम अर्थ एडवाइजर्स एलएलपी कंपनी से संपर्क किया और डेरा बस्सी (मोहाली), पटियाला और संगरूर की साइट पर काम का प्रस्ताव दिया।

इंपीरियम अर्थ एडवाइजर्स एलएलपी कंपनी दिल्ली की कंपनी वैदिक सृजन के साथ मिलकर काम करती है। वैदिक सृजन ने जड़ी-बूटियों का घोल बनाया है, जिसे काउनामिक्स हर्बल कंसंट्रेट नाम दिया गया है। कंपनी ने पायलट प्रोजेक्ट के लिए पटियाला को चुना। यहां के भारत नगर व धामोमाजरा गांव से होकर गुजरने वाले नाले की सफाई बड़ी चुनौती बनी हुई है। नाले के आसपास बहुत बड़ी आबादी होने के कारण पीपीसीबी पर दबाव भी ज्यादा है। धामोमाजरा नाले की चार साइटों की पहचान की गई। रोज सुबह चार से सात बजे के बीच जड़ी-बूटियों के इस घोल को पानी में मिलाया जाता है। बीते 10 मई को काम शुरू हुआ और परिणाम दिखने लगे। लोगों को पानी की दुर्गंध से छुटकारा मिल गया है। कई बीमारियों से जूझ रहे लोगों को राहत मिली है।

क्या है काउनामिक्स हर्बल कंसंट्रेट: काउनामिक्स हर्बल कंसंट्रेट जड़ी-बूटियों का घोल है। इसमें आक, आंवला, बबूल, बेल, अर्जुन, बरगद, चितावर, बन नींबू, भोटिया बादाम व ब्राह्मी आदि मिलाए जाते हैं।

मप्र व छत्तीसगढ़ में भी दिए नतीजे: कंपनी एक साल से ज्यादा समय से काम कर रही है। उसने इस तकनीक की शुरुआत छत्तीसगढ़ में मोतीपुर की काई लेक से की। मध्य प्रदेश में मंदाकिनी नदी का 500 मीटर का घाट साफ किया।

लोगों को मिली राहत: धामोमाजरा के राकेश कुमार के मुताबिक दुर्गंध के कारण पहले घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था, लेकिन अब ऐसी समस्या नहीं है। गांव के बरजिंदर सिंह ने कहा कि पहले नाले के नजदीक से गुजरना भी मुश्किल था। अब दुर्गंध बिल्कुल बंद हो गई है। गंदगी के कारण मच्छर ज्यादा लगते थे। बीमारियां फैलने का डर रहता था, अब स्थिति बेहतर है।

ऐसे होती है नाले की सफाई: काउनामिक्स हर्बल कंसंट्रेट को कम से कम चार महीने तक रोज पानी में तय मात्रा में डाला जाता है। नाले में इसे डालते हुए दो महीने पूरे होने वाले हैं। जिस एक किलोमीटर ड्रेन को शोधित किया गया है, वहां इस घोल से पानी को ब्लॉक करने वाले पदार्थ स्वतः पूरी तरह से घुल जाते हैं। इससे इस इलाके में नाला ओवरफ्लो नहीं होगा और पानी लोगों के घरों में नहीं घुसेगा। वाटर लॉगिंग नहीं होगी।



धामोमाजरा में नाले में मिलाया जा रहा काउनामिक्स हर्बल कंसंट्रेट • जागरण

> अभी प्रोजेक्ट के नतीजे सकारात्मक आए हैं। सही स्थिति के बारे में दो महीने के बाद ही पता चलेगा। अगर सब कुछ सही रहा तो भविष्य में इसे बड़े स्तर पर भी अपनाया जा सकता है।



प्रो. सतविंदर सिंह मरवाहा, चेयरमैन, पीपीसीबी

गाय को कचरा खाते देख मिला आइडिया

इस घोल को तैयार करने वाली कंपनी वैदिक सृजन के निदेशक मधुकर स्वयंभू ने बताया कि वह एक आइटी कंपनी से जुड़े थे। एक दिन गाय को नाले में कचरा खाते देखा। इससे विचार आया कि नालों की इस तरह से सफाई हो कि उसमें वनस्पतियों की बहुतायत रहे। उन्होंने वैदिक विज्ञान का अध्यन किया और लंबे अध्ययन व शोध के बाद काउनामिक्स हर्बल कंसंट्रेट के नतीजे पर पहुंचे। चूंकि आइडिया गाय से मिला इसलिए घोल का नाम काउनामिक्स हर्बल कंसंट्रेट रखा। 1008 जड़ी-बूटियों में से स्थान-विशेष और जरूरत के हिसाब से इनका घोल बनाने के लिए चयन किया जाता है।



मधुकर स्वयंभू

सीसीटीवी कैमरों से गंगोत्री-यमुनोत्री की लाइव मानिटरिंग

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी: केदारनाथ धाम की तर्ज पर उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री व गंगोत्री धाम भी सीसीटीवी कैमरों से जुड़ गए हैं। अब जिला मुख्यालय उत्तरकाशी को दोनों धाम से फुटेज मिलती रहेंगी। इनकी जिला कार्यालय व आपदा प्रबंधन कार्यालय से नियमित लाइव मानिटरिंग की जाएगी।

जिलाधिकारी उत्तरकाशी मयूर दीक्षित ने बताया कि आपदा के मद्देनजर संवेदनशील उत्तरकाशी जिले के दोनों धाम में 13 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए है। इससे आपदा के दौरान भागीरथी व यमुना नदी के जलस्तर पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही दोनों धाम में किए जा रहे पुनर्निर्माण कार्यों की भी लाइव मानिटरिंग की जा रही है। बताया कि यमुनोत्री धाम में चार और गंगोत्री धाम में नौ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सभी की अलग-अलग सजीव फुटेज देखने को मिल रही है।

12 लाख 31 हजार विदेशी कामगार हैं सिंगापुर में दिसंबर 2020 के आंकड़ों के मुताबिक। इनमें से 19 फीसद सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, 19 फीसद पेशेवर सेवा और 15 फीसद वित्त क्षेत्र में हैं।

उत्तरी अफगानिस्तान पर तेजी से काबिज हो रहा तालिबान

टकराव ▶ पाक सहित कई देशों ने वाणिज्य दूतावास का कामकाज समेटा, रूस ने चेताया– अमेरिका मध्य एशिया के देशों में सैन्य तैनाती की न सोचे

काबुल, एपी : अफगानिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में सेना और तालिबान के बीच लड़ाई में सेना कमजोर पड़ गई है। यहां अधिकांश जिलों पर तालिबान का कब्जा होने के दौरान पाकिस्तान सहित कई देशों ने वाणिज्य दूतावास का कामकाज समेटना शुरू कर दिया है। कुछ देशों ने दूतावास बंद करने की घोषणा कर दी है। इधर रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वह मध्य एशिया के किसी देश में सैन्य अड्डा बनाने की योजना न बनाए।

अफगानिस्तान में बीस साल पहले अमेरिका और नाटो देशों की सेना ने तालिबान, इस्लामिक स्टेट व अन्य आतंकवादी संगठनों पर उत्तरी क्षेत्र में ही सबसे पहले बढ़त बनाई थी। सेना वापसी के दौरान बगराम हवाई अड्डे के खाली करने के बाद तालिबान ने उत्तरी अफगानिस्तान में एक के बाद एक कई जिलों पर कब्जा कर लिया है। बाल्ख और बदख्शान प्रांत में कुछ जिलों को बिना लड़े ही तालिबान ने हासिल कर लिया।

रूस ने वाणिज्य दूतावास बंद कर दिया : बाल्ख में ईरान और तुर्की ने पहले ही वाणिज्य दूतावास बंद करने की घोषणा कर दी है। बाल्ख के गवर्नर मुनीर फरहाद ने मंगलवार को बताया कि पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान ने भी वाणिज्य दूतावास की अपनी सेवाएं कम कर दी हैं। रूस ने वाणिज्य दूतावास बंद कर दिया है। बदख्शान से लगी सीमा पर ताजिकिस्तान ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। अफगान सैनिक भागकर यहीं से ताजिकिस्तान पहुंच रहे हैं। ताजिकिस्तान में एक हजार से अधिक सैनिकों के पहुंचने के बाद यहां शिविर खोल दिए गए हैं।

इधर एएनआइ के अनुसार रूस के अफगानिस्तान के लिए विशेष दूत जामिर काबुलोव ने अमेरिका से कहा है कि वह अफगानिस्तान से सेना वापसी के बाद मध्य एशिया के किसी देश को सैन्य अड्डे के लिए विकल्प के तौर पर न देखे। वर्तमान में मध्य एशिया के सभी देश कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी आर्गनाइजेशन (सीएसटीओ) के सदस्य हैं। इन सभी का बाहरी खतरे को लेकर रूस के साथ सुरक्षा समझौता है।

ताजिकिस्तान की सीमा पर रूस का सुरक्षा अभ्यास : रायटर के अनुसार रूस ने ताजिकिस्तान में अपने लड़ाकू हेलिकाप्टर के साथ अफगानिस्तान की सीमा पर सुरक्षा अभ्यास किया और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों की टेस्टिंग भी की। रूस ने कहा है कि वह ताजिकिस्तान की सीमा की पूरी सुरक्षा करेगा। ताजिकिस्तान ने बीस हजार सैनिकों की अफगानिस्तान सीमा पर तैनाती कर दी है।

काबुल में अमेरिकी दूतावास की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता : एपी के अनुसार अमेरिका और नाटो देशों की सेना की वापसी के बाद अमेरिकी दूतावास की सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ी चिंता हो गई है। काबुल में अमेरिकी दूतावास ग्रीन जोन में है, जहां 1400 अमेरिकी नागरिक और चार हजार कर्मचारी एक छोटे से शहर के रूप में बने क्षेत्र में काम करते हैं। इनके आने-जाने के लिए काबुल का हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जिसकी सुरक्षा फिलहाल अमेरिका और तुर्की के सैनिक कर रहे हैं। अब तालिबान के विस्तार से दूतावास सुरक्षा की चिंता बढ़ गई हैं।

77 तालिबानी आतंकी और 16 अफगान सैनिक मारे गए : आइएएनएस के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि लघमन प्रांत में किए गए हवाई हमलों में 77 तालिबानी आतंकी मारे गए हैं। मंत्रालय ने हमले के संबंध में वीडियो फुटेज भी जारी किए हैं। एएनआइ के अनुसार पश्चिमी हेरात प्रांत में सलमा बांध पर घात लगाकर हमले में आतंकियों ने 16 अफगान सैनिकों की हत्या कर दी।



अमेरिकी और नाटो सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद राजधानी काबुल की सड़कों पर तैनात अफगान सुरक्षाकर्मी। एपी

अफगानिस्तान में बंद नहीं होंगे भारत के मिशन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती ताकत की सूचनाओं के बीच भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वह अफगानिस्तान में शांति व संपन्नता के लिए लगातार कोशिश करता रहेगा। साथ ही भारत ने इन बातों से भी इन्कार किया है कि वह काबुल, कंधार और मजार-ए-शरीफ स्थित मिशनों को बंद करने जा रहा है। हालांकि हालात को देखते हुए काबुल स्थित दूतावास या दूसरे वाणिज्य दूतावासों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या जरूर कम की जा सकती है। दूसरी तरफ भारत अफगानिस्तान सरकार और वहां के राजनीतिक दलों से भी लगातार संपर्क बनाये हुए है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की बुधवार से शुरू हो रही रूस यात्रा के दौरान भी अफगानिस्तान की स्थिति पर अहम चर्चा होने की संभावना है। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद जिस तरह से अफगानिस्तान में अस्थिरता फैली है उसे देखते हुए रूस की भावी भूमिका पर सभी की नजर है।

मंगलवार को विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला की नई दिल्ली स्थित अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मानुन्दजई व उनके सहयोगियो के साथ लंबी बैठक हुई। इसमें विदेश सचिव ने यह आश्वासन दिया कि भारत अफगानिस्तान में लंबे समय के हितों को देखते हुए काम करता रहेगा ताकि वहां शांति व समृद्धि आए। बैठक में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव जेपी सिंह भी मौजूद थे। इस बैठक की अहमियत इसलिए भी है कि हाल में यह खबरें आने लगी हैं कि भारत तालिबान के साथ संपर्क में है। वैसे भारत सरकार ने इससे साफ तौर पर इन्कार किया है लेकिन माना जा रहा है कि अफगानिस्तान के बदलते हालात को देख कर भारत अपने हितों को लेकर हरसंभव कोशिश में जुटा हुआ है। भारत व तालिबान के बीच संपर्क स्थापित होने के लेकर पाकिस्तान की मीडिया में लगातार खबरें प्रकाशित हो रही हैं।

मजबूत हो रहा तालिबान : सनद रहे कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही वहां तालिबान के मजबूत होने की भी सूचना है। ऐसे में अगले दो दिनों के दौरान रूस और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच होने वाली वार्ता पर भी सभी की नजर रहेगी। जयशंकर की मास्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात में अफगानिस्तान मुद्दा अहम रहने वाला है।

न्यूज गैलरी

पोप फ्रांसिस की सेहत में आया सुधार

रोम : पोप फ्रांसिस ने अपनी आंत के आपरेशन के दो दिन बाद मंगलवार को सुबह नाश्ता करके अखबार पढ़ा और कुछ कदम चहलकदमी भी की। वेटिकन के प्रवक्ता मैटियो ब्रूनी ने बयान जारी करके कहा कि उनकी सेहत अब अच्छी और सामान्य है। ब्रूनी ने कहा कि पोप फ्रांसिस ने रविवार को हुए आपरेशन के बाद रात में अच्छी नींद ली। उनकी तबियत स्थिर रही। उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। उनके रुटीन टेस्ट भी अच्छे रहे हैं। 84 वर्षीय फ्रांसिस फिलहाल अभी रोम के जेमिली पॉलीक्लीनिक में ही रहेंगे। (एपी)

सिंगापुर में भारतवंशी ने जीती सरकारी प्रतियोगिता

सिंगापुर : सिंगापुर की सरकार के द्वारा प्रवासी कामगारों के लिए आयोजित की गई प्रतियोगिता में मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले 33 वर्षीय गणेशन संधीरकासन ने पहला पुरस्कार जीता है। गणेशन ने इस प्रतियोगिता में भारत में चौथी शताब्दी से चली आ रही मार्शल आर्ट सिलंबम का प्रदर्शन किया। इस सरकारी प्रतियोगिता की सीरीज बनाकर फाइनल प्रसारण टीवी पर किया गया। गणेशन ने 2010 में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विश्व सिलंबम चैंपियनशिप में भाग लेकर सिल्वर मेडल जीता था। गणेशन की मार्शल आर्ट सिलंबम के प्रदर्शन का वीडियो टिकटाक पर भी डाला गया, जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया। (प्रेट्र)

ईरान का इजरायल पर परमाणु संयंत्र पर हमले का आरोप

तेहरान : ईरान ने इजरायल पर तेहरान के करीब स्थित असैन्य परमाणु केंद्र के ऊपर जून में हमला करके सब तहस-नहस करने का आरोप लगाया है। आधिकारिक समाचार एजेंसी इरना के अनुसार ईरान की कैबिनेट के प्रवक्ता अली राबेई ने मंगलवार को आरोप लगाया कि इजरायल ने यह हमला वियना में जारी वार्ता को बाधित करने के लिए किया था। वियना में परमाणु समझौते की बहाली के लिए विश्व के नेताओं से हो रही थी। लेकिन इजरायल के ऐसे कदमों की वजह से ईरान और अधिक मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि यहूदियों के शासन में ऐसी कार्रवाइयों से ईरान को रोकने के संकेत दिए गए हैं। इसीलिए वह कहते हैं ईरान से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। राबेई ने कहा कि इजरायल ने ईरान की राजधानी से 40 किमी उत्तर-पश्चिम स्थित कराज में परमाणु ऊर्जा केंद्र पर विगत 23 जून को बमबारी हुई थी। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे कोई विशेष क्षति नहीं हुआ है। केवल छत क्षतिग्रस्त हुई है। इसकी जो सैटेलाइट इमेज जारी की गई थी। वह इंडस्ट्रीयल शीट मरम्मत के लिए हटाने के बाद जारी की गई थी। (एपी)

फेसबुक, ट्विटर और गूगल ने दी हांगकांग को छोड़ने की धमकी

हांगकांग, आइएएनएस : फेसबुक, ट्विटर और गूगल ने हांगकांग सरकार को धमकी दी है कि डाटा संरक्षण के कानूनों में अगर अधिकारियों ने बदलाव करने की कोशिश की तो वह इस क्षेत्र में कामकाज बंद कर देंगे। दूसरी ओर, हांगकांग की नेता कैरी लैम ने कहा कि 'विचारधाराएं' राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रही हैं। उन्होंने अभिभावकों, अध्यापकों और धार्मिक नेताओं से आग्रह किया कि वह किशोरों के व्यवहार पर नजर रखें। साथ ही प्रशासन के कानून तोड़ने वालों के संबंध में जानकारी दें।

फेसबुक, ट्विटर व गूगल आदि ने कहा है कि हांगकांग में डाटा प्रोटेक्शन के तहत नए कानून लाकर गलत इरादे से लोगों की आनलाइन सूचनाएं न मांगी जाएं। इंटरनेट कंपनियों के समूह डब्ल्यूएसजे की ओर से भेजे गए एक पत्र में कहा गया है कि इन कंपनियों को लगता है कि इस कानून में संशोधन करके उनके कर्मचारियों को आपराधिक जांच के दायरे में लाया जाएगा। या फिर यूजर्स को अपनी किसी निजी पोस्ट के लिए आपराधिक जांच के दायरे में लाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि विगत मई में हांगकांग के डाटा प्रोटेक्शन कानून में लोगों की निजी जानकारियां इंटरनेट पर प्रसारित करने से रोकने के संबंध में कुछ नए प्रविधान जोड़ने की बात कही गई थी। इसकी सजा व 1.28 लाख डालर (10 लाख हांगकांग डालर) का जुर्माना करने का प्रविधान जोड़ने का भी प्रस्ताव है। इन प्रतिबंधों से बचने का बस यही तरीका है कि आइटी कंपनियां हांगकांग में निवेश करना और सेवाएं देना बंद कर दें।

नेट-वार

- कहा-डाटा संरक्षण के कानूनों में बदलाव की कोशिश की तो वह इस क्षेत्र में कामकाज बंद करेंगे
- निजी जानकारी इंटरनेट पर जारी करने पर होगी सजा, 1.28 लाख डालर जुर्माना लगाने पर विचार जारी



दी चेतावनी। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

बम विस्फोट की साजिश में नौ छात्र गिरफ्तार

हांगकांग की नेता कैरी लैम ने कहा कि वित्तीय केंद्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत चीनी प्रशासन का कब्जा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक साप्ताहिक कांफ्रेंस में सरकारी आदेश से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं हो सकता है। लैम के वक्तव्य के बाद पुलिस ने कहा कि नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी गतिविधियों के संदेह में गिरफ्तार किए गए इन छात्रों में कुछ तो माध्यमिक शिक्षा के हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए लोग आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं और वह बम विस्फोट की साजिश में लिप्त पाए गए। इन पर आरोप है कि इन्होंने टीएटीपी बमों से अदालतों, सुरंगों, रेलों को उड़ाने की साजिश रची है।

विशेषज्ञ के ट्विटर अकाउंट पर रोक

वेलिंगटन (न्यूजीलैंड) : न्यूजीलैंड के विशेषज्ञों का कहना है कि ट्विटर ने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग का मजाक उड़ाने वाले विशेषज्ञ के अकाउंट पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। ट्विटर ने अब उनके दो ट्वीट को हटाकर उस स्थान पर अनुपलब्धता लिख दिया है। हालांकि, ट्विटर ने यह नहीं बताया कि उसने यह कदम किस लिए उठाया है। उल्लेखनीय है कि कैंटिनबरी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर एनी-मारी ब्रैडी चीन संबंधी विषयों पर विशेषज्ञता रखती हैं। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचक ने ट्वीट करके पिछले हफ्ते चीनी दल के 100 साल पूरे होने के समारोह का मजाक उड़ाया था।

चीन ने ताइवान पर जापान के बयान का कड़ा विरोध किया

- जापानी उप प्रधानमंत्री ने कहा, 'अगर चीनी सेना ने हमला किया तो जापान और अमेरिका मिलकर ताइवान की रक्षा करेंगे'
- चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि ऐसी टिप्पणी बेहद गलत और घातक

बीजिंग, प्रेट्र : चीन ने जापान के उप प्रधानमंत्री तारो असो के हांगकांग पर दिए बयान को खतरनाक बताते हुए सख्त एतराज जताया है। तारो असो ने कहा था कि अगर चीनी सेना ने हमला किया तो जापान और अमेरिका मिलकर ताइवान की रक्षा करेंगे।

जापान टाइम्स अखबार ने मंगलवार को प्रकाशित रिपोर्ट में कहा कि असो ने ऐसा कह कर संकेत दिए हैं कि अगर चीन ताइवान पर हमला करेगा तो जापान इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए कार्रवाई करेगा। साथ ही, जापान अमेरिका के साथ मिलकर स्वशासित हांगकांग की रक्षा करने में अपना पूरा सहयोग देगा। अखबार ने जापान के उप प्रधानमंत्री असो के हवाले से कहा, 'अगर ताइवान के साथ कोई बड़ी घटना हुई तो यह कहना उचित होगा कि वह स्थिति जापान की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं होगी।' जापान के रक्षा मंत्री नोबियो किशी ने मंगलवार को कहा कि जापान एक समग्र फैसला लेगा फिर चाहे सवाल जापान के अस्तित्व का हो या फिर विशिष्ट हालात या सूचना पर आधारित हो।

असो के बयान पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि ऐसी टिप्पणी बेहद गलत और घातक है। यह हमारी 'एक चीन' की नीति के विरुद्ध है, जो ताइवान को चीन का एक हिस्सा मानता है। उन्होंने कहा कि चीन ने इस बयान को खारिज किया है और जापानी पक्ष को अपना प्रतिरोध जता दिया है। झाओ ने कहा कि जापान के कुछ नेता ताइवान को अभी भी अपना बनाना चाहते हैं। इससे जाहिर है कि उन्होंने इतिहास से कोई सबक नहीं लिया है।



चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान का फाइल फोटो। जागरण आर्काइव

रूस में विमान दुर्घटनाग्रस्त, 28 मरे

- पेट्रोपाव्लोव्सक-कामचत्स्की शहर से पलाना जा रहा था एंटोनोव एएन-26 विमान
- अचानक कंट्रोल रूप से टूट गया संपर्क, उसके बाद राडार से भी हो गया गायब



दुर्घटनाग्रस्त रूसी विमान एंटोनोव एएन-26 की फाइल फोटो। एएफपी

मास्को, एपी : रूस में सुदूर पूर्वी क्षेत्र कमचतका में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एंटोनोव एएन-26 विमान में चालक दल के छह सदस्यों सहित 28 लोग यात्रा कर रहे थे। इसमें कमचतका के मेयर भी सवार थे। इन सभी यात्रियों की मौत हो गई।

अधिकारियों के अनुसार यह विमान पेट्रोपाव्लोव्सक-कामचत्स्की शहर से पलाना जा रहा था। अचानक उसका कंट्रोल रूप से संपर्क टूट गया। उसके बाद वह राडार से भी गायब हो गया। विमान कमचतका एविएशन एंटरप्राइजेज का था।

विमान के गायब होने के बाद उसकी खोज में एक विमान और दो हेलीकाप्टर लगा दिए गए। कुछ घंटे बाद विमान का मलवा ओखोटस्क सागर तट के निकट मिला।

कमचतका के गवर्नर व्लादिमीर सोलोडोव ने बताया कि विमान का मुख्य मलवा समुद्र तट और अन्य हिस्से समुद्र में मिले। रूसी मीडिया के अनुसार विमान में सवार कोई भी यात्री दुर्घटना में नहीं बचा।

पलाना एयरपोर्ट के अधिकारियों के अनुसार यह विमान जब पलाना से दस किमी. दूर था, तब उससे संपर्क बना हुआ था। उसके अगले ही क्षण संपर्क टूट गया। अधिकारियों ने बताया कि विमान में कमचतका के मेयर ओल्गा मोखिरेवा भी सवार थे। यह विमान 1982 से सेवा में था।

अमेरिकी संसद पर हमले के छह माह पूरे, हमलावरों की तलाश अधूरी

वाशिंगटन, एपी : अमेरिका की संसद (कैपिटल हिल) पर छह जनवरी को हुए हमले के छह माह बाद भी हमलावरों की तलाश पूरी नहीं हो पाई है। हमले के तुरंत बाद पांच सौ लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद भी अभी कई हमलावरों की न्याय विभाग तलाश कर रहा है। इस दंगे के बाद अति उत्साह में आकर हमलावरों ने कई फोटो और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर साझा किए थे। उस दौरान पुलिस और खुफिया एजेंसियों को प्रारंभिक स्तर पर गिरफ्तारी करने में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन छह माह होने के बाद अभी भी कई हमलावर पकड़ से बाहर हैं। एफबीआइ की साइट पर कैपिटल हिल हिंसा में शामिल लोगों की तलाश के लिए अभी भी तीन सौ लोगों की नौ सौ से अधिक तस्वीर पड़ी हुई हैं। जिनको तलाश किया जाना है। एफबीआइ को हिंसा के बाद जनता से अनगिनत जानकारियां मिलीं। उसके बाद भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इनमें से कई हमलावर ऐसे हैं, जिन्हें तस्वीरों में सीधे तौर पर सुरक्षा अधिकारियों पर हमला करते देखा गया। उनको भी पुलिस और जांच एजेंसी गिरफ्तार नहीं कर सकी हैं।

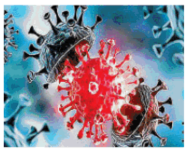
कई देशों में कोरोना संक्रमण से राहत के बाद पाबंदियों में दी गई ढील

- कनाडा-अमेरिका की बीच यात्रा में दी गई राहत
- जर्मनी ने जोखिम वाले देशों की सूची से भारत का नाम हटाया

टोरंटो, एपी : कोरोना महामारी के कारण अमेरिका और कनाडा के बीच यात्रा में लगाई गई पाबंदियों में सोमवार से राहत दे दी गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि अगले कुछ सप्ताह में ये पाबंदियां पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएंगी।

यात्रा के संबंध में जारी नए निर्देशों के अनुसार कनाडा के जो नागरिक और स्थायी निवासी वैक्सीन की दो खुराक ले चुके हैं, उन्हें अब 14 दिन के लिए क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। हवाई यात्रा करने वालों के लिए भी तीन दिनों का अनिवार्य क्वारंटाइन समाप्त कर दिया गया है। पाबंदियों में ढील अभी जरूरी काम से आने-जाने वाले लोगों के लिए की गई है।

रायटर के अनुसार जर्मनी ने डेल्टा वैरिएंट के कारण भारत सहित ब्रिटेन, रूस, नेपाल और पुर्तगाल को जोखिम वाले देशों की सूची में डाल दिया था। अब इन सभी देशों का नाम इस सूची से हटा दिया गया है। ब्रिटेन और पुर्तगाल से यात्रा में भी ढील दी गई है। आइएएनएस के अनुसार ब्रिटेन में पिछले 24 घंटों में 27 हजार से ज्यादा कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। यहां 19 जुलाई से पाबंदियों को हटाने के लिए तेजी से वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने कहा कि देश अब केवल कोरोना के ही बारे में नहीं सोच सकता। हमारे सामने अन्य चुनौतियां भी हैं, उनकी ओर भी ध्यान देना होगा।



जारी है कोरोना से जंग। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

चीन : रायटर के अनुसार यहां अब तक लोगों को एक अरब तीस करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी हैं। म्यांमार से सटे शहरों में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद उन स्थानों पर लाकडाउन कर दिया गया है।

इजरायल : एएनआइ के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पांच सौ संक्रमण के नए केस मिले हैं।

इंडोनेशिया : एएनआइ के अनुसार डेल्टा वैरिएंट के कारण यहां मरीजों की संख्या बढ़ रही है।

इटली : आइएएनएस के अनुसार स्वास्थ्यकर्मियों के लिए वैक्सीन लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

पाकिस्तान : प्रेट्र के अनुसार कोरोना संक्रमण के कारण अफगानिस्तान की सीमा को बंद कर दिया गया है।

रैनसमवेयर हमले से 1500 कंपनियों का कारोबार ठप

वाशिंगटन, रायटर : अभी तक के सबसे बड़े रैनसमवेयर (मालवेयर) हमले का संकट जारी है। अमेरिकी तकनीकी सूचना कंपनी कसेया ने कहा, साइबर हमले से समूचे विश्व में करीब 1500 कंपनियों का कारोबार ठप हो गया है। करीब दस लाख कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं।

फ्लोरिडा की इस कंपनी के सीईओ फ्रेड वकोला ने मंगलवार को कहा, शुक्रवार को हुए साइबर हमले का कितना असर हुआ इसका आकलन करना मुश्किल है। चूंकि जिन्हें इससे नुकसान हुआ है उनमें से ज्यादातर उपभोक्ता कसेया के ही थे। कसेया कंपनी आइटी की आउटसोर्सिंग दुकानों को साफ्टवेयर टूल मुहैया कराती है। इसका बैकआफिस ही कंपनी के छोटे-मोटे मसले हल करता है। साथ ही इनका अपना टेक डिपार्टमेंट है। वकोला ने यह बताने से इन्कार कर दिया कि वह क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि करीब सात करोड़ डालर की फिरौती मांगने वाले इस रैनसमवेयर के हैकर रूसी समूह रेविल के माने जाते हैं। अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी (एफबीआइ) की ओर से जारी जांच के बावजूद रूसी सरकार ने इस बात से साफ इन्कार किया है। अपराधियों ने एक ऐसे उपकरण का उपयोग किया है जो मालवेयर के जरिये कंप्यूटर की फाइलों को हैक करके मोटी रकम ऐंठता है।



अनोखा प्रदर्शन... बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स स्थित यूरोपियन परिषद भवन के सामने पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने यूरोपीय संघ के नेताओं के मुखौटे लगाकर अनोखा प्रदर्शन किया। इसके माध्यम से बढ़ रहे प्रदूषण की ओर इन नेताओं का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। एपी

सिंगापुर में 15 वर्षों के दौरान दोगुने हुए भारतीय पेशेवर

सिंगापुर, प्रेट्र : सिंगापुर में भारतीय पेशेवरों की संख्या तेजी से बढ़ी है। यहां की संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2005 से 2020 के बीच में भारतीयों की संख्या 13 फीसद से 26 फीसद यानी दो गुना हो गई है। कोरोना महामारी के दौरान ज्यादा संख्या में जा रही नौकरियों पर स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां भारतीयों को सहूलियतें दी जा रही हैं, इसलिए इनकी संख्या बढ़ रही है।

इस पर यहां की संसद में जनशक्ति मंत्री टैन सी लेंग ने आंकड़ों के साथ पूरा स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीयों की संख्या तकनीकी योग्यता के कारण बढ़ी है। उनको सरकारी स्तर से किसी प्रकार की सहूलियत नहीं दी जा रही है। वैश्विक स्तर पर विकास के लिए जरूरी तकनीकी प्रतिभा की मांग के कारण ऐसा हो रहा है। मंत्री ने कहा कि यह गलत धारणा है कि भारतीय इन नौकरियों में नहीं आएंगे तो स्थानीय लोगों को ये नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि सिंगापुर में अच्छी योग्यता वाले लोग हैं, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जरूरत के लिए यह पर्याप्त नहीं है। इन कंपनियों को जिस योग्यता और प्रतिभा की जरूरत है, उस पर भारतीय पेशेवर खरे उतर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि तकनीकी प्रतिभा की देश में आवश्यकता बढ़ रही है। इसके साथ ही जिस स्तर की योग्यता चाहिए, उसको स्थानीय स्तर से पूरा नहीं किया जा सकता।

इंग्लैंड और डेनमार्क के बीच होगा यूरो कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, फार्म में वापसी कर चुके हैं इंग्लिश कप्तान हैरी केन

डेनमार्क को हल्के में नहीं लेना चाहेगी केन की टीम

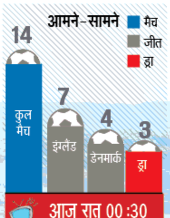

हैरी केन • फाइल फोटो, एपी

लंदन, एपी : इंग्लैंड की टीम यूरो कप में सेमीफाइनल तक पहुंच गई, लेकिन ग्रुप स्तर में उसने ऐसा प्रदर्शन नहीं किया था जिससे उसकी तारीफ की जाए, खासकर उनके कप्तान हैरी केन की जो ग्रुप मैचों में गोल नहीं कर पाए थे। लेकिन नाकआउट में केन ने अपनी फार्म वापस पाई और टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। वहीं, डेनमार्क की ग्रुप स्तर में हार से शुरुआत हुई लेकिन उसने ऐसा रास्ता तय कर लिया है कि वे यहां से घर नहीं लौटना चाहेंगे। दोनों टीमों के बीच बुधवार देर रात को यूरो का दूसरा सेमीफाइनल होगा। भले ही घर में खेलने से इंग्लैंड जीत का दावेदार है, लेकिन डेनमार्क की टीम को हल्के में लेना इंग्लिश टीम की भूल साबित होगी।

4 इंग्लैंड : फीफा रैंकिंग | **1966** सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन: सेमीफाइनल
8 गोल किए **0** गोल खाए
11 पिछले मैचों से इंग्लैंड की टीम एक भी मुकाबला नहीं हारी है। उसे पिछली हार बेल्जियम के खिलाफ नेशंस लीग में मिली थी



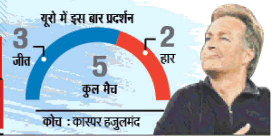
कोच : गैरेथ साउथगेट



आज रात 00:30
सोनी नेटवर्क

5 बार इंग्लैंड व डेनमार्क यूरो में भिड़े हैं, जिसमें इंग्लैंड ने दो मैच जीते, डेनमार्क को एक में जीत मिली है और दो मुकाबले ड्रा पर खत्म हुए हैं

10 डेनमार्क : फीफा रैंकिंग | **1992** सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन: विजेता
11 गोल किए **5** गोल खाए



कोच : कास्पर हजुलमंद

मैच का एक्स फैक्टर

इस सदी में डेनमार्क की टीम ने इंग्लैंड में तीन मैच खेले हैं और दो में उसे जीत मिली है। हाल की जीत में 2020 में वेंबले में 1-0 से जीत दर्ज की थी। वे लंदन में बड़े आत्मविश्वास के साथ आएंगे और वे जानते हैं कि इंग्लैंड को उनके घर में कैसे हराना है। डेनमार्क के प्रशंसक भी स्टेडियम में अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए कम नहीं होंगे लेकिन, उनके समर्थन ने यूरो में नया रंग ला दिया है और वेंबले में भी वे अपनी टीम को समर्थन करने के लिए तैयार होंगे।


डेनमार्क के स्ट्राइकर कास्पर डोल्बर्ग • फाइल फोटो, एपी

यहां तक कैसे पहुंचे

डेनमार्क : डेनमार्क का यहां तक का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। फिनलैंड के खिलाफ अपने पहले मुकाबले के दौरान डेनमार्क के क्रिस्टियन एरिक्सन मैदान पर बेहोश हो गए थे लेकिन, इसके बाद डेनमर्का ग्रुप स्तर के शुरुआती दो मुकाबले हार गया था लेकिन, इसके बाद टीम में ऐसा जोश आया कि उन्होंने नाकआउट में पहुंचने के लिए पहले रूस को हराया और फिर वेल्स और चेक गणराज्य को शिकस्त देकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया था।

इंग्लैंड : साउथगेट की टीम ने अभी तक टूर्नामेंट में एक भी गोल नहीं खाया है। टीम ने ग्रुप स्तर में पहले क्रोएशिया को हराया, फिर स्काटलैंड से ड्रा खेला और फिर चेक गणराज्य को मात देकर नाकआउट का टिकट कटाया था। प्री-क्वार्टर में जर्मनी को हराया फिर क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन को मात दी।

जीत का मंत्र

इंग्लैंड : इंग्लैंड की टीम इस टूर्नामेंट में सबसे खतरनाक टीमों में से एक मानी जाती है। साउथगेट की टीम की सभी विभागों में अच्छी है। वेंबले स्टेडियम में यानी घर में खेलने से उसे फायदा मिलेगा। 1966 विश्व के बाद से इंग्लैंड की टीम किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में नहीं पहुंच पाई है इसलिए उम्मीद और दबाव साउथगेट की टीम पर होगा। लेकिन यदि वे मैदान के बाहर चल रही चीजों पर ध्यान नहीं दे तो वे डेनमार्क के खिलाफ ज्यादा मजबूत टीम होगी।

डेनमार्क : डेनमार्क की एक समूह के रूप में प्रदर्शन करके जीत की ललक सामने तब से आई जब उसके कप्तान साइमन काजर ने एरिक्सन के मैदान पर गिर जाने के बाद समूह के रूप में एक घेरा बनाने का आग्रह किया था। इसके बाद टीम ने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। डेनमार्क के गोलकीपर कास्पर श्माइकल हमलों को नाकाम कर दें और स्ट्राइकर चल पड़े तो वह जीत सकता है। यूएफा ने एरिक्सन को मैच में आने का निमंत्रण दिया है अगर वह आते है तो इससे टीम का मनोबल और बढ़ेगा।

इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर

हैरी केन (फारवर्ड) : इंग्लिश कप्तान हैरी केन का ग्रुप स्तर में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था और वह गोल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। साउथगेट जानते थे कि फाइनल में पहुंचने के लिए केन का चलना जरूरी है और ऐसे में कप्तान ने नाकआउट में अपनी खोई लय हासिल कर ली। उन्होंने बेल्जियम के खिलाफ प्री-क्वार्टर फाइनल में एक गोल किया तो फिर अगले मैच में यूक्रेन के खिलाफ दो गोल दागे थे। अब इंग्लैंड को फाइनल का टिकट चाहिए तो कप्तान को फिर से गोल दागने होंगे।

रहीम स्टर्लिंग (फारवर्ड) : केन के फार्म में नहीं होने से रहीम स्टर्लिंग पर गोल करने का दबाव था और ऐसे में स्टर्लिंग ने ग्रुप स्तर से टीम को जीत दिलाना शुरू किया। उन्होंने क्रोएशिया के खिलाफ 1-0 की जीत में एकमात्र गोल किया। फिर ग्रुप के आखिरी मैच में चेक गणराज्य को भी इसी स्कोर से हराने में एक गोल दागा। फिर जर्मनी के खिलाफ भी गोल किया और अब डेनमार्क के खिलाफ भी उनसे ऐसे ही प्रदर्शन की आस रहेगी।

ल्यूक शा (डिफेंडर): इस इंग्लिश डिफेंडर का प्रदर्शन केन और स्टर्लिंग से कम नहीं है। उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ मैगुएर और केन के गोल करने में मदद की जिससे टीम का जीत का अंतर बढ़ गया।

जोकिम महले (डिफेंडर) : 24 वर्षीय जोकिम डेनमार्क की तरफ से इस बार यूरो में दो गोल कर चुके हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में पांचों मैच खेले हैं और 90 मिनट तक मैदान पर रहे हैं।

यूसुफ पाउलसन (फारवर्ड) : 27 वर्षीय इस फारवर्ड की भी सेमीफाइनल में भूमिका अहम रहेगी। वह इस बार यूरो में चार मैच खेल चुके हैं जिसमें उन्होंने दो गोल किए हैं। रूस के खिलाफ ग्रुप मैच में वह 59 मिनट तक खेले व एक गोल किया। टीम ने यह मैच 4-1 से जीता। इससे पहले बेल्जियम के खिलाफ मिली हार में टीम की तरफ से एकमात्र गोल उनकी तरफ से ही था।

कास्पर डोल्बर्ग (फारवर्ड) : डेनमार्क को यहां तक पहुंचाने में डोल्बर्ग की अहम भूमिका रही है। वह वेल्स के खिलाफ प्री-क्वार्टर फाइनल में 68 मिनट तक मैदान पर खेले और उसमें उन्होंने दो गोल दागकर टीम को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया था। फिर क्वार्टर फाइनल में उन्हें 58 मिनट तक खेलने का मौका मिला तो उन्होंने एक गोल कर दिया।

पेरू को हराकर फाइनल में पहुंचा ब्राजील

रियो डि जेनेरियो, एपी : खिताब की प्रबल दावेदार ब्राजील ने अपने रसूख के मुताबिक प्रदर्शन करते हुए पेरू को 1-0 से हराकर कोपा अमेरिका फुटबाल के फाइनल में प्रवेश कर लिया। खिताब मुकाबले में टीम का सामना अर्जेंटीना और कोलंबिया के बीच होने दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम से होगा। अगर अर्जेंटीना की टीम यह मैच जीत लेती है तो प्रशंसकों को मेसी बनाम नेमार का रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है।



जीत के बाद ब्राजील के स्टार स्ट्राइकर नेमार ने कहा, 'मैं चाहता हूं कि फाइनल अर्जेंटीना से हो। मेरे उस टीम में कई दोस्त हैं और मैं उनसे फाइनल खेलना चाहता हूं। जीत तो ब्राजील की ही होगी।'

निल्टन सांतोस स्टेडियम पर खेले गए इस मैच में नेमार ने एकमात्र गोल में सूत्रधार की भूमिका निभाई। उन्होंने डिफेंडर अलेक्जेंडर कालेंस से गेंद लेकर लुकास पाकेटा को सौंपी जिन्होंने 35वें मिनट में उसे नेट के अंदर डाल दिया। टीम की हार के बावजूद पेरू के गोलकीपर पेड्रो गालेसे ने शानदार प्रदर्शन करके कई गोल बचाए। पहले हाफ में नेमार और रिचार्लीसन के गोल उन्होंने नहीं बचाए होते तो हार का अंतर अधिक होता। ग्रुप चरण में ब्राजील ने पेरू को 4-0 से हराया था लेकिन, इस मैच में कहानी दूसरी थी। दूसरे हाफ में जियांलुका लापाडुला के शाट पर ब्राजील के गोलकीपर एडरसन ने शानदार बचाव किया। ब्राजील के कोच टिटे ने बाद में स्वीकार किया कि यह काफी थकाऊ मैच था। शारीरिक और मानसिक रूप से। कोपा अमेरिका मानसिक मैराथन से कम नहीं है।

ब्राजील पिछले 14 सत्रों में से नौ बार फाइनल में पहुंच चुका है। इस बार उसे तुरंत मौके पर मेजबान बनाया गया क्योंकि मूल मेजबान अर्जेंटीना और कोलंबिया पीछे हट गए थे। दो साल पहले नेमार चोटिल होने के कारण नहीं खेले थे लेकिन, ब्राजील ने पेरू को 3-1 से हराकर खिताब जीता था। फाइनल में मेजबान की हौसलाअफजाई के लिए उसके उत्साही प्रशंसक नहीं होंगे जिनके स्टेडियम में प्रवेश पर कोरोना ने रोक लगा दी है। पेरू तीसरे स्थान के प्लेआफ में दूसरे सेमीफाइनल में हारने वाली टीम से खेलेगा।


गोल करने के बाद लुकास पाकेटा के साथ नेमार • एएफपी

विंबलडन से बाहर हुए डेनिल मेदवेदेव

लंदन, प्रेट्र : पोलैंड के 14वीं वरीयता प्राप्त हुबर्ट हरकाज ने मंगलवार को यहां दूसरी वरीयता प्राप्त डेनिल मेदवेदेव को पांच सेट तक चले मुकाबले में पराजित करके पहली बार विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

यह मैच सोमवार को बारिश के कारण चौथे सेट में रोकना पड़ा था। हरकाज ने हालांकि चौथा और पांचवां सेट अपने नाम करके इस मैच में 2-6, 7-6 (2), 3-6, 6-3, 6-3 से जीत दर्ज की। हरकाज ने पहली बार किसी ग्रैंडस्लैम प्रतियोगिता के अंतिम-आठ में जगह बनाई। वह इस साल पहली बार विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने वाले पांचवें पुरुष खिलाड़ी हैं। हरकाज का अगला मुकाबला बुधवार को अपने आदर्श रोजर फेडरर से होगा। अपने 21वें सिंगल्स ग्रैंडस्लैम खिताब पर नजर लगाए फेडरर ने बारिश से बाधित मैच में लोरेंजो सोनेगो को सीधे सेटों में 7-5, 6-4, 6-2 से हराया था।


मैच के दौरान डेनिल मेदवेदेव • रायटर

पुरुष वर्ग में हरकाज के अलावा जिन खिलाड़ियों ने पहली बार विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, उनमें कनाडा के डेनिस शापोवालोव, इटली के मैटियो बेरेटिनी, हंगरी के मार्टन फुकसोविक और रूस के कारेन खाचनोव भी शामिल हैं। आराम दिन के कारण मंगलवार को पुरुष सिंगल्स में अन्य क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं खेले गए।

इस बीच, महिला वर्ग में चेक गणराज्य की आठवीं वरीयता प्राप्त कैरोलिना प्लिसकोवा ने स्विट्जरलैंड की विक्टोरिया गोलुबिक को 6-2, 6-2 से पराजित करके पहली बार विंबलडन सेमीफाइनल में जगह बनाई। यह तीसरा अवसर है जबकि प्लिसकोवा ने किसी ग्रैंडस्लैम प्रतियोगिता के अंतिम-चार में प्रवेश किया। इससे पहले वह 2017 में फ्रेंच ओपन और 2019 में आस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची थीं।

38 साल की मिताली फिर बनीं नंबर एक बल्लेबाज

दुबई, प्रेट्र : भारतीय कप्तान मिताली राज ने इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में शानदार प्रदर्शन की बदौलत तीन साल से अधिक समय बाद आइसीसी की महिला वनडे रैंकिंग में एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत को सीरीज में 1-2 से हार मिली, लेकिन 38 साल की मिताली ने तीनों मुकाबलों में अर्धशतक जड़े।


मिताली राज • फाइल फोटो, ट्विटर

मिताली चार स्थान के फायदे से शीर्ष पर पहुंच गई हैं। वह पिछली बार फरवरी 2018 में रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची थीं। मिताली पहली बार अप्रैल 2005 में रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची थीं। पहली बार और आखिरी बार रैंकिंग में शीर्ष पर होने के बीच 16 साल का अंतर किसी भी महिला बल्लेबाज के लिए सबसे अधिक है। इंग्लैंड की जेनेट ब्रिटिन 1984 में पहली बार और 1995 में आखिरी बार नंबर एक बनी थीं, जबकि न्यूजीलैंड की डेबी हाकले एक अन्य महिला बल्लेबाज हैं जिनके नंबर एक पर काबिज होने में 10 साल से अधिक का अंतर है। हाकले पहली बार 1987 और आखिरी बार 1997 में रैंकिंग में शीर्ष पर थीं। शेफाली वर्मा 71वें पायदान पर पहुंच गई हैं।

टेस्ट में ओपनिंग से कतरा रहे केएल राहुल

रोहित, मयंक, राहुल और ईश्वरन के बावजूद टीम प्रबंधन ने दो और ओपनरों की मांग की

अभिषेक त्रिपाठी • नई दिल्ली

शुभमन गिल के चोटिल होने के बाद भारतीय टीम प्रबंधन इंग्लैंड में दो और सलामी बल्लेबाजों पृथ्वी शा और देवदत्त पडीक्कल को जोड़ना चाहता है। इसके लिए टीम इंडिया के प्रशासनिक मैनेजर ने 28 जून को मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा को ईमेल भी लिखा था। हालांकि चेतन ने उस पर संज्ञान नहीं लिया लेकिन सवाल यह उठता है कि रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, केएल राहुल और अभिमन्यु ईश्वरन के होने के बावजूद टीम प्रबंधन को अचानक से दो और ओपनरों की जरूरत क्यों पड़ गई।

एक सूत्र ने कहा कि टीम प्रबंधन इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के शुरुआती मैचों में रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल की जोड़ी को ओपनिंग में उतारेगा लेकिन अगर इनमें से कोई सफल नहीं होता है या चोटिल होता है तो फिर टीम के पास राहुल और ईश्वरन के तौर पर दो विकल्प बचते हैं। गिल के चोटिल होने के बाद टीम प्रबंधन ने राहुल से इस बारे में पूछा भी था लेकिन वह लाल गेंद के सामने ओपनिंग नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा हनुमा विहारी भी ओपनिंग नहीं करना चाहते हैं। इतनी लंबी सीरीज किसी का भी करियर बना सकती है और बिगाड़ सकती है। विराट भी अपने चहेते राहुल को ओपनिंग में उतारकर रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि अगर उनका प्रदर्शन खराब रहता है तो उनके करियर पर इसका असर होगा। वहीं बंगाल के लिए खेलने वाले ईश्वरन को लेकर टीम प्रबंधन बहुत आशान्वित नहीं है। उन्हें लगता है कि ईश्वरन इंग्लिश परिस्थितियों में ज्यादा सफल नहीं साबित होंगे। इसके अलावा टीम प्रबंधन को किसी ने यह भी चुगली की है कि चेतन शर्मा (जब वह मुख्य चयनकर्ता नहीं थे) पहले ईश्वरन के पिता की उत्तराखंड स्थित अभिमन्यु अकादमी में प्रशिक्षण देने जाते थे। हालांकि इसमें कोई गलत बात नहीं है। दैनिक जागरण को यह भी पता चला है कि विराट ने क्रिकेट से जुड़े एक-दो लोगों को फोन करके यह पता करने की भी कोशिश की कि इसमें कितनी सत्यता है?


लोकेश राहुल • फाइल फोटो, ट्विटर

मालूम हो कि बीसीसीआइ के एक सूत्र ने कहा, 'शुभमन गिल चोटिल होने के कारण इंग्लैंड के पूरे दौरे से बाहर हो गए हैं। उन्हें फिट होने में कम से कम तीन महीने का समय लगेगा। पिछले महीने टीम के प्रशासनिक प्रबंधक ने पूर्व तेज गेंदबाज चेतन शर्मा को पत्र भेजकर दो अन्य सलामी बल्लेबाजों को ब्रिटेन भेजने के लिए कहा था।' गिल की चोट की स्थिति जानने के बावजूद माना जा रहा है कि शर्मा ने टीम प्रबंधन के अनुरोध पर खास ध्यान नहीं दिया। अब देखना यह है कि क्या टीम प्रबंधन शा और पडीक्कल को भेजने के लिए बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह से औपचारिक अनुरोध करता है। ये दोनों बल्लेबाज अभी सीमित ओवरों की सीरीज के लिए श्रीलंका में हैं।

कोरोना संक्रमण के कारण इंग्लैंड को चुननी पड़ी नई टीम

लंदन, एपी : इंग्लैंड की सीमित ओवरों के प्रारूप की मुख्य टीम में कोरोना वायरस संक्रमण के सात मामले आने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए उसे मंगलवार को पूरी तरह से नई टीम का चयन करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

श्रीलंका के खिलाफ ब्रिस्टल में खेले गए वनडे मैच के बाद सोमवार को खिलाड़ियों के नमूने लिए गए थे, जिसकी जांच में तीन खिलाड़ी और चार सहयोगी सदस्य कोरोना पाजिटिव पाए गए। संक्रमण की चपेट में आने वाले किसी का नाम हालांकि नहीं बताया गया है। टीम के बाकी सदस्य भी पाजिटिव पाए गए सदस्यों के संपर्क में थे।

इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने मंगलवार को बताया गया कि टीम रविवार से क्वारंटाइन में है। इंग्लैंड की इस नई टीम में नौ खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बने हैं। बेन स्टोक्स इस टीम के कप्तान होंगे, जबकि नियमित कोच क्रिस सिल्वरवुड की टीम में वापसी हो रही है। वह श्रीलंका के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के दौरान छुट्टी पर थे।

इंग्लैंड को पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के साथ इतने ही मैचों की टी-20 सीरीज खेलनी है। पाकिस्तान दौरे की शुरुआत गुरुवार को कार्डिफ में खेले जाने वाले पहले वनडे मैच से होगी। कार्डिफ में टीम में शामिल होने से पहले खिलाड़ियों के 18-सदस्यीय दल और कर्मचारियों को कोविड-19 के जांच की निगेटिव रिपोर्ट पेश करनी होगी।

इंग्लैंड की नई टीम : बेन स्टोक्स (कप्तान), जेक बाल, डैनी ब्रिग्स, ब्रायडन कार्से, जैक क्राले, बेन डकेट, लुइस ग्रेगरी, टाम हेल्म, विल जैक, डैन लारेंस, साकिब महमूद, डेविड मलान, क्रेग ओवरटन, मैट पार्किंसन, डेविड पायने, फिल साल्ट , जान सिंपसन, जेम्स विंस।

इंग्लैंड से लौटते ही बायो-बबल में जाएंगे श्रीलंकाई क्रिकेटर : इंग्लैंड की टीम में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने की वजह से भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज से पहले इंग्लैंड से लौटते ही श्रीलंकाई क्रिकेटर बायो-बबल में जाएंगे। भारत और श्रीलंका को 13 जुलाई से वनडे और टी-20 सीरीज खेलनी हैं ।

श्रीलंका क्रिकेट के एक अधिकारी ने बताया, 'श्रीलंकाई टीम कोलंबो पहुंचते ही आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद दूसरे बबल में जाएगी। रविवार को दौरा खत्म होने के बाद इंग्लैंड में ही टीम का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया। भारत के खिलाफ सीरीज शुरू होने में समय नहीं रह गया है तो कोई भी खिलाड़ी घर नहीं जाएगा। बबल से बबल में ही जाएंगे। अगर कोई पाजिटिव पाया गया तो टेस्ट और क्वारंटाइन और जांच के नियमों का पालन किया जाएगा।'

भारतीय टीम के कार्यक्रम में नहीं होगा बदलाव

लंदन: इंग्लैंड की टीम में कोरोना के आने के बावजदू भारतीय टीम अपने कार्यक्रम में बदलाव नहीं करेगी और उसका 20 दिन का विश्राम काल जारी रहेगा। भारतीय खिलाड़ी 14 जुलाई को लंदन में एकत्रित होंगे, जहां से वे दो सप्ताह के अभ्यास शिविर और सिलेक्ट काउंटी एकादश के खिलाफ प्रथम श्रेणी मैच के लिए डरहम जाएंगे।'

टीकाकरण आज और शुक्रवार को : भारत के सभी खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के सदस्यों को बुधवार और शुक्रवार को दूसरा टीका लगाया जाएगा। भारतीय खिलाड़ियों को कोविशील्ड का पहला टीका पहले ही लग चुका है। अभी अधिकतर खिलाड़ी लंदन या उसके आसपास के इलाकों में हैं और अपने परिवारों के साथ समय बिता रहे हैं। कुछ ग्रामीण इलाकों में भी गए हैं।

तेंदुलकर ने भारतीय ओलंपिक दल की हौसलाअफजाई की

नई दिल्ली, प्रेट्र : दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने आगामी ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों की हौसलाअफजाई की।

तेंदुलकर ने ट्वीट किया, 'जब हम तिरंगे का प्रतिनिधित्व होते हुए देखते हैं तो रोमांच से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस ओलंपिक में भी इससे अलग नहीं होना चाहिए और हम सभी भारत से हौसलाअफजाई करेंगे क्योंकि आप हमें गौरवान्वित करेंगे। महामारी के दौरान हम सभी ने चुनौतियों का सामना किया, जिसमें हमारे खिलाड़ी भी शामिल हैं। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और मुझे पता है कि वे टोक्यो में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। हार-जीत में मिली सेकेंड का अंतर होता है। इसके लिए उन्होंने वर्षों कड़ी मेहनत की है। उन्हें हमारी शुभकामनाओं व समर्थन की जरूरत है। चलो भारत की हौसलाअफजाई करें।'

उलटफेर कर पदक जीतने में माहिर हैं अंशु मलिक

पदक के दावेदार
TOKYO 2020
16 दिन शेष

अनिल भारद्वाज • गुरुग्राम

टोक्यो ओलंपिक में पदक के दावेदारों में पहलवान अंशु मलिक का भी नाम प्रमुख है। 57 किग्रा भारवर्ग की इस पहलवान के सीनियर वर्ग में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक पदक भले ही नहीं हैं, फिर भी अखाड़े में उलटफेर करने में इन्हें महारत हासिल है। 19 साल की इस पहलवान का कहना है कि पूर्व में जीते पदकों की संख्या आपका हौसला जरूर बढ़ाती है, लेकिन अखाड़े में प्रदर्शन ही काम आता है। पिछले कुछ माह के दौरान हुए कुश्ती के मुकाबलों की बात की जाए तो अंशु विदेशी पहलवानों को चित कर पदक जीतने में सफल रही हैं। किसी भी पहलवान का प्रतियोगिता के ठीक पहले बेहतर प्रदर्शन होना उसे पदक के करीब पहुंच देता है और हाल की प्रतियोगिताओं में अंशु ने जोरदार प्रदर्शन कर दिग्गजों को हैरान किया है। अब वह मिशन टोक्यो के लिए दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत कर रही हैं।

दादी का मिला साथ : ओलंपिक तक का सफर तय करने के लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष के दौर से गुजरना होता है। अंशु बताती हैं कि मेरे गांव और परिवार में कुश्ती का बड़ा ही बेहतर माहौल रहा है। मेरे दादा मास्टर बीर सिंह कबड्डी के खिलाड़ी रहे हैं तो ताऊ पवन देश के नामी पहलवान रहे हैं। पिता धर्मवीर भी पहलवान रहे हैं। उनकी छाप बचपन में ही मेरे मन पर पड़ गई थी। मैं भी अखाड़े में खुद को आजमाना चाहती थी, मगर इसके लिए वह ना ताऊ और ना ही पिता से बात कर सकी। अखाड़े में उतरने की इच्छा दादी बेदवती के सामने प्रकट की। दादी ने भी साथ दिया और परिवार को अपना फैसला सुनाया तो सभी ने कहा कि वह भी यही चाहते हैं। अंशु कहती हैं कि जब मैं 11-12 वर्ष की थी तब अखाड़े में उतरी थी तो मेरा सपना था कि देश की नामी पहलवान बनूं। अखाड़े में प्रशिक्षण शुरू किया था और आज वहीं पर प्रशिक्षण ले रही हूं।

तेजी से करती हैं प्लान : अंशु के प्रशिक्षक जगदीश श्योराण कहते हैं कि अंशु में शुरू से ही अच्छी लगन है। उनमें अच्छे पहलवान के सभी गुण हैं। किसी भी दांव पेंच को सीखने में उन्हें अधिक समय नहीं लगता। अंशु ताकत के साथ यह तेजी से प्लान करती हैं कि सामने वाले पहलवान को कौन सा दाव लगाना है। उनकी दांव लगाने या नहीं लगाने की प्लानिंग गजब की है व अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुकाबले में पहलवान के पास यही समझदारी होनी चाहिए।

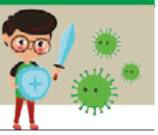

अंशु • फाइल फोटो, ट्विटर

उपलब्धियां

वर्ल्ड कैडेट	एशियन चैंपियनशिप
2016 में कांस्य पदक	2020 में कांस्य पदक
2017 में कांस्य पदक	2021 में स्वर्ण पदक
2018 में स्वर्ण पदक	2021 में स्वर्ण पदक

इनसे मिलेगी चुनौती

अंशु का कहना है कि टोक्यो ओलंपिक में हर पहलवान के साथ कड़ा मुकाबला होगा। सभी के पास अंतरराष्ट्रीय अनुभव है और वह उनके काम आएगा। मेरे सामने चुनौती जापान की पहलवान होंगी, जो रियो ओलंपिक की चैंपियन हैं। इसके अलावा चीन, नाइजीरिया, बेलारूस, पोलैंड, यूएसए, मंगोलिया, यूक्रेन और रूस की पहलवानों से भी कड़ा मुकाबला रहेगा। इन पहलवानों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं, जिनमें यूरोपीय खेलों और विश्व चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता पहलवान भी शामिल हैं।



हड्डियों व इम्युनिटी के लिए जरूरी है विटामिन डी

नेक सलाह



डा. आर. के. सिंह,
ज्वाइंट एंड रिप्लेसमेंट सर्जन, कानपुर

धूप से मुफ्त में मिलने वाला विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ ही इम्युनिटी के लिए भी है जरूरी...

हमारे शरीर को हर तरह के संक्रमण से बचाती है मजबूत इम्युनिटी। इम्युनिटी तब बनती है, जब हमारा खानपान पोषण युक्त होता है। अच्छी सेहत के लिए शरीर को प्रचुर मात्रा में विटामिंस, मिनरल्स जैसे तत्वों की आवश्यकता होती है। हर तत्व का शरीर में अलग-अलग कार्य होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन डी बहुत आवश्यक है। यह ऐसा विटामिन है, जो हमें धूप से मिलता है और कुदरत द्वारा मुफ्त उपहार के तौर पर मिला है। सुबह के समय नियमित रूप से कुछ देर धूप सेंकने से शरीर के लिए आवश्यक विटामिन डी मिल जाता है। इसके अतिरिक्त संतरा, डेयरी उत्पाद और गाजर आदि को नियमित आहार में शामिल किया जाए तो शरीर को आवश्यक विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है।

कई तरह से करता है काम: कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए जरूरी उपायों के साथ ही हमें अपनी इम्युनिटी भी मजबूत रखनी है। स्वस्थ सेहत और मजबूत इम्युनिटी के लिए शरीर को पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिनमें विटामिन-डी बहुत आवश्यक है। विटामिन डी न सिर्फ मजबूत इम्युनिटी का निर्माण करता है, बल्कि शरीर में कैल्शियम व फास्फोरस को संश्लेषित कर हड्डियों को मजबूती भी प्रदान करता है। इसकी कमी से हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि कई बार हल्की चोट लगने या गिरने से इनके टूटने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। हड्डी व जोड़ों से संबंधित बीमारियों की वजह भी शरीर में इस विटामिन की कमी है।

हो सकती हैं कई परेशानियां: विटामिन डी एंटीमाइक्रोबल प्रोटीन बनाने में सहायक है, जिससे इम्युनिटी बरकरार रहती है और शरीर को कोविड-19 जैसी बीमारियों से लड़ने का सुरक्षा कवच मिलता है। इसके अतिरिक्त शरीर में विटामिन डी की कमी कैंसर, हाईपरटेंशन और मधुमेह जैसी बीमारियों का कारण भी बनती है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं में यदि इस विटामिन की कमी होती है तो इसका असर उनके बच्चों पर पड़ता है और इस तरह के बच्चे कुपोषण के साथ ही लिवर आदि बीमारियों से प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे बच्चों की इम्युनिटी बहुत कमजोर होती है। सप्लीमेंट के तौर पर विटामिन डी का सेवन चिकित्सक की सलाह के बिना करना नुकसानदायक हो सकता है।

इसे जरूर अपनाएं

- मशरूम विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। इससे मिलने वाला विटामिन हड्डियों के साथ ही आंखों व त्वचा को भी फायदा पहुंचाता है।
- दलिया, ओटमील, दूध, मक्खन, पनीर आदि विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं। इन्हें डाइट का हिस्सा बनाएं।
- सूर्योदय के समय नियमित रूप से कुछ देर धूप में बैठें। इससे प्राकृतिक रूप से विटामिन मिलेगा।
- संतरा और बादाम का सेवन करें।
- सोयाबीन से बने उत्पादों को अपने भोजन में शामिल करें।



स्वाद बढ़ाएं ग्रीन टी का

काम की बात

ग्रीन टी इम्युनिटी बूस्टर है, लेकिन यदि इसमें शहद, नींबू और अदरक को मिला दिया जाए तो यह और भी फायदेमंद हो जाएगी...



कोरोना संक्रमण से यह सुनिश्चित हो गया है कि अगर हमारी इम्युनिटी अच्छी है तो हम हर संक्रमण से सुरक्षित रह सकते हैं। ग्रीन टी का सेवन शरीर को डिटाक्स करने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर इसमें कुछ अतिरिक्त चीजें मिला दी जाएं तो ये इम्युनिटी के लिहाज से और भी अच्छी हो जाती है।

शहद: शहद में प्रचुर मात्रा में विटामिंस व मिनिरल्स पाए जाते हैं। यदि ग्रीन टी में इसे मिला दिया जाए तो इसमें शुगर मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती और इसका स्वाद भी डिफरेंट हो जाता है। शहद वाली ग्रीन टी पीने से त्वचा के विकार भी दूर होते हैं।

नींबू: ग्रीन टी में नींबू मिलाने से इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है और कड़वाहट चली जाती है। नींबू साइट्रिक एसिड के साथ ही एंटीआक्सीडेंट से भरपूर होता है। जिससे शरीर को अतिरिक्त पोषक तत्व मिलते हैं। नींबू वाली ग्रीन टी पीने से तनाव कम होता है।

अदरक: अदरक कैंसररोधी होने के साथ ही अस्थमा और डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे ग्रीन टी में मिलाने से स्वाद और सेहत के लिए जरूरी कई पोषक तत्व मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अदरक वाली चाय सूजन की समस्या को दूर करती है।

बच्चों के लिए जीवन रक्षक है रूटीन टीकाकरण

कोरोना को हराना है

इन दिनों



डा. एस. के. काबरा
प्रोफेसर, पीडियाट्रिक विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली

टीका बच्चों के जीवन का ऐसा सुरक्षा चक्र है, जिसे लगाने से वे टीबी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, खसरा सहित कई घातक बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं। कोरोनाकाल में टीकाकरण कुछ प्रभावित जरूर हुआ है, लेकिन अगर देर हो गई है तो भी बच्चे का टीकाकरण अवश्य करवाएं...



दो बूंद जिंदगी की, चार शब्दों के इस नारे ने भारतीय जनमानस को इस तरह झकझोरा कि पोलियो जैसी घातक बीमारी देश में जड़ से खत्म हो गई। टीका चिकित्सा विज्ञान का ऐसा चमत्कार है, जिससे संक्रामक बीमारियों को न सिर्फ काबू में किया जा सकता है, बल्कि उसे मिटाया भी जा सकता है। इन दिनों कोरोना को भी टीके के प्रभावी हथियार से काबू करने में पूरी दुनिया लगी हुई है। कोरोना के इस दौर में बच्चों का रूटीन टीकाकरण अभियान कुछ प्रभावित जरूर हुआ है, लेकिन इसे रुकने नहीं देना है, बल्कि इसे पहले की तरह ही प्रभावी ढंग से जारी रखना होगा। टीका बच्चों के जीवन का ऐसा सुरक्षा चक्र है, जिसे लगाने से वे टीबी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, खसरा सहित कई घातक बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं। इसलिए टीका जिंदगी बचाने के लिए विज्ञान की सबसे बड़ी खोज में से एक है।

लगभग एक दर्जन बीमारियों के टीके लगाए जा रहे हैं: देश में टीकाकरण का अभियान बहुत पुराना है। पहले छह बीमारियों से बचाव के लिए बच्चों को टीके लगाए जाते थे। इसके तहत टीबी से बचाव के लिए बीसीजी का टीका, डिप्थीरिया, काली खांसी व टिटनेस से बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगता था। बाद में इस अभियान में पोलियो, हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड, हीमोफिलस इंफ्लुएंजा टाइप बी, रूबेला, डायरिया इत्यादि के टीके भी शामिल होते चले गए। मौजूदा समय में मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत करीब एक दर्जन बीमारियों से बचाव के लिए बच्चों को टीके लगाए जाते हैं।

लाकडाउन में पड़ा असर: पिछले साल कोरोना संक्रमण शुरू होने के बाद लाकडाउन लगने पर अस्पतालों में ओपीडी बंद हो गई थी, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं संचालित हो रही थीं। संक्रमण से बचाव के लिए लोग भी घर से ज्यादा बाहर नहीं निकल रहे थे। बच्चों को अस्पताल लेकर जाने में लोग घबरा रहे थे। यातायात प्रभावित होने से दूर दराज के लोगों को अस्पताल पहुंचने में भी परेशानी थी। इन कारणों से जीवनरक्षक टीका लगाने का अभियान कुछ हद तक जरूर प्रभावित हुआ है। दूसरी लहर में भी देश के ज्यादातर हिस्सों में लाकडाउन हुआ। इस दौरान भी बच्चों के रूटीन टीकाकरण अभियान पर असर पड़ा, लेकिन दूसरी लहर में एम्स में बच्चों का रूटीन टीकाकरण जारी रखा गया और ओपीडी पंजीकरण की बाध्यता भी खत्म कर दी गई और यह व्यवस्था की गई कि माता-पिता बच्चे को लेकर सीधे टीकाकरण कमरे में पहुंच सकते हैं। जहां नर्स द्वारा बच्चे के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग के बाद तुरंत टीका लगा दिया जाता है। बच्चे के बीमार होने की आशंका होने पर डाक्टर को दिखाना जरूरी है। इसी आधार पर हर जगह रूटीन टीकाकरण को जारी रखना होगा। रूटीन टीकाकरण के लिए दिन भी निर्धारित हैं। यह कोशिश होनी चाहिए कि उस दिन बच्चों के टीकाकरण में कोई बाधा न आने पाए।

रूटीन टीकाकरण कम होने पर बीमारियां दोबारा बढ़ने का खतरा: देश में अब भी पांच साल तक की उम्र के बच्चों की मौत का एक बड़ा कारण डायरिया है। इस वजह से राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में रोटा वायरस के टीके को शामिल किया गया है, क्योंकि यह देखा गया है कि देश में बच्चों में डायरिया का सबसे बड़ा कारण रोटा वायरस का संक्रमण है। इसके टीके के जरिए डायरिया के कारण होने वाली बच्चों की मौतों को कम किया जा सकता है। दो दशक पहले देश में शिशु मृत्यु दर 100 के करीब थी, जो अब घटकर 30 से कम हो गई है। हालांकि, शिशु मृत्यु दर कम होने के कई अन्य कारण भी हैं। इसलिए इसका 100 फीसद श्रेय सिर्फ टीकाकरण को तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन शिशु मृत्यु दर कम करने में रूटीन टीकाकरण ने अहम भूमिका निभाई है। टीके के कारण ही चिकेन पाक्स की बीमारी पूरी तरह खत्म हो गई है। देश पोलियो मुक्त भी हुआ। खसरा, काली खांसी, डिप्थीरिया व टिटनेस की बीमारी भी काफी कम हो गई है। टीकाकरण यदि कम हुआ तो यह बीमारियां दोबारा बढ़ सकती हैं। कुछ देशों में देखा जा रहा है कि काली खांसी की बीमारी दोबारा वापस आ गई है।

बीत गया हो टीकाकरण का समय तो भी लगवाएं टीका: बच्चों के लिए टीके आवश्यक हैं। यदि आपके बच्चे का कोई टीका रह गया हो, जो किसी कारण नहीं लग पाया है तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी, अस्पताल या बच्चों के डाक्टर के पास जाकर टीका लगवाएं। अस्पताल में मास्क पहनकर पूरी सतर्कता के साथ जाएं और कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करते हुए टीका लगवाएं। इससे बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा। यदि बच्चों को टीका लेने में तीन से नौ माह की देर भी हो गई है तब भी यह न समझें कि अब टीका नहीं लग सकता। रूटीन टीकाकरण नहीं कराने पर बच्चों को बाद में दूसरी तरह की परेशानियां होने लगेंगी। टीकाकरण अभियान के तहत बच्चों को नौ माह, 18 माह व ढाई साल पर विटामिन ए की खुराक भी दी जाती है। यह बच्चों के विकास के लिए जरूरी है। इससे बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। इससे शिशु मृत्यु दर में कमी आती है। इसलिए विटामिन ए की खुराक देना भी जरूरी है।

प्रस्तुतिः रणविजय सिंह

जन्म के छह माह के अंदर आवश्यक टीके लगवाना जरूरी

बच्चे के जन्म होने के 24 घंटे के भीतर बीसीजी, पोलियो व हेपेटाइटिस बी के टीके की पहली खुराक दे दी जाती है। इसके बाद छह सप्ताह, 10 सप्ताह व 14 सप्ताह पर पोलियो व पेंटावेलेंट टीका दिया जाता है। पेंटावेलेंट के रूप में पांच बीमारियों डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी व हीमोफिलस इंफ्लुएंजा टाइप बी के लिए एक टीका दिया जाता है। जन्म के छह माह के अंदर ये टीका जरूर लगवा देने चाहिए ताकि इन घातक बीमारियों से बच्चों का बचाव हो सके। कई राज्यों में रोटावायरस का भी टीका लगने लगा है और दो साल में टायफाइड का टीका लगाया जाता है।

दिल को बचाएं कोरोना वायरस के हमले से

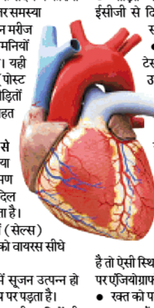
इसे भी जानें



पद्मविभूषण डा. पुरुषोत्तम लाल
सीनियर कार्डियोलाजिस्ट एवं चेयरमैन, मैट्रो ग्रुप आफ हास्पिटल्स, नोएडा

कोरोना वायरस शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करने के साथ ही दिल को भी पहुंचाता है नुकसान। इसलिए इससे उबरने के बाद भी बरतें एहतियात...

एक बड़ी संख्या में लोगों के दिमाग में यह धारणा अभी तक व्याप्त है कि कोरोना वायरस सिर्फ फेफड़ों को ही क्षतिग्रस्त करता है या उन्हें नुकसान पहुंचाता है। यह सच है कि कोविड-19 वायरस का बुरा असर फेफड़ों पर पड़ता है, लेकिन इसके साथ ही यह दिल (हार्ट) और उसकी रक्तवाहिकाओं पर भी हमला करता है। हृदय को क्षति पहुंचाने के संदर्भ में कोरोना वायरस से उपजी समस्या वैस्कुलर समस्या होती है। कोविड संक्रमण के दौरान मरीज के हृदय और उसकी सूक्ष्म धमनियों पर इसका बुरा असर पड़ता है। यही नहीं कोविड संक्रमण के बाद (पोस्ट कोविड) भी अनेक मामलों में पीड़ितों के दिल व उनके सिस्टम की सेहत दुरुस्त नहीं पाई गई।



वायरस का दिल पर चार प्रकार से असर: अधिसंख्य मामलों में पाया गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के समय और संक्रमण के बाद दिल को चार तरह से नुकसान पहुंचाता है।

- दिल (हार्ट) की कोशिकाओं (सेल्स) में रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर्स को वायरस सीधे तौर पर प्रभावित करता है।
- वायरस के असर से शरीर में सूजन उत्पन्न हो जाती है, जिसका बुरा असर हृदय पर पड़ता है।
- वायरस का प्रतिकूल प्रभाव हृदय की धमनियों की इनर लाइनिंग (एंडोथीलियम) पर भी पड़ता है। इस प्रतिकूल प्रभाव से धमनियों की इनर लाइनिंग नष्ट हो जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप धमनियों में रक्त के थक्के बनने लगते हैं। इस स्थिति में हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है।
- कोविड-19 वायरस हार्ट के सिस्टम पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके कारण पोस्ट कोविड पीरियड में दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है। यहां तक कि अनेक पोस्ट कोविड मरीजों को पेसमेकर की भी आवश्यकता पड़ सकती है।

इन बातों पर दें ध्यान

- कोविड से उबरने के बाद की स्थिति (पोस्ट कोविड) में मरीज का ब्लडप्रेशर बढ़ सकता है और कम भी हो सकता है।
- जिन मरीजों को पहले से ही हार्ट की समस्या हो चुकी है, उनमें हार्ट की समस्या बढ़ने की ज्यादा संभावना रहती है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि कोविड वायरस से हृदय की धमनियों में रक्त के थक्के बनने लगते हैं। जिन लोगों को स्टंट लग चुका है, उनमें रक्त के गाढ़ा होने का खतरा बढ़ जाता है। रक्त के गाढ़ा होने के कारण स्टंट में ब्लड क्लाट्स हो सकता है।

प्रमुख जांचें

- इकोकार्डियोग्राफी से हृदय की मांसपेशियों (हार्ट मसल्स) में होने वाली क्षति का पता चलता है।
- पीड़ित व्यक्ति की 24 घंटे तक मानीटरिंग और ईसीजी से दिल या इसकी धड़कन से संबंधित समस्या का पता चल जाता है।
- लिपिड प्रोफाइल और डी-डाइमर टेस्ट कराए जाते हैं।

उपचार

- बड़ी संख्या में कोविड से उबर चुके लोगों में आमतौर पर कमजोरी और डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है। ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने व जूस लेने की सलाह दी जाती है।
- चिकित्सक के चेकअप के बाद अगर किसी व्यक्ति को सीने में दर्द रहता है या फिर उसकी सांस फूलती है तो ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति की जरूरत पड़ने पर एंजियोग्राफी करवाई जाती है।
- रक्त को पतला करने वाली दवाएं दी जाती हैं।

सजगता बरतें कोरोना संक्रमण के बाद

- ब्लड प्रेशर की नियमित रूप से जांच करें या करवाते रहें।
- डायबिटीज से ग्रस्त हैं तो चिकित्सक के परामर्श से अपने ब्लड शुगर को नियंत्रित रखें।
- कोरोना से मुक्त हो चुके लोगों को अपनी शारीरिक गतिविधियों को धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए।
- फलों व हाईफाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को खानपान में वरीयता देनी चाहिए।

किसी भी उम्र में हो सकते हैं बाल सफेद

हेल्थ फाइल



डा. अनूप धीर
सीनियर कास्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन, अपोलो हास्पिटल, नई दिल्ली

असमय बालों का सफेद होना कई कारणों से होता है। यदि विटामिंस की कमी या त्वचा विकार के कारण बाल सफेद हो रहे हैं तो ही उपचार से इसे रोका जा सकता है...



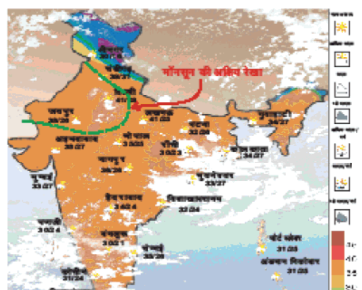
बढ़ती उम्र के साथ बालों का रंग बदलना कुदरती है, लेकिन बालों में सफेदी उम्र के किसी भी दौर में दिखाई दे सकती है। यहां तक कि किशोरों में और 20-22 साल के युवाओं के बालों में भी सफेदी की झलक उभर सकती है। मनुष्य के शरीर में लाखों हेयर फालिकल्स होते हैं, ये त्वचा की भीतरी परत पर छोटी-छोटी थैलियों जैसे होते हैं। इनसे ही बाल पनपते हैं और बालों को रंग देने वाला मेलानिन पदार्थ पैदा करने वाले सेल्स भी यहीं बनते हैं। समय के साथ हेयर फालिकल्स अपने पिगमेंट सेल्स खोने लगते हैं जिसके कारण बालों की रंगत सफेद पड़ने लगती है।

विटामिंस की कमी भी है कारण: विटामिन बी6, बी12, डी, ई और बायोटिन की कमी की वजह से भी समय से पहले बालों में सफेदी आने लगती है। बालों की सफेदी आमतौर पर आनुवांशिक होती है, लेकिन शरीर में तनाव (आक्सीडेटिव स्ट्रेस) की वजह से भी समय से पहले ऐसा हो सकता है। आक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से शरीर में असंतुलन बढ़ता है और इस स्थिति में शरीर में फ्री रेडिकल्स के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए पर्याप्त एंटीआक्सीडेंट्स मौजूद नहीं होते हैं। फ्री रेडिकल्स दरअसल, अस्थिर अणुओं को कहते हैं, जिनके कारण कोशिकाओं को क्षति पहुंचती है और शरीर रोगों की चपेट में आता है।

त्वचा विकार है बालों की सफेदी: आक्सीडेटिव स्ट्रेस अधिक होने से रोग बढ़ते हैं, स्किन पिगमेंटेशन कंडीशन या विटिलिगो की आशंका भी बढ़ जाती है। विटिलिगो की वजह से भी बालों से सफेदी झांकने लगती है, जो कि मेलानिन कोशिकाओं के खत्म हो जाने या उनकी कार्यक्षमता नष्ट होने की वजह से होता है। सफेद बाल एक खास तरह के त्वचा संबंधी विकार एलोपेसिया अरेटा के कारण भी हो सकते हैं। इस स्थिति में सिर के बाल झड़ते हैं और जब दोबारा बाल बढ़ते हैं तो मेलानिन की कमी के कारण सफेद हो जाते हैं।

तनाव भी है एक प्रमुख कारण: जीवन में तनाव का होना, जो कि किसी चोट की वजह से भी हो सकता है, भी समय से पहले बालों को सफेद करने का कारण बन सकता है। इसी तरह, धूमपान करने वाले लोगों में 30 साल की उम्र से पहले ही बालों के सफेद होने की संभावना दो से ढाई गुना तक बढ़ जाती है। विभिन्न तरह की हेयर डाई, हेयर कलर्स और अन्य हेयर प्रोडक्ट्स, यहां तक कि शैंपू वगैरह के इस्तेमाल से भी बालों का समय पूर्व सफेद होना देखा गया है। कारण, इन प्रोडक्ट्स में नुकसान पहुंचाने वाले कई तत्व मौजूद होते हैं, जो मेलानिन की मात्रा घटाते हैं। अधिकांश डाई में मौजूद हाइड्रोजन पैराक्साहइड ऐसा ही एक खतरनाक रसायन है। इसका अत्यधिक इस्तेमाल बालों को ब्लीच करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाल सफेद हो जाते हैं।

आनुवांशिक हैं तो नहीं है इलाज: याद रखिए कि अगर बालों में सफेदी का कारण आनुवांशिक या बढ़ती उम्र है तो आप किसी तरह से इसे रोक नहीं सकते, लेकिन अगर बालों में सफेदी का कारण कोई मेडिकल कंडीशन है तो आप हेयर ट्रीटमेंट से बालों का कलर पिगमेंटेशन लौटा सकते हैं। इसी तरह अगर खानपान और विटामिंस-मिनरल्स आदि की कमी के कारण बाल असमय सफेद हो रहे हैं तो उपचार द्वारा इस समस्या को गंभीर होने से रोका जा सकता है। इसके लिए सही उपचार काम आता है और बालों को सफेद होने से पूरी तरह से रोका जा सकता है। कुछ मामलों में तो इस प्रक्रिया को रिवर्स भी किया जा सकता है। नियमित रूप से कुछ प्राकृतिक उपाय बालों के सफेद होने की प्रक्रिया को काफी हद तक धीमा कर सकते हैं या मुमकिन है कि इसे रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन एक समय तो ऐसा आता ही है कि हरेक के बाल सफेद होते ही हैं।





राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 7 जुलाई, 2021
आजकल
14
www.jagran.com

भारत में सिनेमा का आगाज, पहली बार छह फिल्मों का प्रदर्शन

वर्ष 1896 में आज ही के दिन भारत में सिनेमा का प्रवेश हुआ था। बंबई (अब मुंबई) के वाटसन होटल में फ्रांस के ल्यूमिर बंधुओं (चलती फिल्मों के जन्मदाता) ने पहली बार छह फिल्मों का प्रदर्शन किया था। पहले दिन 200 से ज्यादा दर्शकों ने एक-एक रुपये देकर फिल्म देखी थी।





दुनिया ने पहली बार चखा स्लाइस्ड ब्रेड का स्वाद

वर्ष 1928 में आज ही के दिन स्लाइस्ड ब्रेड की बिक्री अमेरिका में शुरू हुई थी। इसे जो ओट्टो रोहवेडर की बनाई मशीन से काटा गया था। इसे क्लीन मेड स्लाइस्ड ब्रेड के नाम से प्रचारित किया गया था। रोहवेडर 1917 में भी मशीन बना रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिली थी।

कभी स्पोर्ट्स में मेडल जीतना चाहते थे राकेश ओम प्रकाश मेहरा

भाग मिल्खा भाग जैसी हिट फिल्में बनाने वाले निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा का जन्म वर्ष 1963 में आज ही के दिन हुआ था। एक वक्त ऐसा था जब वे खेलों में देश के लिए मेडल जीतना चाहते थे। जब वह इस क्षेत्र में करियर नहीं बना पाए तो एड इंडस्ट्री से जुड़ गए। 2001 में फिल्म अक्स से बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म भले ही हिट साबित नहीं हुई, लेकिन उनके काम को सभी ने सराहा। उन्हें पहचान फिल्म 'रंग दे बसंती' से। आमिर खान स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर और नेशनल अवॉर्ड भी मिला।



मंगल के दक्षिणी ध्रुव के नीचे झीलों की मौजूदगी पर आशंका

न्यूयार्क, आइएएनएस : दूसरे ग्रहों पर मानव बस्तियां बसाने का सपना देख रहे विज्ञानी इस दिशा में निरंतर अध्ययन करते रहते हैं। इसी क्रम में एक अहम तथ्य सामने आया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर से प्राप्त डाटा का प्रयोग कर जिसे मंगल के दक्षिणी ध्रुव के नीचे पाई जाने वाली उपसतह झीलें बताया गया था, वास्तव में वे झीलें नहीं हो सकती हैं। 2018 में दो शोध दलों ने इस आश्चर्यजनक खोज की घोषणा की थी। उस वक्त लाल ग्रह के दक्षिणी ध्रुव से मिले परावर्तित रडार सिग्नल्स से झील होने का दावा किया गया था।

वहीं, अब नासा और एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी (एएसयू) के विज्ञानियों के एक दल ने मंगल एक्सप्रेस डाटा के व्यापक सेट का विश्लेषण करने के बाद दक्षिणी ध्रुव के आसपास दर्जनों समान रडार प्रतिबिंब पाए हैं। उनके अनुसार, जिन क्षेत्रों में पहले झीलें होने का दावा किया गया था, वहां पानी तरल अवस्था में मौजूद हो इसकी बेहद कम संभावना है, क्योंकि वे क्षेत्र बेहद ठंडे हैं। इतने ठंडे वातावरण में पानी तरल अवस्था में नहीं रह सकता है।

एएसयू के स्कूल आफ अर्थ एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन के आदित्य खुल्लर के मुताबिक, आमतौर पर रडार तरंगें किसी सामग्री के माध्यम से यात्रा करते समय ऊर्जा खो देती हैं। इसलिए गहराई से



पूर्व के अध्ययन में तरल अवस्था में पानी होने के मिले थे संकेत। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

प्रतिबिंब सतह से कम चमकदार होनी चाहिए। हालांकि, उपसतह के असामान्य रूप से चमकदार होने के कुछ और कारण भी हो सकते हैं। इन दो अध्ययनों से निष्कर्ष निकाला गया था कि तरल अवस्था में मौजूद पानी इन चमकदार प्रतिबिंबों का कारण हो सकता है, क्योंकि तरल अवस्था में पानी रडार पर चमकदार दिखाई देता है। मूल रूप से मार्टियन साउथ पोलर लेयर्ड डिपॉजिट के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में लगभग 10 से 20 किलोमीटर तक तरल पानी होने की परिकल्पना की गई थी।

नए अध्ययन के लिए विज्ञानियों के दल ने मंगल ग्रह के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र का विस्तार से अध्ययन किया। 15 वर्षों के दौरान एकत्र की गईं 44 हजार मापों के डाटा का विश्लेषण रेडियो सिग्नल्स से किया गया। इसमें पूर्व में किए गए अध्ययन की तुलना में चमकदार प्रतिबिंबों की संख्या अधिक मिली। कुछ स्थानों पर तो ऐसी चमकदार सतह एक मील के करीब थीं, जहां तापमान शून्य से 63 डिग्री सेल्सियस कम होने का अनुमान है। इतने ठंडे वातावरण में तो पानी जम जाता है, भले ही उसमें नमकीन खनिज मिले हों। ऐसे में इन चमकदार सतहों के पानी होने की बात सही साबित होती प्रतीत नहीं होती।

नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी (जेपीएल) के जेफरी प्लाट के मुताबिक, हम यह स्पष्ट नहीं कर सकते कि ये सिग्नल्स तरल अवस्था में मौजूद पानी के हैं या नहीं, लेकिन वे मूल पेपर की तुलना में कहीं अधिक व्यापक प्रतीत होते हैं। मंगल के दक्षिणी ध्रुव के नीचे या तो तरल पानी आम है, या ये सिग्नल्स किसी और चीज की तरफ इशारा करते हैं। फिलहाल इस पर और अध्ययन की आवश्यकता है।



नदी के तट पर उकेरी कलाकृति...

अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का कला एक सशक्त माध्यम है। मूर्ति कला, ग्राफिक्स, सैंड आर्ट और विजुअल आर्ट के जरिये आर्टिस्ट जब अपनी कल्पनाओं को साकार करते हैं तो लोग बेहद प्रभावित होते हैं। क्रोएशिया के शहर ओपुजेन में हर साल स्ट्रीट फेस्टिवल जेन ओपुजेन आयोजित होता है। इसमें विश्वभर के कलाकार सार्वजनिक स्थलों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। नदी के तट पर रेत में यह विशाल कलाकृति आर्टिस्ट निकोसा फलेर ने बनाई है। इस आर्ट फेस्टिवल का मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों एवं पर्यटकों के बीच सार्थक संवाद कायम करना है। रायटर

इधर-उधर की

मालिक को सुख-दुख बताने वाली फीमेल डॉग

लंदन, एजेंसी : कुत्तों को इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। वह न केवल अपने मालिक के सुख-दुख को समझते हैं, बल्कि अपने गुस्से व खुशी को भी साझा करते हैं। लंदन में रहने वाली लैब्रोडोर प्रजाति की फीमेल डॉग कूपर अपनी प्रजाति के दूसरे जानवरों से थोड़ा आगे है। वह न केवल अपने सुख-दुख और खिलौने मांगने जैसी बातों को बताती है, बल्कि भूख लगने पर खाने की डिमांड भी करती है। दरअसल, ये सब कूपर की 50 वर्षीय मालकिन टिया के चलते संभव हुआ है। टिया पेशे से भाषा विज्ञानी हैं और उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है, जिसके जरिये कूपर अपनी डिमांड बताती है। टिया कूपर को बहुत छोटी उम्र से प्रशिक्षित कर रही हैं। उन्होंने शुरुआत में छोटे-छोटे निर्देश दिए, जिसका उसने बखूबी पालन किया। मौजूदा समय में इस डिवाइस में 40 बटन हैं और कूपर इनके माध्यम से अपनी सभी बातें घरवालों को बताती है।



डिवाइस में मौजूद 40 बटनों के जरिये कूपर घरवालों को सभी बातें बताती है • इंटरनेट मीडिया

हमारी क्षमताओं को बढ़ा रही स्मार्ट टेक्नोलाजी

दूसरा पहलू ▶ अभी तक कहा जाता रहा है कि गैजेट्स हमारी सोच को कर रहे हैं कमजोर

ओहियो, एएनआइ : अक्सर कहने-सुनने में आता है कि गैजेट्स हमारी सोचने-समझने की क्षमता कम कर रहे हैं। मोबाइल फोन, टैबलेट आदि के ज्यादा प्रयोग से हमारी रचनात्मकता पर असर पड़ रहा है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि मोबाइल फोन के आने के बाद से उन्हें दूसरों के फोन नंबर याद नहीं होते। ऐसी एक अवधारणा बनती जा रही है कि स्मार्ट टेक्नोलाजी हमें मानसिक रूप से कमजोर कर रही है। ...लेकिन हकीकत कुछ और ही है। दरअसल, यूनिवर्सिटी आफ सिनसिनाटी (यूसी) के शोधकर्ताओं के अध्ययन में सिक्के के दूसरे पहलू को भी बताया गया है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंथनी चेमेरो के मुताबिक, स्मार्ट टेक्नोलाजी के प्रयोग से जुड़ी कई नकारात्मक बातें हमें बताई गई हैं, लेकिन इसका सकारात्मक पहलू भी है।

इस अध्ययन के सह लेखक और यूसी में दर्शन और मनोविज्ञान के प्रोफेसर एंथनी चेमेरो कहते हैं, हेडलाइंस के अलावा, वैज्ञानिक रूप से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह साबित करता हो स्मार्ट और डिजिटल टेक्नोलाजी हमारी सोचने-समझने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही हो। अपने शोध पत्र में चेमेरो और टोरंटो यूनिवर्सिटी के रोटमैन स्कूल आफ मैनेजमेंट के उनके सहयोगियों ने डिजिटल युग के विकास पर विस्तार पर बताया कि कैसे स्मार्ट टेक्नोलाजी हमारी सोच को नए आयाम देती है। बकौल प्रो. चेमेरो ऐसा प्रतीत होता है कि स्मार्टफोन और डिजिटल तकनीक हमारे सोचने-समझने की क्षमता को प्रभावित करती है। इसे लेकर नकारात्मक बातों का प्रचार किया गया है। दरअसल, हकीकत यह है कि ये हमारे सोचने-समझने की क्षमता को फायदा पहुंचाते हैं। प्रो. चेमेरो ने उदाहरण स्वरूप बताया कि आपका स्मार्टफोन क्रिकेट स्टेडियम या कोई और खास जगह के बारे में जानता है। ऐसे में आपको न तो किसी नक्शे की आवश्यकता होती है और न ही किसी से रास्ता पूछने की जरूरत। ऐसे में आपके मस्तिष्क को राहत मिलती है। वह आजाद होता है दूसरे कार्य करने या कुछ और सोचने के लिए। साथ ही यह भी सच है कि आज स्मार्ट टेक्नोलाजी की वजह से हम गणित के कठिन सवालों को हल करने के लिए कागज और कलम पर निर्भर नहीं हैं और न ही हमें ढेर सारे फोन नंबर याद करने की जरूरत होती है। इन कार्यों के लिए हमारे पास कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन जैसे उपकरण हैं। ये हमारे सहायक के रूप में कार्य करते हैं। यह गणित की कठिन गणनाएं और कठिन सवाल हल करने में हमारी मदद करते हैं। साथ ही हमारा बहुत सा डाटा अपने में संग्रहित रखते हैं। इससे हमारा मस्तिष्क कुछ आजाद रहता है, जिस वजह से वह अन्य महत्वपूर्ण कार्य बेहतर ढंग से कर सकता है।

यहां भी मिलती है मदद : यूनिवर्सिटी आफ टोरंटो में पीएचडी के छात्र व इस शोध पत्र के प्रमुख लेखक लोरेंजो सेकुट्टी के मुताबिक, स्मार्ट टेक्नोलाजी हमें निर्णय लेने में भी मदद करती है। वह जीपीएस तकनीक का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि इस तकनीक के जरिये हमें पता होता है कि किस रास्ते पर ट्रैफिक की क्या स्थिति है। ऐसे में हमें निर्णय लेने में आसानी होती है कि मंजिल पर पहुंचने के लिए किस रास्ते का चुनाव करना बेहतर होगा। किसी नए शहर में तो यह तकनीक बहुत ही लाभकारी साबित होती है और इसका लाभ हममें से कई लोग उठा रहे हैं।



नए अध्ययन में बताया गया कि दरअसल, मोबाइल, कंप्यूटर व दूसरे उपकरण हमें बना रहे हैं बेहतर। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

राहत पहुंचाती तकनीक

प्रो. चेमेरो के मुताबिक, स्मार्ट टेक्नोलाजी आज हमारी सोच को नए आयाम दे रही है। यह हमारे कार्य आसान करती है। हमारे मस्तिष्क को बेहतर सोचने और निर्णय लेने के लिए रास्ता उपलब्ध कराती है। ऐसे में इसके अभी तक के बताए जा रहे सिर्फ नकारात्मक पहलुओं पर ही विचार नहीं करना चाहिए, जिनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। दरअसल, हमें तो इसे अपने लिए लाभकारी मानते हुए इसका सही प्रयोग करने की दिशा में और उचित कदम उठाए जाने के बारे में सोचना चाहिए।

खानपान में बदलाव करने से कम किया जा सकता है सिर दर्द

अनुसंधान



द बीएमजे जर्नल में प्रकाशित हुआ अध्ययन। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

एक अध्ययन में सामने आया है कि जंक फूड से भी सिरदर्द की समस्या बढ़ सकती है। आप अपने खानपान में बदलाव करके इस समस्या को काफी हद तक कम या खत्म कर सकते हैं। यह जानकारी नए अध्ययन में सामने आई है। इस अध्ययन में 16 सप्ताह की अवधि में फैटी एसिड के आधार पर खानपान में किए गए बदलाव से रोगियों में सिरदर्द की कमी देखी गई। यह अध्ययन द बीएमजे जर्नल में प्रकाशित हुआ है। दुनियाभर में माइग्रेन (एक प्रकार का सिरदर्द) एक बड़ी समस्या है। वर्तमान में माइग्रेन का जो इलाज है, उससे समस्या का पूरा निराकरण नहीं हो पा रहा है। अध्ययन से यह सामने आया है कि सिरदर्द के मरीज खानपान में बदलाव करके इस समस्या से काफी हद तक राहत पा सकते हैं। अध्ययन करने वाले दल का नेतृत्व करने वाली यूएनसी स्कूल आफ मेडिसिन की असिस्टेंट प्रोफेसर डेजी जामोरा ने बताया कि हमारे पूर्वजों का के खानपान में वसा की मात्रा वर्तमान समय से बिल्कुल अलग थी। जामोरा ने बताया कि पाली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हमारा शरीर नहीं बनाता है, लेकिन हमारे खानपान में चिप्स, क्रेकर्स और ग्रेनोला जैसे जंक फूड शामिल हो गए हैं, जो इस एसिड की मात्रा बढ़ा देते हैं। इस अध्ययन में 182 माइग्रेन रोगियों पर 16 सप्ताह तक परीक्षण किया गया। इन सभी को वर्गीकृत कर अलग-अलग खानपान दिया गया। देखने में आया कि जंक फूड न लेने वालों में माइग्रेन यानी सिरदर्द में काफी राहत देखी गई। -एएनआइ

स्क्रीन शॉट

16 जुलाई को राहुल और दिशा हो जाएंगे एकदूजे के



बिग बॉस 14 में दिशा को शादी के लिए प्रपोज किया था राहुल ने। इंस्टाग्राम

गायक राहुल वैद्य और अभिनेत्री दिशा परमार जल्द ही एक-दूसरे संग शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हैं। अपनी शादी का एलान राहुल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर किया है। उन्होंने लिखा कि हमारे परिवारों के आशीर्वाद से हम बेहद खुशी के साथ आप लोगों के साथ इस खास मौके को साझा कर रहे हैं। हमारी शादी 16 जुलाई को हो रही है। हमें अपने इस प्यार और साथ वाले नए अध्याय की शुरुआत के लिए आपके प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। सप्रेम दिशा और राहुल। इसके साथ ही राहुल ने अपने और दिशा के नाम को मिलाते हुए हैशटैग के साथ दिशाहुलवेडिंग लिखा। दिशा और राहुल के बीच प्यार की शुरुआत दोस्ती से हुई थी। बिग बॉस 14 में राहुल ने अपनी इस दोस्ती को प्यार और शादी में बदलने का फैसला किया। उन्होंने शो पर ही दिशा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। बिग बॉस से बाहर आने के बाद दिशा ने राहुल के इस प्रपोजल का जवाब हां में दिया। राहुल पिछले दिनों केप टाउन से खतरों के खिलाड़ी 11 की शूटिंग करके लौटे हैं। वहां से आने के बाद राहुल ने दिशा से शादी का एलान कर दिया। बिग बॉस 14 में राहुल के दोस्त बने अली गोनी इस खबर से बेहद खुश हैं। उन्होंने राहुल को बधाई देते हुए लिखा कि तुम आज कितने खुश हो, यह मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। कितनी बातें हमने रात में आसमान को देखते हुए की हैं। तुम कहते थे कि कब दिशा से मेरी शादी होगी, कब वह मेरी बीवी बनेगी। आखिरकार वह दिन आ ही गया।



लंबे समय के बाद अभिनय में लौट रही हैं ईशा देओल • जागरण आर्काइव

डिजिटल प्लेटफॉर्म मेरे लिए नया है। सीरीज की स्क्रिप्ट में जो मेरा किरदार है, वह बहुत ही अलग है। जल्द ही इस पर काम शुरू होगा।

क्राइम ड्रामा सीरीज में अजय संग होंगी ईशा

कई कलाकार डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसमें अब अभिनेत्री ईशा देओल का नाम भी शुमार हो गया है। धूम और नो एंट्री जैसी फिल्में कर चुकीं ईशा देओल तख्तानी लंबे वक्त बाद लाइमलाइट में वापसी कर रही हैं। अजय देवगन के साथ ईशा क्राइम ड्रामा सीरीज रुद्रः द एज ऑफ डार्कनेस से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करेंगी। अजय और ईशा ने साथ में एलओसी कारगिल, काल, युवा, मैं ऐसा ही हूं जैसे कई फिल्में की हैं। अप्लॉज एंटरटेनमेंट और बीबीसी स्टूडियोज इंडिया बड़े स्केल पर बनने वाली इस सीरीज का निर्माण कर रहे हैं। ईशा ने दैनिक जागरण से बातचीत में बताया कि काम पर दोबारा लौटने को लेकर मैं बहुत उत्सुक हूं। खासकर अजय के साथ काम करने को लेकर तो बहुत खुश हूं। हमने साथ में कई फिल्मों में काम किया है। हमारे बीच में बतौर कलाकार काफी सहजता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का फॉर्मेट मेरे लिए नया है। इस फॉर्मेट पर काम करने के लिए भी काफी उत्सुक हूं। सीरीज की स्क्रिप्ट में जो मेरा किरदार है, वह बहुत ही अलग है। मेरे साथ अजय का भी यह डिजिटल डेब्यू होगा। जल्द ही इस सीरीज के प्रोडक्शन पर काम शुरू होगा। इस सीरीज को मुंबई की लोकल ट्रेन में शूट किया जाएगा। यह ब्रिटिश सीरीज लूथर का भारतीय संस्करण होगा, जिसे देश के दर्शकों के मुताबिक बनाया जाएगा। यह सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआइपी पर इस साल स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अजय की आगामी फिल्म भुजः द प्राइड ऑफ इंडिया भी 13 अगस्त को रिलीज होगी। इसकी रिलीज डेट का एलान अजय ने मंगलवार को ट्विटर पर किया।

चार साल बाद उसी सेट पर शूट करके किरदार को पकड़ने में मदद मिली

वेब सीरीज की तर्ज पर इन दिनों टेलीविजन जगत में धारावाहिकों के भी अलग-अलग सीजन लाने का चलन जोरों पर है। इसी क्रम में 2016 में शुरू हुए धारावाहिक कुछ रंग प्यार के ऐसे भी का तीसरा सीजन 12 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जिसमें अभिनेता शहीर शेख, अभिनेत्री एरिका फर्नांनडीज और सुप्रिया पिलगांवकर एक बार फिर अपने-अपने क्रमशः देव, सोनाक्षी और ईश्वरी के किरदारों में नजर आएंगे। शो का दूसरा सीजन 2017 में खत्म हुआ था। करीब चार साल बाद दोबारा अपने किरदार में वापसी पर शहीर का कहना है, 'इन किरदारों ने हमें कभी छोड़ा ही नहीं था। मैं निर्माताओं को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने पिछले सीजन की पूरी टीम को इस सीजन में भी साथ रखा है। सेट पर जाते ही हमें देजा वू (पहले की तरह) जैसा अहसास हुआ। इससे एक-दूसरे के साथ हमारी सहजता बरकरार रही। इस बार भी हम उसी सेट पर शूट कर रहे हैं, जहां करीब चार साल पहले दूसरे सीजन की शूटिंग होती थी। इससे किरदार में दोबारा लौटने में काफी आसानी हुई। देव का किरदार दोबारा पकड़ने में मुझे कुछ मुश्किलें भी आईं, क्योंकि उसका किरदार कई पहलुओं वाला है और इस बार निर्माताओं ने एक नया पहलू छेड़ा है। शुरुआत में उसे समझना थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अब धीरे-धीरे किरदार पकड़ में आ रहा है।' यह बातें शहीर ने मंगलवार को आयोजित इस धारावाहिक की वर्चुअल कान्फ्रेंस में कहीं, जहां धारावाहिक के कलाकारों के अलावा इसके लेखक और निर्माता भी मौजूद रहे।



कुछ रंग प्यार के ऐसे भी-नई कहानी में एक बार फिर से देव के किरदार में दिखेंगे शहीर। सौ. टीम सोनी

अनुपम ने लियोनार्डो डिकैप्रियो से अपनी मुलाकात को किया याद

इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कलाकार जहां अपने प्रोजेक्ट्स और विचारों को अपने प्रशंसकों के बीच साझा करते हैं, वहीं कुछ कलाकार इस प्लेटफॉर्म के जरिये प्रशंसकों को अपनी अतीत की गलियों में ले जाकर उन्हें अपने जीवन की दिलचस्प घटनाओं से भी रूबरू कराते हैं। अभिनेता अनुपम खेर भी उन्हीं कलाकारों में से एक हैं। सोमवार की रात उन्होंने हॉलीवुड अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा करते हुए प्रशंसकों को उनकी मुलाकात की कहानी बताई।

इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, 'कुछ वर्ष पहले मैं लास एंजेलिस के एक इवेंट पर लियोनार्डो डिकैप्रियो से मिला। मैंने उन्हें अपना परिचय दिया। मैंने कहा कि मैं एक भारतीय अभिनेता हूं। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं। फिर मैंने पूछा कि कैसे। उसके बाद उन्होंने मुझे गर्मजोशी से गले लगा लिया। वह दयालु और उदार थे। एक्टर होने की सबसे बेहतरीन चीज यह है कि आप दुनिया भर के शानदार लोगों से मिलते हैं और उनके साथ बहुत ही सहजता से जुड़ जाते हैं। एक्टर्स अपने आप में एक प्रजाति हैं।'

इससे पहले अनुपम ने हाल ही में फिल्मकार यश चोपड़ा के साथ तस्वीर साझा करते हुए उन्हें याद किया था। काम की बात करें तो अनुपम आगामी दिनों में नौटंकी और द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों में नजर आएंगे।

मुझे पता था कि फिल्म पर साल भर काम करना है

अभिनेता फरहान अख्तर की भाग मिल्खा भाग के बाद तूफान उनकी खेल पर आधारित दूसरी फिल्म है। फिल्म में फरहान रिंग में बॉक्सिंग खेलते दिखेंगे। इंस्टाग्राम पर लाइव के दौरान फरहान दो बॉक्सर निखत जरीन और नीरज गोयत से जुड़े। इस मौके पर फरहान ने अपनी ट्रेनिंग और एक कलाकार और खिलाड़ी के बीच का फर्क बताते हुए कहा कि खिलाड़ी कई चीजों से गुजरते हैं। सिर्फ खेल ही नहीं, उनकी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी भी होती है, उसमें कई उतार-चढ़ाव होते हैं। मुझे बॉक्सर बनने में मजा इसलिए आया, क्योंकि मुझे यह पता था कि यह सारी मेहनत जो मैं कर रहा हूं, वह कम वक्त के लिए है, कुछ महीने या साल भर में यह खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने इस किरदार को करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। जबकि एक खिलाड़ी सालों साल तक अपनी ताकत झोंक देता है। एथलीट उसेन बोल्ट, टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने इतने सारे गोल्ड मेडल जीते हैं, इतनी उपलबधियां पाई हैं, लेकिन उनमें एक भूख होती है कि और बेहतर खेले और मेडल जीते, मुझे कई बार समझ में नहीं आता है कि उनमें यह भूख कहां से आती है। इस फिल्म की ट्रेनिंग के दौरान समझा कि एक बॉक्सर की जिदंगी कैसी होती है। उनका वर्कआउट, खाना-पीना समय सब वक्त में बंधा होता है। वह एक जीवनशैली होती है, जिसे आपको अपनाना होता है। कुछ बनने के लिए उससे जुड़ी जिदंगी को अपना बना लेना होता है, वह यह फिल्म सिखा गई है। क्लासिक फिल्मों में बॉक्सिंग पर बनी हॉलीवुड फिल्म रॉकी मेरी पसंदीदा रही है।



16 को अमेजन प्राइम पर आएगी तूफान • इंस्टाग्राम

करण जौहर ने रणवीर को दिया बर्थडे गिफ्ट



गली ब्वॉय के बाद इस फिल्म में दूसरी बार बनेगी आलिया और रणवीर की जोड़ी • इंस्टाग्राम

बाजीराव मस्तानी, गुंडे और पद्मावत जैसी फिल्मों के अभिनेता रणवीर सिंह मंगलवार को 36 वर्ष के हो गए। उनके जन्मदिन पर तोहफे के तौर पर फिल्मकार करण जौहर ने उनकी अगली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का एलान किया है। खास बात यह है कि इसके साथ करण साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म ये दिल है मुश्किल के करीब पांच साल बाद दोबारा निर्देशन में वापसी करेंगे। फिल्म में रणवीर और आलिया के साथ धर्मेंद्र, जया बच्चन और शबाना आजमी भी अहम भूमिकाओं में होंगे। फिल्म से जया बतौर अभिनेत्री करीब आठ साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करेंगी। करण ने ट्विटर पर लिखा, अपने पसंदीदा लोगों को कैमरे के सामने रखकर, कैमरे के पीछे काम करने को लेकर बहुत उत्साहित हूं। प्रस्तुत है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। यह अनोखी कहानी साल 2022 में स्क्रीन पर आएगी। फिल्म के बारे में करण ने लिखा, यह लव स्टोरी है, लेकिन पारंपरिक लव स्टोरी नहीं। रॉकी और रानी अपने इस सफर में लव स्टोरी को एक अलग तरीके से परिभाषित करने जा रहे हैं।

किरदार के नाम से बुलाया जाना अच्छा लगता है : संजना

करियर के शुरुआती दौर में ही पहचान मिल जाना हर कलाकार के लिए संभव नहीं होता। अभिनेत्री संजना सांघी इस मामले में लकी रही हैं। फिल्म रॉकस्टार में एक छोटे से किरदार से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली संजना की पहली फिल्म बतौर हीरोइन दिल बेचारा थी। फिलहाल संजना अपनी दूसरी फिल्म ओम-द बैटल विदइन पर काम कर रही हैं। संजना ने एक लाइव चैट के दौरान बताया कि आज भी उन्हें लोग दिल बेचारा के किरदार किजी के नाम से बुलाते हैं। यह बात उन्हें अच्छी लगती है। संजना कहती हैं कि मैं जब थिएटर किया करती थी तो यही चाहती थी कि जो किरदार मैं स्टेज पर निभा रही हूं, दर्शक उसे नाटक खत्म होने के बाद भी याद रखें। दिल बेचारा फिल्म की रिलीज के बाद जब लोग मुझे किजी के नाम से बुलाने लगे तो मैं बेहद खुश हुई। किरदार के नाम से बुलाया जाना अच्छा लगता है। मेरा सफर रॉकस्टार के साथ शुरू हुआ था। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी एक्ट्रेस बनूंगी। मैं दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में पढ़ती थी। वहां अपनी कथक परफार्मेंस के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा रॉकस्टार की कास्टिंग के लिए दिल्ली आए थे। वह कश्मीरी जैसी दिखने वाली लड़की की तलाश में थे। उन्होंने मुझे देखा और ऑडिशन करने के लिए कहा। मुझे रॉकस्टार के लिए चुन लिया गया। स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई के साथ मैं थिएटर और फिल्मों के लिए ऑडिशन्स करती रहती थी। यही सपना था कि मेरे किरदार याद रखे जाएं, आज वह हो रहा है।



रॉकस्टार फिल्म से संजना ने शुरू किया था अभिनय का सफर। सौ. टीम संजना

फिलहाल आदिपुरुष की शूटिंग में जुटी हैं कृति सैनन

काम के लिहाज से अभिनेत्री कृति सैनन के लिए यह दौर भी काफी व्यस्त रहा है। फिलहाल कृति के पास मिमी, बच्चन पांडे, भेड़िया, गणपत, हम दो हमारे दो और आदिपुरुष जैसी फिल्में हैं। जिनमें से मिमी रिलीज के तैयार है और उन्होंने हाल ही में वरुण धवन के साथ फिल्म भेड़िया की शूटिंग खत्म की है। अन्य फिल्मों की शूटिंग पूरी की जानी अभी बाकी है। लिहाजा लॉकडाउन में ढील मिलते ही उन्होंने काम शुरू कर दिया। उनके करीबी बताते हैं कि कृति ने फिल्म भेड़िया के ज्यादातर हिस्सों की शूटिंग अरुणाचल प्रदेश में ही पूरी कर ली थी, बची हुई शूटिंग उन्होंने हाल ही में मुंबई में पूरी की। अब वह प्रभास के साथ फिल्म आदिपुरुष की शूटिंग में व्यस्त हैं। फिल्म में कृति सीता का किरदार निभा रही हैं। आदिपुरुष का शेड्यूल पूरा होने के बाद वह अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग खत्म करेंगी। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सभी निर्माता अपनी अधूरी फिल्मों की शूटिंग जल्द पूरी करना चाहते हैं। इन तीनों फिल्मों की शूटिंग पूरी होने के बाद ही कृति अगले प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगी। कृति की फिल्म मिमी जल्द ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी।



फिल्म आदिपुरुष में सीता का किरदार निभा रही हैं कृति • इंस्टाग्राम